सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

लोक लेखा समिति

का

दिनांक– 05 मार्च 2021 को सदन में उपस्थापित प्रतिवेदन।

नोट :– अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन को देखने के लिए *प्रतिवेदन संख्या* पर क्रमवार क्लिक करें।

क्र0	विभाग का नाम	प्रतिवेदन संख्या
1.	ग्रामीण विकास विभाग	704
2.	ग्रामीण कार्य विभाग	706

प्रकाशन संख्या –715

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या– 704

ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित भारत के
नियंत्रक–महालेखापरीक्षाक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष
2008–09 (सिविल) की कंडिका 2.1.5 पर
लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन ।

(दिनांक – **05 मार्च 2021** को सदन में उपस्थापित)।

विषय–सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	1 अप्रील 2020 से षोडश बिहार विधान सभा की शेष अवधि तक के लिए गठित लोक लेखा समिति ।	क
2.	लोक लेखा समिति (मुख्य) का गठन वर्ष 2018–20 ।	ख
3.	लोक लेखा समिति की उप–समिति (4) का गठन वर्ष 2018–20 ।	ग
4.	सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारीगण ।	घ
5.	प्राक्कथन	च
6.	प्रतिवेदन	1–7
7.	परिशिष्ट	8–78

क

बिहार विधान सभा सचिवालय

1 अप्रील, 2020 से षोडश बिहार विधान सभा की शेष अवधि तक के लिए गठित लोक लेखा समिति ।

सभापति

1. **श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी,** **स०वि०स०,**

सदस्यगण

1. श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०,
2. श्री विजय शंकर दूबे, स०वि०स०,
3. श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव, स०वि०स०,
4. श्री अवधेश कुमार सिंह, स०वि०स०,
5. श्रीमती प्रेमा चौधरी, स०वि०स०,
6. श्री रवीन्द्र सिंह, स०वि०स०,
7. श्री अजीत शर्मा, स०वि०स०,
8. श्री भोला यादव, स०वि०स०,
9. श्री मेवालाल चौधरी, स०वि०स०,
10. श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, स0वि0स0
11. श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0
12. श्री मनीष कुमार, स0वि0स0,

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वर्ष 2018–20 (षोडश बिहार विधान सभा)

सभापति

1.	**श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,**	**स०वि०स०,**

सदस्यगण

1.	श्री ललित कुमार यादव,	स०वि०स०,
2.	श्री विजय शंकर दूबे,	स०वि०स०,
3.	श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव,	स०वि०स०,
4.	श्री अवधेश कुमार सिंह,	स०वि०स०,
5.	श्रीमती प्रेमा चौधरी,	स०वि०स०,
6.	श्री रवीन्द्र सिंह,	स०वि०स०,
7.	श्री अजीत शर्मा,	स०वि०स०,
8.	श्री भोला यादव,	स०वि०स०,
9.	श्री मेवालाल चौधरी,	स०वि०स०,
10.	श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव,	स0वि0स0
11.	श्री विजय कुमार खेमका,	स0वि0स0
12.	श्री मनीष कुमार,	स0वि0स0
13.	श्री मनोज यादव,	स0वि0प0,
14.	डॉ0 रामवचन राय,	स0वि0प0,

लोक लेखा समिति उप समिति (4) का गठन वर्ष 2018–20

सभापति

1. **श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स०,**

संयोजक

2. श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स०,

सदस्यगण

3. श्री अजीत शर्मा, स०वि०स०,
4. श्री रवीन्द्र सिंह, स०वि०स०,

बिहार विधान सभा सचिवालय

1.	श्री बटेश्वर नाथ पाण्डेय	सचिव
2.	श्री भूदेव राय	निदेशक
3.	श्रीमती अनुपमा प्रसाद	अवर–सचिव
4.	श्री उमा शंकर यादव	प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्री राजीव रंजन–2	सहायक
6.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह	सहायक
7.	श्री अरबिन्द कुमार दास	सहायक
8.	सुश्री कंचन कुमारी	सहायक
9.	श्री अमित कुमार झा	सहायक
10.	श्री बिट्टू शर्मा	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय

1.	श्री नीलोत्पल गोस्वामी	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
2.	श्री शिवशंकर	उप महालेखाकार
3.	श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव	वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
4.	श्री संजय कुमार मिश्रा	सहायक ले0प0अ0
5.	श्री आलोक रंजन तिवारी	सहायक ले0प0अ0 (त0)

वित्त विभाग

1.	श्री एस0 सिद्धार्थ	प्रधान सचिव
2.	श्री ओम प्रकाश झा	अपर सचिव

ग्रामीण विकास विभाग

1.	श्री अरविंद कुमार चौधरी	सचिव
2.	श्री बाल मुकुद डी.	विशेष सचिव
3.	श्री संजय कुमार सिंह	संयुक्त सचिव

प्राक्कथन

मैं सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 (सिविल) की कंडिका–2.1.5 पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या–704 प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक–04.06.2020 को मुख्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है ।

उक्त कंडिका जमुई एवं नवादा जिलों से संबंधित है, जिसमें सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना अंतर्गत दैनिक मजदूरों के लिए अनाज वितरण में अनियमितता का मामला है, जो एक गंभीर विषय है । समिति द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए विषय को पुरे राज्य के लिए आच्छादित करते हुए विभाग के साथ राशि की वसूली हेतु लगातार बैठकें की जाती रहीं । इस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में विभाग द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री उदय सिन्हा (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया । विभाग द्वारा आयोग का जांच प्रतिवेदन एवं उसपर विभाग द्वारा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन को दिनांक–20.02.2019 को सदन में उपस्थापित किया गया है ।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय, वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने परिश्रम से समिति को जो सहयोग दिया है, वह सराहनीय है । इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

समिति के माननीय सदस्यगणों ने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग प्रदान किया है, मैं उनका आभारी हूँ, और इस कार्य हेतु मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ ।

पटना :

दिनांक–04 जून, 2020 (ई0)।

अब्दुल बारी सिद्दिकी
सभापति,
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा ।

प्रतिवेदन

सी0ए0जी0 प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 (सिविल) की कंडिका 2.1.5 पृष्ठ संख्या–65 से 67 पर द्रष्टव्य ।

2.1.5 चावल का दुर्विनियोजन

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना अंतर्गत दैनिक मजदूरों के वितरण के लिए 86.53 लाख रुपये मूल्य के चावल का दुर्विनियोजन एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 11.51 करोड़ रुपये मूल्य का चावल का उपयोग नहीं किया गया था।

भारत सरकार ने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (स. ग्रा. रो. यो.) और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना (रा. का. ब. अ. यो.) के अंतर्गत मजदूरों को प्रतिदिन न्यूनतम 5 किलो चावल वितरित करने हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जि. ग्रा. वि. अ.) को चावल प्रदान किया। जि. ग्रा. वि. अ. द्वारा योजना लागू करने वाले अभिकरणों के लिए किए गए आवंटन के अनुसार राज्य खाद्य निगम (रा. खा. नि.), भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) के सबसे नजदीकी डिपो से चावल का उठाव कर उसे जन वितरण प्रणाली (ज. वि. प्र.) के डीलरों को निर्गत करता था। जन वितरण प्रणाली के डीलर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुमति पत्र (परमिट) के अनुसार मजदूरों के बीच वितरण हेतु योजना कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों को चावल निर्गत करते थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (रा. ग्रा. रो. गा. यो.) के लागू (फरवरी 2006) होने के बाद स. ग्रा. रो. यो. और रा. का. व. अ. यो. कार्यक्रम के अंतर्गत अवशेष चावल को जून 2006 तक उपयोग कर लेना था और इन योजनाओं के अंतर्गत प्रारम्भ किए गए कार्यों को अगस्त 2007 तक बन्द कर देना था।

(क) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जमुई के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2008) में उद्घाटित हुआ कि लक्ष्मीपुर प्रखंड के एक ज. वि. प्र. के व्यवसायी ने जनवरी 2002 से जून 2006 के दौरान स. ग्रा. रो. यो और रा. का. के. ब. अ. का. के अंतर्गत 852.22[9] एमटी चावल का उठाव किया। इसमें से डीलर ने अगस्त 2007 के अन्त तक योजना कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों को 196.70[10] एम टी चावल निर्गत कर दिया। शेष 655.52 एम टी चावल उनके भंडार में शेष थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी (प्र. वि. प.), लक्ष्मीपुर ने उप–विकास आयुक्त (उ. वि. आ.) और जिलाधिकारी (डी. एम), जमुई को सूचित किया (अगस्त/सितम्बर 2006) कि परमिटों के निर्गमन के बावजूद डीलर योजना कार्यान्वयन अभिकर्त्ताओं को न तो चावल निर्गत कर रहा है और न ही अपने भंडार के भौतिक सत्यापन में सहयोग कर रहा है। अनुक्रिया में उप विकास आयुक्त ने प्र. वि. पदा. को 655.42 एम टी चावल की वसूली हेतु व्यवसायी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज एवं सर्टिफिकेट केस[11] करने का निदेश दिया (सितम्बर 2006) हालांकि जुलाई 2008 के अन्त तक व्यवसायी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसको इंगित करने पर (जुलाई 2008) प्र. वि. पदा., लक्ष्मीपुर ने व्यवसायी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया (अगस्त 2008) और 41.66 लाख रुपये के

---

9 *रा. का. के. ब. आ. का : 258.16 एम. टी तथा सं. ग्रा. रो. यो : 594.06 एम. टी.।*

10 *रा. का. के. ब. अ. का. : 54 एम टी (जुलाई 2005) तथा सं. ग्रा. रो. यो. : 142.70 एम (फरवरी 2002 से जून 2006)*

11 *सर्टिफिकेट केस : इसे जिला सर्टिफिकेट पदाधिकारी के कोर्ट में सरकारी धन या परिसंपत्ति की वसूली हेतु किया जाता है।*

लिए सर्टिफिकेट केस दायर किया (मई 2009)। मात्र 41.66 लाख रुपये के लिए सर्टिफिकेट केस के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा की पृच्छा पर प्र. वि. पदा. ने आगे सूचित किया (अगस्त 2009) कि गरीबी रेखा के ऊपर (ए. पी. एल.) – दर के चावल के मूल्य के आधार पर सर्टिफिकेट की राशि को पुनरीक्षित कर 83.32 लाख रुपये कर दिया गया था। तथापि अभी तक सर्टिफिकेट केस के फलाफल को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया (अक्टूबर 2009) था।

इस प्रकार ज. वि. प्र. के डीलर द्वारा 86.53 लाख रुपये मूल्य का 655.52[12] एमटी चावल (13200 रुपये प्रति एम टी की दर से) का दुर्विनियोजित कर लिया गया था।

(ख) जि. ग्रा. वि. अ., नवादा के अभिलेखों की संवीक्षा (नवंबर 2008) में उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2003–06 के दौरान स. ग्रा. रो. यो. के अंतर्गत 13973.99 एम टी चावल प्राप्त किया गया था जिसमें से 5609.24 एम टी मात्र का उपयोग किया गया। चार प्रतिशत वैट एवं एक प्रतिशत बाजार शुल्क सहित 13755 रुपये प्रति एम टी की दर से 11.51 करोड़ रुपये मूल्य की 8364.75 एम टी शेष मात्रा नवंबर 2008 तक उपयोग नहीं की जा सकी थी तथा ज. वि. प्र. के डीलरों के पास उपलब्ध थी।

उ. वि. आ., जि. ग्रा. वि. अ., नवादा ने उत्तर दिया (नवम्बर 2008) कि रा. ग्रा. रो. ग. यो. में चावल स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और तदंतर उ. वि. आ. ने सभी प्र. वि. पदा./ जिला परिषदों को चावल की शेष मात्रा को बेचने का अनुदेश दिया एवं बिक्री से प्राप्त आय को जि. ग्रा. वि. अ. में जमा करने का निदेश दिया (जून 2009)। बाद में उ. वि. आ. ने प्र. वि. पदा./जिला परिषदों को गलती करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया (अगस्त 2009)। इसी बीच जिलाधिकारी, नवादा ने एक चार्टर्ड एकाउन्टेंट (चा. ए.) को आवंटन, उठाव, उपयोगिता और चावल के अंतशेष (पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद–वार) के संदर्भ में चावल की स्थिति निर्धारित करने एवं सम्बन्धित व्यवसायी से अनुपयोगित अनाज का मूल्य वसूली करने हेतु नियुक्त किया (जुलाई 2009)। यद्यपि चार्टर्ड एकाउंटेंट का अन्तिम प्रतिवेदन जमा नहीं किया गया था (दिसम्बर 2009) लेकिन उसने 10 ज. वि. प्र. व्यवसायियों से 450.11 एम टी शेष चावल के लिए 61.91 लाख रुपये की वसूली हेतु सिफारिश किया (अक्टूबर 2009)।

इस प्रकार समय सीमा (जून 2006) के भीतर और कार्य बन्द करने के पूर्व (अगस्त 2007) स. ग्रा. रो. यो. के शेष चावल स्थानान्तरित नहीं किए जाने के कारण अनुपयोगित पड़े रहे।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया था (अप्रैल और जून 2009)। तत्पश्चात् स्मारित किया गया (अगस्त 2009), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2009)।

---

[12] *रा. का. के. ब. अ. का. : 204.16 एम टी तथा सं. ग्रा. रो. यो. : 451.36 एम टी*

विभागीय स्पष्टीकरण

सी0ए0जी0 प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 (सिविल) का दिनांक–23.07.2010 को सदन में उपस्थापन किया गया है ।

दिनांक–28.01.2011 को उक्त कंडिका पर प्रथम बैठक हुई। बैठक में विभागीय संयुक्त सचिव, द्वारा बताया गया कि जिलों से प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है । प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा बताया गया कि कंडिका राज्य के दो जिलों (नवादा, जमुई) से संबंधित है । समिति द्वारा सारे तथ्यों पर विचार करते हुए विभाग को शीघ्र उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

दिनांक–15.02.2011 की बैठक में विभाग के पत्रांक–1448 दिनांक–14.02.2011 द्वारा प्राप्त उत्तर में नवादा से संबंधित कुछ राशि वसूल होने, अनेकों डीलरों द्वारा वसूली के कार्रवाई के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किये जाने की सूचना दी गई ।

जमुई से संबंधित प्रतिवेदन में विभाग द्वारा यह बताया गया कि **''विलंब से कार्रवाई के लिए दोषी प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र–क गठन करेन की कार्रवाई एवं डीलर के विरूद्ध सर्टिफिकेट केस की अद्यतन स्थिति उप विकास आयुक्त जमुई से मांग की गई है तथा गिरफ्तारी हेतु आरक्षी अधीक्षक जमुई से अनुरोध किया गया है ।**

विभाग द्वारा प्राप्त उत्तर पर समिति द्वारा यह निदेश दिया गया कि **''किस दर से रिकवरी हुई है और कितनी हुई है, उनके पास कितना अनाज रहा, जिस उद्देश्य के लिए अनाज गया उसकी पूर्ति हुई की नहीं दूसरी बात है कि कितने साल तक अनाज रह गया तथा बिहार के अन्य जिलों की क्या स्थिति है, सभी जिलों से रिकवरी किस दर से की जा रही है इसकी अद्यतन स्थिति से समिति को अवगत कराया जाय ।''**

इस बीच समिति द्वारा उक्त कंडिका पर विभाग के साथ आठ बैठकें की गई, परंतु उचित फलाफल नहीं आने पर समिति द्वारा **दिनांक–26.06.2012** को मुख्य सचिव, एवं डी0जी0 बिहार के साथ बैठक का निर्धारण किया गया। मुख्य सचिव, मुख्यालय से बाहर रहने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। समिति द्वारा विभाग से यह अपेक्षा की

गई कि पूरे बिहार राज्य में कितनी राशि वसूलनीय है और विभाग द्वारा कितनी राशि वसूल की गयी है । पृच्छा के आलोक में विभागीय विशेष सचिव, द्वारा बताया गया कि **''320 करोड़ की वसूलनीय राशि है उसके विरूद्ध 18 करोड़ की वसूली हुई है ।''** चर्चा के दौरान पुलिस महानिदेशक बिहार, द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विभाग सारे केस को क्लब करके किसी एक कोर्ट में पेटिशन फाईल करे और इस पर जैसा कोर्ट का डिसीजन आये उसके अनुसार विभाग कार्य करें । समिति द्वारा इस सुझाव के आलोक में यह निदेश दिया गया कि डी0जी0पी0 के तरफ से सभी जिले के एस0पी0 को यह निदेश दिया जाय कि राशि वसूली में विभाग को सहयोग करें तथा जिलें में डी0एम0, एस0पी0 और डी0डी0सी0 की एक कमिटी बनाकर बराबर बैठक कर राशि वसूली में तेजी लाए ।

दिनांक–26.06.2012 की बैठक के आलोक में दिनांक–25.07.2012 को प्रधान सचिव, वित्त विभाग के कार्यालय कक्ष में ग्रामीण विकास विभाग के साथ बैठक संपन्न हुई । उक्त बैठक में राशि वसूली में प्रगति लाने हेतु साथ ही वैसे जनवितरण प्रणाली के दुकानदार जिनके यहां राशि बकाया है उनके अनुज्ञप्ति निलंबन/रद्द करने तथा बकाया राशि की वसूली की दिशा में कारगर कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग के साथ बैठक का आयोजन करने का निदेश दिया गया ।

दिनांक–10.09.2013 की बैठक में विभागीय सचिव, द्वारा बताया गया कि समिति के डायरेक्शन के आलोक में फुडग्रेन डीलर के पास शेष रह गयी राशि की वसूली की जा रही हैं । परंतु इसमें 300 डीलर कोर्ट में चले गये है । कोर्ट ने सारे मामले को क्लब करते हुए आदेश दिया है कि इस मामले में जो डीलर के पास अनाज था, उसको यूज करना संबंधित अधिकारियों की भी जिम्मेवारी थी, अतएव जितना डीलर जिम्मेवार हैं उतने अधिकारी भी जिम्मेवार है इसलिए राज्य सरकार विचार करें कि कितने रेट पर वसूली करनी है । और इसके आलोक में चीफ सेक्रेटरी, की अध्यक्षता में कमिटी बनी । जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उस समय 13 रूपया 70 पैसा अनाज का रेट था । इस मामले को लोक लेखा समिति, देख रही है इसलिए राज्य सरकार इसमें निर्णय नहीं ले सकती है । लोक लेखा समिति के डायरेक्शन के आलोक में 13 रूपये 70 पैसे के हिसाब से वसूली किया जाता है । हाइकोर्ट द्वारा कहा गया कि लोक लेखा समिति के सामने यह मामला है अतएव पहले इस मामले को पी0ए0सी0 के सामने रखा जाय उसके बाद हाइकोर्ट द्वारा डायरेक्शन दिया जाएगा ।

संबंधित विषय पर समिति द्वारा विभाग के साथ लगातार बैठकें होती रहीं ।

दिनांक–03.12.2014 की बैठक में विभागीय विशेष सचिव, द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पी0डी0एस0 डीलरों से अवशेष बचे खाद्यान की वसूली हेतु दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश पारित किया गया है । साथ ही CWJC NO-19529/11 श्री सदानन्द यादव तथा 106 अन्य संलग्न समादेश याचिकाओं की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लगातार की जा रहीं है । सुनवाई के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न दिशा–निर्देश दिये गये है :–

1. सभी जिलों में अवशेष बचे खाद्यान की मांग एवं संबंधित डीलर की सूची प्राप्त की जाय ।

2. अवशेष बचे खाद्यान के रख–रखाव में हुई त्रुटि के कारण क्षति के लिए जिम्मेवार जिला से लेकर पंचायत तक के सरकारी कर्मियों की सूची उपलब्ध कराई जाय ।

3. सरकार को जनवितरण प्रणाली डीलर एवं संबंधित सरकारी सेवकों के दायित्व के निर्धारण हेतु एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण के गठन पर सहमति की मांग की गई ।

4. सी0ए0जी0 की कंडिकाओं में नमूने के जिले में अंकेक्षण के आधार पर खाद्यान के अवशेष रहने का उल्लेख किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा संबंधित खाद्यान हेतु सभी जिलों से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में सभी जिलों से प्रतिवेदन मांगा गया है, अभीतक 32 जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। सभी जिलों से प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् खाद्यान के वास्तविक क्षति का आकलन किया जा सकेगा ।

सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय समिति द्वारा यह निदेश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत विभाग कार्रवाई करके समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराये ।

दिनांक–01.09.2016 की बैठक में विभागीय सचिव, द्वारा यह बताया गया कि ''माननीय न्यायमूर्ति श्री उदय सिन्हा (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है आयोग के प्रतिवेदन आने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।''

दिनांक–23.06.2017 की बैठक में विभाग द्वारा यह उत्तर दिया गया कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के बंद होने के उपरांत अवशेष खाद्यान की क्षति एवं उसके समतुल्य राशि की वसूली के दायित्व के निर्धारण के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC NO-19529/11 श्री सदानन्द यादव बनाम राज्य सरकार तथा अन्य बैच वादों में **दिनांक–21.09.2015** को पारित आदेश में न्यायिक आयोग के गठन का निर्देश दिया गया है । उक्त आदेश के अनुपालन में अधिसूचना क्रमांक–258459, **दिनांक–18.01.2016** के द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री उदय सिन्हा (सेवानिवृत) के अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गयाा है, जैसा कि **दिनांक–01.09.2016** की बैठक में विभागीय सचिव द्वारा बताया गया था । आयोग के प्रतिवेदन आने उपरांत इस पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

समिति द्वारा न्यायिक आयोग का प्रतिवेदन आने के उपरांत निर्णय लेने का फैसला किया गया ।

दिनांक–03.10.2019 की बैठक में विभाग द्वारा पत्रांक–62/C दिनांक–03.10.2019 से अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया कि **''आयोग द्वारा जांच प्रतिवेदन सरकार को समर्पित कर दिया गया है एवं जांच प्रतिवेदन के आलोक में विभाग द्वारा निम्नांकित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है ''** :–

1. अपने जिले में SGRY योजना के गठन किये गये चावल की मात्रा के समतुल्य राशि की वसूली रूपये 1370/– प्रति क्विंटल की दर से डीलर से करना सूनिश्चित करेंगे राशि की वसूली में रूपये 13/– प्रति क्विंटल की दर से परिचालन एवं हथालन हेतु राशि का समयोजन सुनिश्चित करेंगे ।

2. आयोग के सुझाव के आलोक में निलाम पत्र पदाधिकारियों को कर्णांकित कर प्रति माह वसूली की प्रक्रिया एवं वसूली की समीक्षा कर तत्संबंधी प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराया जाय ।

न्यायिक जांच आयोग का जांच प्रतिवेदन (परिशिष्ट पृष्ठ संख्या–8 पर द्रष्टव्य) तथा जांच प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (परिशिष्ट पृष्ठ संख्या–67 पर द्रष्टव्य) दिनांक–20.02.2019 को विभागीय मंत्री द्वारा सदन में उपस्थापित किया गया है । (सदन की बैठक से संबंधित विवरणिका परिशिष्ट पृष्ठ संख्या–72 पर द्रष्टव्य) ।

दिनांक–20.02.2020 की बैठक में विभाग से पत्रांक–457745, दिनांक–19.02.2020 (परिशिष्ट पृ0स0–73 पर द्रष्टव्य), द्वारा प्राप्त उत्तर में यह उल्लेख किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशोपरांत गठित न्यायिक आयोग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में विभाग द्वारा राशि वसूली एवं दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई की जा रही है ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक–20.02.2020 को उप समिति–4 की विभाग के साथ संपन्न बैठक में उक्त कंडिका पर यह निदेश दिया गया कि **''माननीय उच्च न्यायालय के आदेशोपरांत गठित न्यायिक आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में विभाग द्वारा जो सारे जिलों को निर्देश दिया गया है, उस पर जिले द्वारा क्या कार्रवाई की गई, उक्त कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाय ।''**

अब समिति इस अनुशंसा पर कार्यान्वयन उप समिति में विचार करेगी ।

सभापति,

पटना

दिनांकः–04.06.2020

(अब्दुल बारी सिद्दिकी)
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट

(8)

GOVERNMENT OF BIHAR

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

FINAL REPORT

Justice Uday Sinha Judicial Inquiry Commission

For

Fixing the responsibility for the loss of residual grain after the closing of SGRY & NFFW Scheme

⑨

FINAL REPORT

1- In 2001 on the 15th August, Hon'ble Prime Minister of India announced launching of a scheme with an outlay of Rs 10,000/- crores for providing additional wage employment, infrastructural development and food security in the rural areas. In this regard the Ministry of Rural Development, after review of on-going schemes of the Employment Assurance Scheme (EAS), launched Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY) after merging Jawahar Samridhi Rozgar Yojana with a new scheme with effect from September, 2001.

2- The objective of the scheme was to provide additional wage employment to the rural poor and thus provide food security with improved nutritional levels. It was a Centrally sponsored scheme on cost sharing basis between the Centre and the States in the ratio of 75:25 of the cash component of the programme. The food grains were to be provided to the States free of cost. The Central Government was to provide entire 100% rice under the scheme. It was to be open to all rural poor who were in need of wage employment and were willing to do manual and skilled works in and around their village. The programme was to be instituted through Panchayati Raj institutions. In concise terms the scheme was to pay to rural poor who were willing to work. 75% of the man day labour was to be paid in kind and 25% was to be paid in cash. This process would result in employment with respectability to the rural poor as well as bring about development in the rural areas by construction of roads, water tanks etc. Food grain was to be given as part of wages under the SGRY to the rural poor at the rate of 5 kg per man day. The State Governments were free to calculate the cost of food grains paid as part of wages at a uniform rate .which could be either BPL rate or APL rate or anywhere between the two rates. The scheme further spelt out that the distribution of food grains to the workers under the programme would be either through PDS (Public Distribution System) or by Gram Panchayat or any other agency appointed by the State Government. District Rural Development Agency (DRDA)/Zila

(10)

Parishads (ZP) were to make necessary arrangement for distribution of food grains to the concerned agency. In the State of Bihar, the programme was implemented by Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads. The work of Gram Panchayats and Panchayat Samitis were placed under the charge of the BDOs (Block Development Officer). The other stream through Zila Parishads was placed under the charge of the District Engineer and similar level officers. In overall terms, the DDC (Deputy Development Commissioner) was incharge of implementation of the SGRY scheme in each district.

3- The rice required for payment/supply was to be supplied to the State of Bihar by the Food Corporation of India (FCI). The FCI was to supply rice at economic cost. The FCI had declared the rate at which it supplied the rice to the State of Bihar as Rs 1370/- per quintal. The State Food Corporation godowns in various districts were to lift rice from the nearest FCI godowns.

4- 40% of the funds and food grains earmarked under the first stream was to be reserved at the district level and was to be utilized by the Zila Parishads and DRDAs. 60% of the funds and food grains earmarked under the first stream would be allocated among the Panchayat Samitis (Intermediate Panchayats). Rice was to be released to public distribution dealers/ Zila Parishads etc **on the basis of prepared estimates of works and requirement of rice.**

5- Thus, the SGRY scheme took off in March, 2002. Later, after four years, the Government decided to close down the SGRY scheme and introduced a fresh scheme known as NREGA (National Employment Rural Guarantee Programme). On 9th January, 2006, the Government of India in the Rural Development Department under the signature of Mrs Anita Sharma, Joint Secretary wrote to the Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar that the SGRY and NFFWP will be closed at the end of the financial year i.e. March, 2006.

6- It would be useful to mention here the difference between SGRY and NREGA. Under SGRY, workers were to be given 75% wages in kind

and 25% in cash per man day. Under the NREGA only cash was to be given. It was written in paragraph-3 of the letter sent by the Secretary, Ministry of Rural Development to the Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar that incomplete works under the SGRY/NFFWP would be allowed to be completed upto 30th June, 2006 out of the balance funds available with the districts. At paragraph-4 it was laid down that under NREGA only cash would be given. As such, no food grain would be provided. Lifting of food grains authorized during the current year under the SGRY and NFFWP would not be allowed in the subsequent year. The change from partial grain and cash to entire cash payment was effected to prevent any possible challenge to the quantum of wages paid to the workers.. The letter of the Government of India is marked as **Annexure-1**. The noting on this letter shows that the letter was sent to all Deputy Development Commissioners (DDCs) for necessary action. The closure of the scheme in March, 2006, except in 15 districts where it was extended till June, 2007, was notified to all officers and dealers. There is no controversy about it.

7- After issuing the direction for closure of the scheme, it appears that the Government went off to sleep. Rice had been issued to several PDS dealers all over the State. They could not be utilized fully for the purpose they had been issued. They were not utilized either on account of non-issue of permits by executing agencies i.e. BDOs, Mukhiyas, Panchayat Samitis, District Engineer in the Zila Parishad, or for want of cash component to be paid along with the rice or for want of schemes. Government of India realized that some works which had been taken up in February or March, 2006 may have been executed only partly and therefore, in March, 2007 the Joint Secretary, Government of India vide letter dated 23rd March, 2007 reiterated that prior to implementation of NREGA, no new SGRY scheme should be taken up in districts mentioned in the letter and therefore, no allocation under the SGRY would be made to those districts in 2007-2008, All out efforts was required to be made by implementing agencies at different levels of the districts to ensure that all works under SGRY were to be completed by 31st March, 2007.

(13) (12)

Such works which could not be completed due to unavoidable circumstances by 31st March, 2007 had to be completed at the earliest with balance of funds under the SGRY in each district as on 1st April, 2007. The details of works which could not be completed by 31st March, 2007 was to be compiled and that also in 15 districts only to be submitted to the Government of India. **This compilation was never done.** As a follow up action, Mr Anup Mukherjee, the then Principal Secretary, Rural Development Department, Government of Bihar issued instructions vide letter no.7619 dated 13/08/2007 to concerned DDCs. It was regretted that no report could be sent to the Government of India in regard to incomplete projects.

8- It appears that Mr Anup Mukherjee woke up to the situation that previous instruction in regard to implementation of the NREGA had not been carried out and grains were left with the PDS dealers. On 21st August, 2008 he held a review meeting of DDCs of the State. The minutes of that review meeting is annexed herewith and marked as **Annexure-2.**

9- It was a review meeting in regard to several rural welfare schemes. The implementation of NREGA, post SGRY, was also one of the subjects of discussion. At paragraph-9 of the proceedings, it was recorded that whatever food grain issued earlier, was available, should be utilized under the NREGA scheme. It is significant that it was decided that whatever grains **which had not been consumed**, the price thereof should be realized from the dealers at the APL rate (Rs10/- per kg). The said sum was to be deposited under NREGA head. I wish to observe that Mr Mukherjee should have given better thought about the rate of realization of residual rice. Mr Hasnain, DDC, Samastipur took some steps for realization of the residual rice on his own in 2007 itself. Another DDC, Munger Mr Arvind Kumar Singh who took charge from Mr Upendra Kumar, took appropriate expeditious steps for realization of the price of the residual rice.

10- Paragraph-9 brings out in clear profile that Mr Anup Mukherjee was aware of the fact that grains issued under SGRY had not been fully consumed and were lying with the PDS dealers. Photocopy of the

proceedings of the review meeting has been supplied to this Commission. There is a noting on the proceeding at the top "e-mail 10/09/08". The copy further shows that on 15/09/2008 by Memo No.1123 copies of the memorandum of the review meeting were sent to all Programme Officers of the district for information and necessary action. The document also shows that the copy thereof had been sent to Deputy Development Commissioner-cum-District Programme Coordinator, Zila Parishad, Vaishali.

11- The State could not furnish the names of the DDCs who had attended the review meeting.

12- The proceeding of the review meeting shows three things. Firstly, that till that date no step had been taken in order to solve the problem of disposal/sale of residual rice and secondly, all the DDCs knew that there was grain available with the PDS dealers and thirdly, none of them took any step to report in writing to the Collector, Commissioner or State Government about the rice lying with the PDS dealers. It further shows that no SDO or DM or Commissioner took any interest in the implementation/working of the SGRY scheme. If they had taken interest in the scheme, as was enjoined upon them by government order, they would have known that grains were in deposit with grain dealers which problem had to be tackled. They all stated that there was no instruction in this regard. In my view, they were required to inquire from the subordinate officers and to seek instruction from superior officers: SDO to Collector, Collector to Commissioner and Commissioner to the State Government. None of them sent any report nor did any of them seek any instruction.

13- Things started moving when Office of the Accountant General, Bihar reported to the State Government about mismanagement of the scheme at Laxmipur block in the district of Jamui and Nawada district. The Accountant General did not specify the amount of loss to the State. The report was placed before the Public Accounts Committee of the Bihar Legislative Assembly. That Committee – Public Accounts Committee was of the view that the State had suffered loss of about Rs 321 crores due to negligence of Officers.

The State was directed to take steps for realization of price of the residual rice so that the loss to the State exchequer may be recouped. Then the wheel of the Government started moving. Mr Mathew, Principal Secretary, Rural Development Deptt issued orders dated 30/06/2011 to the District Magistrates to take steps to realize the value of the residual rice @ Rs 1370/- per quintal. As a sequel to it, notices were issued calling the dealers to deposit the value of the rice @ Rs 1370/- per quintal. That brought about a flood of writ applications before the High Court challenging the demand of the price as well as the rate of realization of the price of the residual rice. Their stand in the writ applications was that the rice had deteriorated and become useless and therefore, they had destroyed them. Their stand further was that they were under no obligation to preserve the rice and therefore, they were not liable to pay for the deteriorated rice.

14- Things would have remained dormant if the Accountant General's Office had not sent a report to the State of Bihar in regard to improper utilization of rice. The Accountant General reported in 2009 that Rs 86.53 lakhs worth grains meant for distribution to daily wage workers had been misutilised and Rs 11.51 crores worth of rice had not been utilized. It was stated in the report that while auditing the books of a dealer in Laxmipur block in the district of Jamui, it was found that he had lifted 852.22 quintals of rice. Till August, 2007 the dealer had utilized/distributed 196.70 quintals of rice leaving a balance of 655.52 quintals in the store. BDO, Laxmipur had informed the DDC and the District Magistrate, Jamui that the dealer was neither issuing rice despite issue of permits nor was he cooperating in physical verification of the rice. Similar report was made in regard to dealers in the district of Nawadah. At Nawadah the audit showed that 30,973 quintals of rice had been lifted. 5,609.24 quintals of rice had been utilized, 8,354.75 quintals had not been utilized. Thus, 11.51 crore rupees worth of rice had not been accounted for. This state of affairs shows that something foul was going on in the districts and the Collectors were unware of the situation and were not alert at all.

15- This action of the Government for realization of price of the residual rice brought about a flood of writ applications in the High Court. The

(14) (15)

first writ application was filed by Raiful Azam & two Ors in CWJC No.5638/2011. Another writ application was filed by Sadanand Yadav in CWJC No.19529/2011. In all 141 writ applications involving more than 216 PDS dealers were filed challenging the demand made from them by the authorities.

16- In course of hearing, it was stated on behalf of the State of Bihar that the State had suffered huge loss. Sometimes it was said that the loss was to the tune of Rs 334 crores and sometimes the figure was given as Rs 321 crore and lastly learned Principal Additional Advocate General said that it was to the tune of Rs 215.89 crores.The writ applications were heard by Hon'ble Mihir Kumar Jha J. His Lordship found that the dealers had behaved in dubious ways and officers also had done no better. His Lordship was of the view that the whole truth covering the whole State would not come out by deciding the limited writ applications one by one. His Lordship's view was that the situation required a deep probe into the functioning of the SGRY and the attitude of dealers and officers. His Lordship's view was that not only the dealers but the delinquent parties, the officers from Commissioners down to SDOs, BDOs, Panchayat Secretaries, District Engineers had also something to account for. His Lordship therefore ordered for a judicial inquiry. His Lordship observed that several aspects of the matter had not been gone into while disposing of several other writ applications (as in the case of Yamuna Nayak) as all aspects had not been taken note of. His Lordship observed:-

> **Para-79:**"This Court, however, would immediately clarify that the individual facts of the case of Yamuna Nayak (supra) or the pleadings made therein cannot cover the case of all 4985 PDS dealers, inasmuch as, from the facts noted to these five cases alone, it would become clear that the allotment order of rice to the PDS dealers had contained certain terms and conditions including the provision for payment of transportation/handling/storage expenses. Yet again, from the facts of these five cases alone, it would also transpire that the petitioners when asked to make payment of the balance amount of rice left with them had also made certain payment. All these aspects noted herein were not noticed in the case of Yamuna Nayak (supra) and, therefore, this Court would not

exonerate the petitioners and/or PDS dealers but then there is also individual defence different from the case to case which has to be taken into account while fixing the individual liability for payment of balance amount of price of rice for which they have been subjected to either demand notice or certificate proceedings. This job of factual analysis of each of the PDS dealers including the petitioners cannot be done by this Court in exercise of power under Article-226 of the Constitution of India and, hence, the necessity of an independent Enquiry Commission specially when the Government before this Court had repeatedly tried to give a clean chit to the Divisional Commissioners, Collectors and Sub Divisional Officers."

Page-80:"All these aspects therefore will require some fact finding by way of leading of evidence. The deck for such enquiry now has been cleared in the form of availability of the name of PDS dealers with quantity of rice allotted to them and the amount which is said to be realized from them on account of their remaining undistributed in the stock and ultimately making them liable either by way of demand notice or certificate proceeding."

Para-81: "As noted above, more than 689 criminal cases have also been filed apart from institution of 4985 number of certificate proceedings which have caused havoc with the PDS dealers including the petitioners who have either voluntarily or under coercion have deposited the amount as also amount as shown in the pleading portion of these writ applications."

17- In the above situation, His Lordship held that a high level inquiry commission headed by a retired Hon'ble High Court Judge as agreed by all the parties was found to be absolutely necessary to go into all relevant aspects arising in respect of recovery of loss of Government money in SGRY as found in the report of the CAG. For going into the root of the matter, His Lordship directed constitution of a 3-Man Inquiry Commission headed by Hon'ble Justice Uday Sinha (myself), a retired Judge of the Patna High Court who would be **assisted by two Members namely; Mr Sanjay Kumar Singh, a retired IAS Officer and Mr Arun Kumar Singh, a retired Officer of IA&AS.**

(17)

18- Hon'ble Mr Justice Jha set down the matters to be inquired into in para-89 which the inquiry commission had to look into. The Commission "for this purpose shall go into the following aspects :-

(i) The quantum of the actual loss sustained by the Government.

(ii) The terms and conditions of allotment of rice to PDS dealers under SGRY for its distribution to the beneficiaries.

(iii) The manner of allotment of rice to the PDS dealers.

(iv) The payment of transportation/handling/storage charges to the PDS dealers

(v) Price of rice on which recovery had to be made.

(vi) Whether 5994 PDS dealers (probably mistake for 4985 PDS dealers as mentioned in paragraph-79 of the High Court order) alone will be responsible for recovery of the aforesaid loss or even the Officials entrusted with the task of regulating and monitoring the scheme including 48 Divisional Commissioners, 204 Collectors, 202 Deputy Development Commissioners, 412 Sub Divisional Officers apart from 2640 Block Development Officers as well as concerned person of Zila Parishad/Panchayat Samiti/Gram Panchayat including Panchayat Secretary and Mukhiya.

(vii) The Inquiry Commission in fact will also have to fix the quantum of recovery from the PDS dealers and/or officials so that not only 5994 PDS dealers being subjected to atleast 689 criminal cases and 4985 certificate proceeding alone are not made liable in isolation unless the Inquiry Commission comes to the conclusion that they discharged their duties religiously in the matter of monitoring and supervising SGRY scheme all over the State.

(viii) The Inquiry Commission may also go into any other related aspect for ensuring recovery of the total loss of revenue caused to the State exchequer in the execution and implementation of the SGRY scheme all over Bihar in the period 2002-2006; and

(ix) The Inquiry Commission will also be free to make any interim as also final recommendation for recovery of entire loss to the Government under the SGRY scheme.

(19)

19- In compliance of the order of the High Court dated 21st October, 2015, the State Government issued a notification dated 18th January, 2016 creating this Commission which read as follows :-

> **S.O.14 dated 18th January, 2016** – In compliance of the order passed by the Honourable High Court in the CWJC No.19529/2011-Sadanand Yadav & Others Versus State of Bihar & Others and other batch cases, Government of Bihar has decided to appoint a Judicial Commission of Enquiry for fixing the responsibility for the loss of residual food grain after the closing of Sampurna Gramin Rojgar Yojana and National Food for Work Scheme between 2002 to 2006, in exercise of powers conferred under Section 3(1) of the Commission of the Enquiry Act, 1952 (No.60 of 1952).
>
> Now, therefore, the Governor of Bihar is pleased to constitute a three member Commission of Inquiry under the Chairmanship of Honourable Justice Mr Uday Sinha, Retired Judge of Patna High Court, Mr Sanjay Singh (later amended as Mr Sanjay Kumar Singh), Retired IAS and Mr Arun Kumar Singh, Retired Indian Audit and Accounts Service will be members of the Commission. Mr Shashi Bhushan Verma, retired Joint Secretary is nominated as Secretary to Commission of Enquiry.
>
> 2. The Commission will have the following terms of reference :
>
> a. to determine the responsibility for the lapses for the loss of food grain and for realization of equivalent amount of the same after the closure of Sampurna Gramin Rojgar Yojana and National Food for Work Schemes. ·
>
> 3. The Governor of Bihar is further pleased to exercise powers conferred by sub section (1) of Section 5 of the said Act to direct that all the provisions of sub section (2)(3)(4) & (5) of the said section shall apply to this Commission.
>
> 4. The Commission shall submit its report within six months from the date of this notification.
>
> By order of the Governor of Bihar,
> Sd/- Pramod Kumar Bihari,
> Special Secretary to Government".

20- Those were the parameters of the Judicial Inquiry Commission. The Chairman and Members assumed charge on the 19th January, 2016. The functioning of the Commission was delayed for want of proper

accommodation and infrastructure. These were provided in April, 2016. The Commission commenced its deliberations thereafter. Dealers in Vaishali were noticed by publication in newspaper. Individual summons were also issued to them. Progressively cases of some other districts were also taken up.

21- The foremost duty of the Commission was to assess the quantum of actual loss sustained by the Government. This was not possible in the absence of audited report in regard to residual rice from different districts. The Commission therefore, took up the cases of individual dealer in the districts mentioned above. The assessment of the loss entailed collection of figures of rice lifted by the dealers till March, 2006 or afterwards. For this purpose all Collectors were instructed to send statement of grains lifted and distributed by the dealers. Statements were received in a tardy manner from some districts but they were not received even till June, 2016. From Katihar audited statement was received in November, 2017. Some District Magistrates did not consider it their duty to furnish the appropriate figures to the Commission. The Commission therefore, proceeded with the figures made available to the Commission.

22- On 30th June, 2017 Mr Sanjay Kumar Singh and Mr Arun Kumar Singh, the two Members relinquished office.

23- The fact of relinquishment of office by two Members namely; Mr Sanjay Kumar Singh and Mr Arun Kumar Singh was brought to the notice of the Chief Justice, Patna High Court by the Chairman. Hon'ble Chief Justice treated the letter of the Chairman as interlocutory application. After hearing the parties, His Lordship passed order that in the changed circumstances, the State Government was of the view that a single member Commission be appointed for smooth functioning and to proceed with the work which was entrusted to the Commission. His Lordship also modified the scope of inquiry by the Commission so as to confine the adjudication disputes raised by writ petitioners who had filed the writ petitions in the High Court and not all PDS dealers in the State of Bihar.

(20)

24- In the changed circumstances, the wings of the Commission were considerably clipped and instead of assessing the total actual loss to the State, the inquiry remained only an inquiry into the grievances of the dealers who had moved the High Court and filed writ petitions. Thus the judicial inquiry was substantively aborted. A copy of the order dated 02/08/2017 passed by Hon'ble Chief Justice, Rajendra Menon in I.A. No.5268/2017 is annexed as **Annexure- 3.**

25- The direction of the High Court was, that the "Commission shall cause an inquiry only with regard to grievances of such of the persons who had filed writ applications in the High Court pertaining to the order passed on 21/09/2015 in CWJC No.19529/2011 and analogous cases. Such inquiry shall be confined to the adjudication of the dispute raised by the writ petitioners who had filed writ petitions before this Court and further, the persons or PDS dealers who were not parties in the writ petitions or who had not ventilated their grievances in the writ petition or before the High Court shall not be permitted to take up the issue before the Commission. The Commission was further enjoined to ensure that the conditions stipulated in the original order passed on 21/09/2015 with regard to deposit of 50% of the original demand for the purpose of preventing coercive action shall continue to remain in operation."

26- The Commission, after issuing notices to the dealers who had filed writ applications, passed final order on their grievances. The Commission took up 141 writ applications but heard more than 216 petitioners because some writ applications contained several petitioners. All of them were noticed and heard individually personally or through lawyers.. The orders passed on the writ applications have been **enclosed in Volume-II**. All the orders have been placed on the website of the Rural Development Deptt (rdd.bih.nic.in).

(21)

DID THE GRAINS BECOME ROTTEN AND WERE THEY THROWN AWAY OR WERE THEY DIVERTED INTO BLACK MARKET :

27- The dealers have advanced their submission that the grains became rotten and were thrown away by them and therefore, they was no liability upon them to pay the price of the decomposed rice.

28- The dealers objected to the demand of price of the rice firstly; on the ground that they had not been told that they would be liable to pay the price of the residual grains. The second objection was that there was no obligation upon them to keep the rice in good order. Their stand was that the State did not provide adequate facility for preservation of rice. The third objection was that the rate at which the price was demanded was unconscienable. According to them the calculation of wages for workers was @ Rs 6.22 per head and therefore, this was the maximum sum which the Government could demand from the dealers.

29- It is elementary that the PDS dealers had not paid for the rice delivered to them. That was given to them free as trustees. It is therefore axiomatic that in case of malfeasance or misfeasance, they would be liable to pay their price. The stand of the dealers that they had not been told that they would be liable to pay the price of the residual grains and therefore they would not pay. It is a silly stand. That argument urged on behalf of the dealers ought to be rejected outright.

30- The first question that arises is whether there was any liability upon the dealers to keep the grains in perfect order. In that connection it is relevant to look at Clause-16 of the license granted to the petitioners under the Public Distribution System (Control) Order, 2001 which reads as follows :-

> **Clause-16:**"The licensee shall keep the essential commodities in proper manner and take adequate measures to prevent it from the damages due to ground moisture, rain, insects, rodents, birds, fire and such other causes are avoided."

31- It is useful to take a view of Clause-19 also of the said order which reads as follows :-

(22)

Cluase-19:"The licensee shall provide accounting of the actual distribution of essential commodities and the balance stock in the end of the month and to submit a report to the Block Supply Officer with a copy to the Gram Panchayat on demand.

32- From the above, it should be appreciated that there was a duty cast upon the license holders to preserve the grains in good order. There is nothing in the rules or act indicating that the Government would provide amenities to the dealers for preserving the grains. It should also be appreciated that the grains under SGRY was not given to each and every dealer but it was done on selective basis. Thus it will not be right to say that there was no obligation upon the dealers to preserve the grains.

33- The dealers were trustees of the grains. If the grains deteriorated or were spirited away it would amount to embezzlement of the property entrusted to them. If the trust is betrayed it is elementary that the dealer would be liable to defray the value of the entrusted grains. Even before the introduction of SGRY scheme the dealers were under obligation to preserve the grains. That condition would continue even when the dealers were functioning under SGRY. It is therefore not open to the dealers that they were not liable to pay the price of the grains as they had not been told that they would be liable to pay for the residual rice. **The monthly statements as required by Clause-19 of the License Order were never complied by them.**

34- Clause 19 quoted earlier enjoined the dealers to provide account of actual distribution of essential commodities and the balance stock in the end of the month to the Block Supply Officer. If this had been complied by the dealers it would show clearly that there was no rotting of rice. That is why they never submitted monthly statement of account to the Block Supply Officer with copy to the Gram Panchayat.

35- The dealers have stated in every case that the grains became rotten and they threw it away. This question is one of fact as well as law. Prior to the demands none of the dealers had informed any State authorities that the grains had deteriorated and become useless. They

stated before the Commission that they had stated orally about the conditions of the grains. I regret I am unable to see any merit in their belated oral statement ten years after the closure of the scheme about the rotten condition of the grains. No documentary proof has been produced by any dealer in regard to the rotting of the grains Several BDOs and superior officers were asked whether they had been informed about the grains having become rotten. They all stated that none of the dealers stated before them that the grains had rotten and they had been thrown away. In the absence of any documentary proof of having informed the authorities about the rotting of grains, I am unable to accept that the grains got rotten and they had thrown them away and as a matter of fact I hold accordingly:

36- Even if the grains had deteriorated, they had no right to discard them as they liked. There is a full paraphernalia for disposal of deteriorated rice. That could have been gone through if the dealers wished to throw them away. I for one, cannot conceive of hundreds/thousands quintals of rice having been destroyed and thrown which would entail further expenditure in handling and carting them.

37- There were two options open to the dealers; one was to suffer the rotting and throwing away the rice and the second was to sell them in dubious (black) market. Question is what a grain dealer would prefer? The obvious answer, to my mind, is that a grain dealer would utilize it for black marketing and to use the story of the grains having become rotten as a ploy to cover their nefarious game. Two former Collectors of Vaishali district were questioned whether they had been informed of the grains having been rotten and thrown them away. They all said that no one ever informed them about it. The course of throwing away so called rotten rice would have raised hue and cry, as a scandal in the villages in which they would have been thrown. Further, rotten rice could be used as chicken feed or manure.

38- Therefore, the dealers had no right to throw the residual rice. The normal honest course for the dealers would have been to inform the authorities that they were going to throw out the so-called rotten rice and thereafter, inform the authorities that they had done so. Such

information was never given to the authorities by any of the dealers. In absence of such conduct by the dealers, I am sanguine that the rice did not rot but had been disposed of in the black market surreptiously.

39- There is yet another aspect of the matter. The huge volume of rice said to have been deteriorated would not have taken place in one day. Clause-19 of the license enjoins (quoted above) that the licensee shall provide accounting of actual distribution of the essential commodities and balance stock at the end of the month and submit report to the Block Supply Officer. If the grains had deteriorated, they should have stated in the monthly statement about the quantity of rice: rotten and disposed of every month. Two Collectors of Vaishali, Dr.Pratima S. Verma and Mr.Atish Chandra stated that there used to be regular monthly Shivir but no one officer or dealer complained that the grains had become rotten.

40- The Commission examined some persons of the relevant area in Vaishali and inquired about the condition of the residual rice. One Raj Narayan Singh who has Panchayat Secretary of Saharia Gram Panchayat of Jandaha block stated in his deposition on oath that PDS dealer Raj Kishore Singh of his Gram Panchayat never informed him that the rice in his stock was getting rotten.

41- Surajdeo Singh, a Panchayat Secrtary of Hussaina Khurd deposed that Ram Bharos Singh, a PDS dealer in his Gram Panchayat never informed him that the rice in his stock was getting rotten.

42- Raj Nandan Singh of Chak Jamal Panchayat also deposed that PDS dealer Ravindra Singh never informed him that the rice in his shop was getting rotten.

43- Binod Kumar Rakesh, Panchayat Secretary of Daudnagar Panchayat (Aurangabad) also deposed that PDS dealer Vijay Singh never informed him that SGRY rice was getting decomposed.

44- Binod Kumar Gupta, Panchayat Secretary of Majrohi Sahariya Panchayat deposed that PDS dealer Raj Kishore Singh never informed him that 186 quintals of rice in his stock was getting rotten.

(26) (25)

45- The oral evidence of the Officers convinces me that the story of rotting of rice was a cock and bull story to cover the nefarious design of diverting the grains in the black market.

46- **Taking all aspects of the matter, I have not the least doubt in holding that the rice had been sold by the dealers in black market. The allotment of rice to them was a God sent opportunity to enrich themselves. In my view, they made full use of the opportunity which had fallen in their lap. They sold the grains in black market and enriched themselves. The rice had not rotten. The case of discarding the rice as rotten is totally unacceptable. I reject it outright.**

47- Another question which some dealers raised was that they had been forced to accept custody of the grains. I cannot accept this at all. No grain dealer would miss the opportunity of getting thousands of quintals which provided lee way to make good time. **No dealer has produced any document to show that he was not willing to undertake this obligation.** Some dealers stated to have been threatened with cancellation of the license if they did not cooperate in the working of SGRY scheme. This attitude of the authorities, the dealers state, was a threat to them to accept the rice. I am unable to accept this as a threat. I do not think that this was so in every case. The authorities would be fully justified in cancelling license of any dealer if he did not accept the obligation under the SGRY scheme. The warning of cancellation of license in not cooperating with the SGRY scheme was fully justified. The dealers having been chosen under the SGRY scheme on a selective basis shows that it was not forced upon them. I have no doubt that the dealers must be longing to get the rice. This was God sent opportunity to the dealers to get the rice as much as they could and there was no question of forcing them to receive the same. DDCs and other officials rejected the stand of the dealers. None the less the threat of cancellation of license was fully justified.

48- My conclusion that the grains had not become rotten, gets re-enforced by the fact that seven dealers in Katihar namely; Kali Charan Mandal,

~~23~~ 26

Mansoor Alam, Md Qayyum, Rajendra Poddar, Jalaluddin Khan, Tilotama Devi and Zainul Ansari did not get their accounts audited despite ten reminders to them. Sita Devi, a dealer in Dharahara block in the district of Munger was also noticed to appear for audit but she never appeared for the audit. The audit would have revealed that the grains had been sold in the black market. Similar is the case of Bhawesh Kumar Bhaskar, a dealer of Tardih block in Darbhanga district who tried to escape the liability of payment of price of 1936 quintals of residual rice by refusing audit for 10-11 years.

49- The stand of the dealers that the grains had become rotten for non-distribution for a long time gets completely blasted by the example of Meena Devi, a PDS dealer within Loharpur Panchayat who stated in writing to the BDO, Nawada block that she had lifted rice between 2005 and 2006 under the SGRY and after distribution, residual rice was still in her godown. She wrote to the BDO that he was welcome to visit her godown and examine them. The quantum of demand is a different matter but her statement shows that even in 2011 the grains were intact and had not deteriorated. In my view it would not be correct to assume that the rice had become rotten (useless) because of lapse of time.

TERMS AND CONDITIONS FOR PDS DEALERS:

50- The duty prescribed for the Commission was to determine the terms and conditions of allotment of rice to the dealers under SGRY for distribution to beneficiaries. This condition gets dovetailed with the fourth condition namely; ascertainment of the payment of transportation/handling/storage charges to PDS dealers.

51- The dealers were all PDS dealers in terms of Licensing Order from before the Commission came into operation. The conditions prescribed for the dealers were that they were to lift the grains from the SFC godowns and were to be paid transportation and handling charge. There was no other condition for payment to the dealers. No storage or commission was to be paid. Some of the dealers made a grievance about it but they could not show any material to indicate that anything apart from transportation and handling charge was to be paid to them under the SGRY scheme. The dealers were required to deliver rice free of cost on permits/coupons/parchas issued to them by the BDO or the authorities of the Panchayat Samiti or the Zila Parishad by the authorities like DDC or the District Engineer. The dealers must have been getting paid for transportation and handling of rice for BPL/APL from before the implementation of the SGRY scheme in terms of other schemes.

52- The dealers were required to lift rice from State Food Corporation in accordance with the order of BDO or Officers of Zila Parishad. The dealers had not to pay for the grains. After having received the grains, they were to deliver rice free in accordance with the direction of the Mukhiya or BDO or Panchayat Samiti or Zila Parishad in accordance with previously approved schemes. In this connection, it is noteworthy that the dealers were to receive transportation and handling charges. All the dealers were holders of food grains license in terms of food grains licensing order from before the launching of SGRY scheme.

(28)

PAYMENT OF TRANSPORTATION AND HANDLING CHARGE TO THE PDS DEALERS :

53- This Commission is required to give its recommendation is in regard to the transportation and handling charges to be paid to the PDS dealers. At the initial stage, I had passed order for payment of those charges @ Rs 50/- per quintal. After I had passed the order, new facts came to light and I felt that my order for payment of transportation and handling charges @ Rs 50/- per quintal was wrong and required reconsideration. I therefore, issued order putting a restraint upon payment of transportation and handling charges until the submission of final report of this Commission. I am now giving my deliberation after serious thought on the question.

54- There are three kinds of material for ascertaining the amount which the dealers could be paid as transportation and handling charge. The first material is letter No.83/C dated 14/03/2002 sent by Mr KAS Subrahmanian, Commissioner & Secretary, Rural Development Department. This letter gives an indication that Rs 50/- per quintal was to be paid to the Food & Civil Supplies Corporation as transportation and handling charges. This letter was sent to all the Deputy Development Commissioners with a copy to the Managing Director, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation. This amount of payment was natural as all grains to be distributed were to be done through the State Food Corporation after lifting them from Food Corporation of India.

55- Another letter which has bearing on the subject is letter No.4695 dated 07/06/2011 from the Managing Director, Bihar State Food & Civil Supplies Corporation. This letter is addressed to all the District Managers of the Corporation. This letter was really for the purpose of directing the district units indicating that the SFC was to receive Rs 37/- per quintal as transportation and handling charges. Thus out of Rs 50/- as directed in the letter of Mr KAS Subrahmanaian, the SFC had to retain Rs 37/-. Since the Corporation did not transport the grains to the dealer, the charge for it was payable to the PDS dealers. That sum

would be Rs 50/- less Rs 37/- i.e Rs 13/- per quintal. This is what the PDS dealer was to get as transportation and handling charges.

56- In support of my above conclusion, I have the statement of the three petitioners in CWJC No.5638/2011- Raiful Azam & Ors Vrs State of Bihar & Ors. In paragraph-7 of the writ petition, it has been stated as follows :-

> "The PDS dealers were required to lift food grains from the SFC godown, Chanpatia for the purpose of distribution to the persons duly authorized by the Block Development Officer, Sikta and/or Panchayat authority. The petitioners submit that it was agreed between the dealer and the respondent authorities **that the dealer would be paid fare for transporting the food grains from SFC godown, Chanpatia to their godown @ Rs 13/- per quintal."**

If such an undertaking was given by the authorities, it would be quite sensible. I have no reason to doubt that such a provision was provided by the authorities.

57- The petitioner in CWJC No.19529/2011-Sadanand Yadav Vrs State of Bihar also stated in his show cause before the Deputy Development Commissioner, Munger as follows :-

> "It is also relevant to state here that under the scheme the petitioner was to be treated only as a carrier and store keeper and for that purpose, he was to be paid Rs 13/- per quintal as handling expenses by the Government. It is a matter of record that he has not been paid even a single penny for the same. **He was to be paid Rs 13/- per quintal as handling expenses."**

58- Petitioner Sita Devi, a PDS dealer within Dharahra block in the district of Munger at paragraph-14 in her writ application before the High Court (CWJC No.21284/2011) also stated as follows :-

> **"14-** That it is a matter of record that the petitioner has not been paid even a single penny till date for the delivered rice although she is entitled for handling expenses as well as the transportation cost @ Rs 13/- per quintal i.e. Rs 19,500/- as guaranteed under the scheme."

And again, Suresh Prasad, petitioner before the High Court in CWJC No.6570/2013 stated at paragraph-11 as follows :-

(20)

"11- That it is also relevant to state here that under the scheme the petitioner was to be treated only as a carrier and store keeper and for that purpose he was to be paid Rs 13/- per quintal as handling expenses by the Government. It is a matter of record that he has not been paid even a single penny for the same although he is entitled for the handling expenses to the tune of Rs 23,738/-."

At pargraph-12 he claimed that :

"12- he is entitled to storage rent of Rs 1,80,000/- @ Rs3000/- for a period of five years due to non-issuance of valid permits which is still due and lying with the respondent authorities."

There is no merit in the claim for storage charge.

59- After the candid statement of Raiful Azam, Sadanand Yadav, Sita Devi and Suresh Prasad Sah, there is no room for doubt that the petitioners had been told that they would be getting Rs 13/- per quintal as transportation and handling charge. In that background, my earlier order in case of some dealers for payment of Rs 50/- per quintal as transportation and handling charge was based on misinformation. **The order for payment of transportation and hanlding charges @ Rs 50/- is held to be NON EST.** It is regrettable that the officers- BDOs and DDCs did not inform the Commission that the dealers knew very well that Rs 13/- would be the transportation and handling charges. The Rural Development Deptt also at the initial stage failed to clearly set out the sum payable to the dealers.

60- Thus, the terms and conditions for allotment of rice to the PDS dealers were that the dealers would act as carriers. Nothing else was to be paid for that. The dealers were to get only Rs 13/- per quintal as handling charge. This conclusion answers the second condition for inquiry laid down by Hon'ble M.K. Jha J.

61- The only question which remains is whether the dealers would be paid transportation and handling charge by the Collector or the State Food Corporation. If the State Food Corporation (SFC) had received transportation and handling charge @ Rs 50/- per quintal, the SFC must pay the transportation and handling charge @ Rs 13/- per quintal to the dealers. On the other hand if the SFC had not received the transportation and handling charge, the Collector must pay to the

dealers the transportation and handling charge. This matter must be decided by the Collector himself. In my view the proper course would be to pay to the dealers the transportation and handling charges by adjustment from the sum demanded from the dealers. Copies of the letters written by Mr KAS Subrahmanian and Mr Pradeep Kumar are enclosed with this report as **Annexure- 4 and 5** respectively.

62- The third condition for inquiry was the manner of allotment of rice to the PDS dealers. In this behalf it has to be said that the grains were to be supplied to the State Food Corporation (as Agent of State of Bihar) by the Food Corporation of India. The rice was to be delivered to the nearest godown of the State Food Corporation in order to minimize expenses of transportation. After the grains had been lifted by the State Food Corporation, rice was to be allotted to different PDS dealers by the BDO or Panchayat Secretary or District Engineer of Zila Parishad and the DDC who has overall incharge of the scheme. The BDOs or Zila Parishad Officers were to issue release orders to the State Food Corporation. Thereafter, the dealers would lift the rice from the State Food Corporation. The dealers were to release grains to either the Mukhiya or to the executing agencies only on the basis of coupons or parchas issued by the executive agencies of the BDOs or other Officers. All dealers were required to maintain Stock Register showing the quantity of rice lifted by them and the quantity of rice delivered to different executive agencies. Further every PDS dealer was required to submit monthly statement of his stock. This was however complied only by default. Consequently, the BDOs or DDC never submitted the status report to the State Government. This fact was noticed by Mr Anup Mukherjee, the then Principal Secretary, Rural Development Deptt. who recorded in the proceeding that status report has not been sent. Further it may be stated that in the beginning of the year, every DDC was required to check and approve all schemes of work. The Government was not obliged to provide any assistance in preserving the rice. The rice was to be delivered only to such dealers who had the capacity to store them. Whether this was complied by the dealers or not or by the BDOs is a big question. It appears that the dealers did not possess the requisite capacity to

maintain the quality of rice but accepted them for the reason that that was an occasion for them to make hay while the sun shone. Those were the method of allotment of rice to the dealers.

63- At paragraph-18(B) Mr Justice M.K. Jha directed the Commission to ascertain the price of rice on which recovery had to be made. That brings us to the question of rate of realization.

64- The matter under examination has become about 17 years old. No Officer of that period during 2002-2006 is available to enlighten this Commission. On the basis of materials available before this Commission, my conclusion in regard to the transportation and handling charges of Rs. 13/- per quintal should be paid to the dealers if not paid already.

~~34~~ 33

RATE OF REALISATION :

65- I had heard the parties either in person or through counsel on the issue of rate of realization for the residual rice from the dealers. A general notice had been published in the press to all dealers in regard to the stand on the rate of realization. Some lawyers appeared and submitted that the rate of realization could only be Rs 622.50 per quintal which was the rate at which Government was calculating the wages to be paid to workers. I heard the counsel at length. In my view, there is no substance in the stand that the dealers were liable to pay only Rs 622.50 per quintal. The FCI had declared its economic cost for SGRY as Rs 1370/- per quintal. The State Government had laid down that it would **purchase rice at economic cost**. In that situation, the State Government is fully justified in demanding Rs 1370/- per quintal as the price of rice. The subsidized rate of rice as APL or BPL cannot form the basis of the realization. If the entire rice had been distributed, the dealers would not be liable to pay anything but since the entire rice was not distributed and found its way in the black market, they were certainly liable to pay the economic cost. The State Government was therefore fully entitled to realize the price of residual rice @ Rs 1370/- per quintal. The State Government Circular issued by Mr S. Mathew, Principal Secretary, Rural Development Deptt. was well founded. In my view, the realization must be done @ Rs 1370/- per quintal. This concludes the discussion in regard to the rate of realization. I have passed this order earlier also and I am mentioning it in this report as well. My earlier order dated 30/05/2017 is also annexed as **Annexure- 6.**

66- Most of the PDS dealers working under the food grains licensing order, were involved in the various welfare schemes namely; Jawahar Rozgar Yojana, Food for Work Scheme and were lifting rice in accordance with those schemes. The incidence of those schemes were different from the incidence under the SGRY scheme.

67- I had occasion to examine the audit of Katihar district at some depth. I found that 10 dealers failed to join the audit for six years although they were repeatedly told to get the audit done. After six years fudged

up papers formed the basis of audit. The auditor himself of M/S Ramakant Jha & Co did not examine the matters and left the audit to its employees (Clerks etc). They were too willing to help the dealers. In some occasion I rejected the audit report. The audit report especially in regard to Abdul Razzaq and Amanullah (Enayatullah) were clearly unacceptable. Similar situation appeared in case of a dealer of Tardih block of Darbhanga district which has already been mentioned earlier. The Commission did not have the time and opportunity to examine the working of audit in other districts.

DELINQUENCY OF COLLECTORS & COMMISSIONERS :

68- In the original notification the Commission had been enjoined to fix responsibility to the loss of residual food grain after closure of the SGRY scheme. In this behalf the role of Commissioners, Collectors and SDOs was also considered.

69- The fact that thousands of tons of rice was with the dealers was an established fact. In that situation, the former Collectors of Vaishali stating that no one informed them about the existence of huge volume of rice shows either that the claim of holding of monthly Shivir was a false claim or that they knew about it but concealed the fact from the Commission. Either situations are deplorable.

70- The Collectors of the district and the Commissioner had their own role to play in the functioning of the scheme. In Chapter VII of the guidelines framed by the Central Government, it was laid down at paragraph 7.1.1, 7.1.2 and 7.1.3 as follows :-

> **7.1.1** – Vigilance & Monitoring Committees at the State, District and Panchayat Samiti level constituted for overseeing the various programmes of the Ministry of Rural Development will also be responsible to monitor the implementation of the works under the first and second streams of the SGRY.
>
> **7.1.2** – Schedule for inspection of works – For effective implementation of the programme, the officers at the District, Sub-Division and Panchayat Samiti levels must closely monitor all aspects of the programme through visits to work sites in the interior areas. A schedule of inspection, which prescribes the minimum number of field visits for each supervisory level functionaries from District to Panchayat Samiti level should be drawn up by the Zila Parishad/DRDAs and strictly adhered to. A copy of the inspection of schedule drawn should be sent to State and Central Governments for information.
>
> **7.1.3** – The officers dealing with the SGRY at the State headquarters shall visit Districts regularly and ascertain through field visits that the programme is being implemented satisfactorily and that execution of works is in accordance with the prescribed procedures and specifications.

(35) (36)

71- From the above it will be observed that Monitoring Committees at the State/District/Panchayat level had to be constituted. There is no report of setting up of any Monitoring Committee. In terms of paragraph 7.1.2 Officers of the District/Sub-division etc were strictly enjoined to closely monitor all aspects of the programme to visit the work site in the interior area. A schedule of inspection which prescribes the minimum number of visits for each supervisory level functionary from District to Panchayat level should be drawn up by the Zila Parishad/DRDA and strictly adhered to. A copy of inspection schedule drawn was to be sent to the State and the Central Government for information. It goes without saying that Commissioners and District Collectors had a serious role to play. They were to oversee the working of the Zila Parishad, Panchayat Samiti etc. There is no evidence of any report having been sent by any Collector to the Commissioner or by any Commissión to the State Goyernment.

72- In pursuance of these directions laid down in the guidelines the State Government had issued detailed instructions by letter no.Gra.Vikas.8/Ka-37/2001-6981 dated 28.05.2002 for the functioning of the SDOs/DDCs/Collectors/Commissioners. By this letter Mr Sudhir Kumar, Special Secretary to the Government wrote to all Commissioners, District Magistrates and all Deputy Development Commissioners giving detailed instructions with regard to implementation of the Sampoorna Gramin Rozgar Yojana. In this letter, it was pointed out that an annual scheme of work should be drawn up in regard to selected schemes by the Gram Panchayat. At paragraph-VIII it was stated therein that no work was to be done through contractors. Implementation of all works should be done departmentally. In any work no middleman or agency should be employed. At paragraph-XIV prohibition was placed on the nature of works to be done under the SGRY. At paragraph-XV the duties of Divisional Commissioners, District Officers, Deputy Development Commissioners, Sub Divisional Officers and Block Development Officers were clothed with power of inspection and coordination. Zila Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat were to inspect the

works. The circular issued by the Special Secretary is annexed as **Annexure- 7** to this report. I only wish to state here that no Sub Divisional Officer, Collector and Commissioner took any interest in implementation of the scheme. In terms of the guidelines detailed monthly report was to be furnished in proforma-I by the 10th of succeeding month as per **Annexure- 8. No progress report was filed by any officer.** In terms of paragraph 7.1.2 the State Government had to ensure that the Officers of the district/State/Sub-Division and block level closely monitor all aspects of the works through visits to the worksite area. A schedule of inspection shall be drawn up by the State Government and strictly adhered to. The schedule so drawn up was to ensure that SGRY works in at least 10 Panchayats were inspected by district level officers (i.e. District Collectors) and in 2% Panchayats by the State level officers. The inspecting Officer was to send the inspection schedule by the State Government to the Ministry of Rural Development. In terms of paragraph 7.1.5 a summary of the number of inspection conducted by district and State level officers was required to be attached with proposal for release of second instalment of cash component of Central assistance. The State Government did not produce any material showing compliance of this direction by district and State level officers.

73- The relevant part of the rules contained in the Government Circular dated 28/05/2002 is as follows :-

"सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के सफल कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक महीने में निम्न प्रकार से योजनाओं का निरीक्षण करेंगे:

प्रमण्डलीय आयुक्त	पाँच योजनायें ।
जिला पदाधिकारी	दस योजनायें ।
उप विकास आयुक्त	पन्द्रह योजनायें (जिसमें कम से कम पाँच योजनाओं की लागत पाँच लाख रू0 से अधिक हो) ।
अनुमण्डल पदाधिकारी	पन्द्रह योजनायें ।
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	बीस योजनायें(दो लाख रू0 से ज्यादा की सभी योजनाओं का निरीक्षण करना आव यक है) ।

इसके अलावा जिला परिशद् को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत योजनाओं के निरीक्षण एवं अनुश्रवण की भाक्ति है । जिला परिशद् पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों द्वारा ली गई योजनाओं के निरीक्षण एवं अनुश्रवण के सक्षम है ।

विभिन्न स्तरों पर गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति भी इन योजनाओं के अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण समय–समय पर कर सकती है ।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत एक वि ोश अंगीभूत अवयव का भी प्राक्धान है । इसके तहत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जिला/प्रखण्ड/पंचायत में राज्य सरकार की अधिसूचना निर्गत होने के प चात् अलग से मुफ्त खाद्यान्न का आवंटन किया जायेगा और इस खाद्यान्न का उपयोग किसी केन्द्रीय योजना या केन्द्र प्रायोजित योजना या राज्य योजना के तहत् अतिरिक्त संसाधन के रूप में होगा और उसी केन्द्रीय योजना या केन्द्र प्रायोजित योजना या राज्य योजना के लिए लागू मार्गदि िका के प्राक्धान के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा । इस योजना का कार्यान्वयन जिला समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा किया जायेगा।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के मार्गदि िका के प्राक्धानों एवं उपर्युक्त निदे ाों के आलोक में कार्रवाई सुनि िचत की जाय । जहाँ भी इस पत्र में दिये गये निदे । तथा भारत सरकार द्वारा प्रचालित मार्गदि िका में कोइ भी विरोधाभाश प्रतीत होता है तो भारत सरकार द्वारा सम्पुर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए प्रचालित मार्गदि िका के प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करना होगा ।

इस पत्र के साथ अनुलग्नक के रूप में उप विकास आयुक्तों तथा जिला परिशद् पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले कार्यों की एक संक्षिप्त सूची सुविधा हेतु संलग्न है।"

74- The rules were completely ignored by the Commissioners, Collectors and Sub Divisional Officers. A SDO was required to inspect 15 schemes. The Collector was required to inspect 10 schemes. A DDC was to inspect 15 schemes (in which at least 5 schemes should have been of the involvement of Rs five lakh and above). There is no report from any SDO to DDC or Collector. There is no report of any DDC to the Collector of the district in writing. No Collectors sent any report to the Commissioner and no Commissioner examined any scheme nor sent any report in writing. Thus, all the high officials took no interest in the implementation of the SGRY scheme.

75- A general notice was published in the press directing all the SDOs/D.D.Cs./D.Ms./Divisional Commissioners in the State to appear before this Commission and state the interest taken by them in the implementation of SGRY scheme. Collectors who were examined by the Commission stated that they all took full interest in the scheme.

That was the statement of Dr Pratima S. Varma, the then Collector, Vaishali district and Mr Atish Chandra who was also Collector, Vaishali for some time. Both of them however feigned ignorance about the existence of huge quantity of rice in the godowns of the dealers. They stated that no one informed them about it. The fact was that huge quantity of rice was available with the dealers according to their Stock Register but the two Collectors stated that nobody informed them about the situation. This shows that the Collectors showed no initiative in the implementation of the SGRY scheme or its successor NREGA scheme. This was serious lapse on their part.

(40)

DISPOSAL OF WRIT APPLICATIONS :

76- As stated earlier, two Members of the Commission – Mr Sanjay Kumar Singh, IAS (Retd) and Mr Arun Kumar Singh, IA&AS (Retd) relinquished office. The Chairman of the Commission (i.e. myself) brought the situation to the notice of the Hon'ble Chief Justice. His Lordship treated the letter of the Chairman as an I.A. heard the parties and passed order on 02/08/2017 laying down that the Commission need not examine all the dealers of the State **(Annexure-3).** His Lordship ordered that :

> "(3) the Commission shall cause an inquiry only with regard to the inquiry of such of the persons who have filed writ petitions before this court pertaining to which orders were passed on 21/09/2015 in CWJC No. 19529/2011 and analogous cases. Scope of the inquiry shall be confined to the adjudication of the dispute raised by the writ petitioners who had filed writ petitions before this Court.
>
> (4) the persons or PDS dealers who are not parties in the writ petitions or who had not ventilated their grievances in the writ petitions before this Court shall not be permitted to take up the issue before the Commission.
>
> (5) the Commission shall further ensure that the condition stipulated in the original order passed on 21/09/2015 with regard to deposit of the 50% of the Certificate amount for the purpose of preventing coercive action shall continue to remain in operation."

Thus this Commission was required to hear the dealers for disposal of the writ applications.

77- 141 writ applications had been filed before the High Court. They were all sent to this Commission. The number of dealers was however more than 141 since several of the petitions contained several petitioner dealers (more than one). The number of dealers swelled to 214. Since they all had to be heard, fresh notices were issued to all writ petitioners to appear with their representation, if any. Several of them

filed representation while others made oral submissions. Some of them appeared personally and some of them appeared through their counsel. In terms of the order of the High Court in regard to payment of dues, every dealer was directed to deposit 50% of the demand. Only such of them were heard who had deposited 50% of the demand. Most of the dealers deposited 50%. Very few recalcitrant dealers refused to deposit. In some cases there was dispute about the quantum of the demand. In those cases after 50% of the demand had been deposited, they were heard. Their cases were given due consideration.

78- All the writ applications have been disposed of. The final orders have been placed on the website of the Rural Development Deptt **(rdd.bih.nic.in).** Hard copies of orders have been placed in Vol.II of this report. I am happy to inform the Government and the High Court that quite a substantial amount has been realised from the dealers but unfortunately the authorities are not in a position to inform the Commission how much has been realised in regard to SGRY scheme.

QUANTUM OF ACTUAL LOSS TO THE GOVERNMENT :

79- The first question posed by Mr Justice M.K. Jha was to ascertain the quantum of actual loss sustained by the Government. That I now proceed to decide.

80- Most of the dealers had lifted the rice but they had not distributed them all for various reasons, either for want of issuance of coupons by the Mukhiya or the Panchayat Secretary or the District Engineer/DDC in the Zila Parishad. Thus huge quantity of rice remained with the dealers. These I shall describe as residual rice. For ascertaining the quantity of residual rice, the Commission had to rely upon the figures supplied by the DDCs. I regret to write that DDCs or the District Rural Development Authority (DRDA) rarely checked the figures that were being supplied to us in regard to lifting and distribution of rice by the BDOs/other agencies. The DDCs only countersigned the statements without checking or verifying them. The result was that BDOs often appeared with different figures in regard to distribution of rice and the Commission had to repeatedly send back to the BDOs to do the re-checking. The Commission therefore has calculated the volume of residual rice on the basis of figures supplied by the district authorities. After calculating the residual rice of all the 38 districts, it was found that the residual rice was to the tune of 1744583.94 quintals i.e. 174458.394 tones, the value thereof in terms of Rs 1370/- per quintal was Rs 239,00,79,997.80 (Rupees two hundred thirty nine crore seventy nine thousand nine hundred ninety seven and paise eighty only).

81- In calculating the residual rice the Commission was faced with some double dealing by the auditors. The Commission found that the auditor M/S Ramakant Jha & Co. was guilty of several lapses. Even on being summoned Ramakant Jha did not turn up to explain the discrepancies. He always sent his clerical staff. I was somewhat perturbed at the attitude of the clerical staff. They had no compunction in accepting furgged papers (coupons and stock registers) which was obvious to my eyes. The clerks had no answer to them. I had the impression that these clerks were also parties to fabrication of

coupons. This was so especially in the district of Katihar. The Commission did not have the time to verify the activity of the Auditors in other districts. The State Government would be well advised to consider whether M/S Ramakant Jha should be retained in the panel of Auditors. Thus the loss sustained by the State Government was to the extent noted above.

COMMISSION AT WORK :

82- I had occasion to examine the audit of Katihar district in some depth. I found that 10 dealers failed to join the audit for six years although they were repeatedly told to get the audit done. After six years, fudged up papers formed the basis of audit. The Auditor himself of M/S Ramakant Jha & Co did not examine matters and left the audit to its employees (Clerks etc). They were too willing to help the dealers. In some occasion I rejected the audit report. The audit report especially in regard to Abdul Razzaq and Amanullah (Enayatullah) were clearly unacceptable. Similar situation appeared in case of a dealer of Tardih block of Darbhanga district which has already been mentioned above. The Commission did not have the time and opportunity to examine the working of audit in other districts.

83- The manner in which the loot took place in the district of Munger needs to be mentioned. On 31/12/2005 when it was known that the scheme was going to be closed, the picture of residual rice in seven blocks was as follows :-

Block	Lifting	Distribution	Balance	Price
Zila Parishad	10422.00	NIL	10422.00	1,42,78,140
Munger Sadar	3583.29	NIL	3583.29	49,09,108
Jamalpur	3749.00	NIL	3749.00	51,36,130
Tarapur	2099.31	NIL	2099.31	28,76,055
Sangrampur	3841.74	NIL	3841.74	52,63,184
Asarganj	9197.65	NIL	9197.65	1,26,00,780
Tetia Bambar	9607.49	NIL	9607.49	1,31,62,261
Haveli Kharagpur	79.06	NIL	79.06	1,08,312
Bariyarpur	4892.00	NIL	4892.00	67,02,040
	3679.65 *		3679.65 *	50,41,120
Dharahra	25384.74	NIL	25384.74	3,47,77,094

These two figures create confusion which remained unexplained by the BDO. The figure with * has not been computed.

TOTAL :-	**72856.28**		**72856.28**	**9,98,13,104**

84- It may be observed that all the lifting was done after 31/12/2005 and at that point of time it was known to the authorities that the scheme was to be closed after March, 2006 and yet lifting in huge quantity was ordered by the authorities. All of them remained undistributed. After the order of lifting of grains post December, 2005, no coupons were issued. That is indicative of the fact that the authorities and the dealers were hand in gloves. The dealers stated that no coupon was issued and therefore, rice was not distributed. This is not a situation of dealers versus BDO or DDC. **It is a situation of dealers, BDOs and the DDC hand in gloves.** The guidelines provided that in the beginning of every year, a list of schemes would be prepared and lifting would be ordered in terms of the scheme but the fact that lifting was ordered but no coupon issued clearly shows that no scheme had been drawn up and that the DDC, BDOs and the dealers were hand in gloves. I have not the least doubt about the rice in the stock on 31/12/2005. The conclusion is obvious that the lifting was ordered with oblique motive. It becomes clear that there was no scheme and the lifting was not correlated with any scheme. The total value of the undistributed rice was Rs 9,79,36,211.65 (Rupee nine crore seventy nine lakh thirty six thousand two hundred eleven and paise sixty five).

85- Mention must be made of Jamui district. The shop at Laxmipur in the district of Jamui was the flash point which brought the caracas tumbling. The Office of the Auditor General commented that the representative of the Auditor General had gone to Laxmipur and learning that the dealer is not issuing rice, the Auditor General's men found that the dealer escaped physical verification of the godown. The dealer actually fled away and avoided checking. If there had been physical verification it would have been evident that there was no grain in the godown.

86- Mr M.K. Agrawal was BDO, Dharahra block between 30/05/2005 and 30/12/2006. That is the period when Mr Agrawal ordered lifting of 231 quintals of rice but nothing was distributed. Question is why did he not issue coupons. This non issue of coupons reflects on his integrity. If there was no scheme why did he order lifting of 231 quintals of rice ?

87- Mr Upendra Kumar was the DDC, Munger between 30/05/2005 to 31/12/2006. The liftings by B.D.Os. (apart from 231 quintals) were ordered by the DDC, Munger, Mr. Upendar Kumar. The Commission has recorded the statement of Mr Upendra Kumar. Summonns were issued to the then District Engineer, were not a sereved upon him as he was said to be traceless. The total misappropriation in the district of Munger was to the tune of Rs 9,79,36,211.65 (Rupee nine crore seventynine lakh thirtysix thousand two hundred eleven and paise sixty five).

88- I must mention about the state of affairs which took place in Dharahra block of Munger district. Seven persons namely; Mahendra Yadav, Dinesh Yadav, Suresh Prasad, Arjun Prasad Verma, Umesh Paswan, Braj Bhushan Singh and Sadanand Yadav were ordered to lift rice in huge quantity. The value of which @ Rs 1370/- per quintal was Rs 1,07,08,942/-(Rupees one crore seven lakh eight thousand nine hundred fortytwo) only. Rice was issued to these dealers but that remained unutilized. There is no evidence of their lifting being ordered in connection with any scheme. I have mentioned that out of the above liftings, Mr M.K. Agrawal, the then BDO, Dharahra block was responsible for lifting of 231 quintals of rice which was not utilized at all. The balance lifting was ordered by the District Engineer and the DDC, Munger. The responsibility of non-utilization of this rice also must fall upon the BDO, District Engineer and DDC, Munger. Mr Upendra Kumar who was the DDC, Munger from 30/05/2005 to 31/12/2006.

89- Besides the pilferage/embezellement at Dharahra block, there is another scandalous affair. A dealer Mahendra Yadav at Dharahra block had lifted 2150 quintals of rice. The value of which was Rs 29,46,185/-. Mr Sujit Kumar Raut, the present BDO has filed a report before this Commission that the residual rice with Mahendra Yadav was only 127 quintals. The same BDO has sent another report today stating that Mahendra Yadav had lifted 100 quintals under SGRY scheme and 27 quintals under NFFW. He has reported that on 17/10/17 the Stock Register and distribution statement of Mahendra Yadav was examined. From the Stock Register and Distribution

(47)

Register it showed that Mahendra Yadav was left with 2150.50 quintals of rice. It appears that the major part of lifting was done under NFFW. In any view of the matter, the BDO was responsible for embezzlement for the entire 2150 quintals of rice. The total embezzlement at Dharahra block appears to the tune of Rs 2,44,32,373/-(Rupees two crore forty four lakh thirty two thousand three hundred seventy three) only.

90- The involvement of Mr Upendra Kumar cannot be brushed aside. This matter must be dealt with by the State Government for taking appropriate action. Mr Arvind Kumar Singh retired a year earlier.

91- The picture in Dharahra block of the district of Munger is mind boggling. Within Dharahra block there were seven dealers besides twenty others namely; Mahendra Yadav, Dinesh Yadav, Suresh Prasad, Arjun Prasad Verma, Umesh Paswan, Brij Bhushan Singh and Sadanand Yadav. The lifting of rice by them after 31/12/2005 was as follows :-

		Lifted Quantity	Distributed Quantity	Balance Quantity	Value @ 1370/-
1-	Mahendra Yadav	2150.50	NIL	2150.50	29,46,185
2-	Dinesh Yadav	7512.00	NIL	7512.00	1,02,91,440
3-	Suresh Prasad @ Sah	709.21	NIL	709.21	9,71,617
4-	Arjun Prasad Verma	517.14	NiL	517.14	7,08,481
5-	Umesh Paswan	5259.00	NIL	5259.00	72,04,830
6-	Brij Bhushan Singh	1255.00	NIL	1255.00	17,19,350
7-	Sadanand Yadav	431.00	NIL	431.00	5,90,470
	TOTAL:	**13833.85**		**13833.85**	**2,44,32,373**

92- The picture in Bariyarpur block was equally dismal. As an example; I am mentioning three dealers namely; Sita Devi, Chamaklal Chaudhary and Chandra Shekhar Prasad. The lifting and balance rice in regard to these dealers were as follows :-

(48)

40

SN.	Name of the dealer	Lifted Qty	Distributed Qty	Balance Qty	Price
1.	Sita Devi	4813.63	NIL	4813.63	65,94,673
2.	Chamaklal Chaudhary	957.17	NIL	1957.17	26,81,322
3.	Chandra Shekhar Pd	1680.24	NIL	1680.24	23,01,928
	TOTAL:	**8451.04**		**8451.04**	**11577923**

93- I have no doubt in my mind that the rice lifted by them were misappropriated by the dealers in conjunction with officers.

94- The entire rice lifted by the dealers remained unutilized. There is no evidence of the lifting having been ordered in connection with any scheme. The guidelines of the scheme provided that lifting should be ordered in relation to schemes prepared in the beginning of the year. This was completely ignored. Mr M.K. Agrawal who was the BDO at Dharahra, when called upon, stated that he had not ordered lifting of the entire quantity shown above but had ordered lifting of only 231 quintals of rice when remained unutilized. He stated that the balance lifting was ordered by the District Engineer and the DDC, Munger. Tones of rice was lifted in Dharahra block when Mr M.K. Agrawal (30/05/2005 to 30/12/2006) was the BDO and Mr Upendra Kumar was the DDC, Munger from May, 2005 to December, 2006. None of the seven dealers paid anything as the price of residual rice.

The picture of seven other blocks also needs to be scrutinized.

SN.	Name of the dealer	Lifted Qty	Distributed Qty	Balance Qty	Price
1.	Munger Sadar	3583.29	NIL	3583.29	49,09,108
2.	Jamalpur	3749.00	NIL	3749.00	51,36,130
3.	Tarapur	2099.31	NIL	2099.31	28,76,055
4.	Sangrampur	3841.74	NIL	3841.74	52,63,184
5.	Asarganj	9197.65	NIL	9197,65	1,26,00,780
6.	Tetia Bumber	9617.49	NIL	9617.49	1.31,75,961
7.	Haveli Kharagpur	79.06	NIL	79.06	1,08,312
	TOTAL:	**32167.54**		**32167.54**	**4,40,69,530**

95- Besides the above, there was 10,422.59 quintals of rice in the Zila Parishad account when the concerned scheme was closed on

31/12/2005. The value of which was Rs 1,42,78,948/-(Rupees one crore forty two lakhs seventy eight thousand nine hundred forty eight). The entire loot was to the tune of Rs 9,81,63,715/- (Rupees nine crore eighty one lakh sixty three thousand seven hundred fifteen) only.

96- From the above statements it will be seen that rice worth crores were lifted when the scheme was about to be closed and nothing was distributed. To order lifting after 31/12/2005 itself shows that the BDOs were up to some smart games. It is inconceivable before me that the entire rice deteriorated and became useless. I have not the least doubt that the rice found dubious alleys and were sold in the black market. I am also doubtful if the entire consignments even reached the godowns of the dealer. For ought one knows the rice may have been directed to different quarters after the rice left the State Food Corporation Godowns. The DDC i.e. Mr Upendra Kumar and Mr M.K. Aggrawal must be held liable for this misappropriation. If rice worth about Rs 10 crores got misappropriated by the dealers, B.D.Os. and D.D.C. (who ordered lifting of more than 70,000 quintals of rice in January, 2006 and March, 2006) the State should examine the matter and take appropriate action. It is no answer for him (the D.D.C.) to say that no one told him about the state of affairs. They were supposed to observe the working of the scheme. They obviously failed in their duty. The dealers cannot get away by saying that the rice was not distributed because coupons were not issued by the BDOs and the District Engineers. To me it is obvious that the dealers and BDOs were hand in glove in this entire loot. The State Government may consider whether Mr. Upendra Kumar was party to the loot and shared the booty.

98- Mr. Upendra Kumar stated in his first statement that he had not ordered lifting of any rice to any particular agency but his statement was demonstrated to be false by the evidence of Mr. Rameshwar Pandey, the present D.D.C. in 2018 who deposed that by letter dated 111 dated 21/01/2006 Mr Upendra Kumar had ordered allotment of 5860 quintals and on 24/03/2006, 65120 quintals of rice to different agencies. Mr Kumar ordered lifting of huge quantity of rice and

nothing was distributed. In view of the stand of the dealers of the district of Munger that the rice had deteriorated and had been thrown away which I have not accepted, it is obvious that the rice had been disposed off in the black market. I have not the least doubt that Mr Upendra Kumar had failed in the improper allotment of rice. Mr Upendra Kumar stated that no order had been received from the Government in regard to the residual rice. Even if no order had been received it was his duty to seek instruction from the Collector, the Commissioner or the State Government. He did nothing in fact. But the big question is why did he ordered lifting of rice at the fag end of the scheme when there was no approved scheme of works. He retired about ten years ago. What action can be taken against him is for the State Government to decide. Government may take such appropriate action as it may consider necessary. It was the duty of Mr. Upendra Kumar, D.D.C. to inform all the authorities about the residual rice.

99- Mr. Arvind Kumar Singh was the D.D.C., Munger between 30/12/2006 to 29/10/2009. No work was taken up during his tenure. In 2009 he took steps for initiating coercive steps but his hands got tied because of the restraint orders passed by the High Court restraining any coercive action. He therefore cannot be found guilty of any delinquency. However, before such restraint orders came, he succeeded in realizing more than 23.00 lacs from the dealers. He also got filed several criminal cases and certificate cases. The situation at Munger beats all comprehension.

100- Thousands of quintals of rice were directed to be lifted without any scheme being in existence. In the district of Munger in Dharahra block, seven dealers were directed to lift 13833.85 quintals of rice. All of them remained undistributed. Their value was Rs. 1,89,52,374.50 (Rupees one crore eighty nine lakh fifty two thousand three hundred seventy four and paise fifty) only. They refused to pay even a shell for the residual rice. The situation in Jamui district was equally dismal. The attempt to examine the grains in the godown of Laxmipur failed because the dealer was neither issued coupons nor they showed any stock of grains whereas the book showed that there

was huge quantity of rice with him and the dealer fled away when a test check was to be done by the auditors of C.A.G.

101- Mention must be made about Mr. Shishir Kumar, the then District Engineer Incharge, Vaishali. He had passed orders for lifting of huge volume of rice. He was summoned several times to explain his conduct in the SGRY scheme but he did not turn up. He turned up on the first occasion and prayed for time to explain matters but he never turned up later despite issuance of several reminders. His action also calls for serious inquiry and suitable deterrant action.

102- Mention must also be made about Mr. Navin Kumar Singh, who was BDO, Raja Pakar block in the district of Vaishali between 11/08/2004 to 17/02/2006. On 09/12/2016 he was Deputy Director, Youth Mission, Bihar Vikas Mission. He stated in his representation before this Commission that he never received any information from anyone concerned about rotting or diversion of food grains lying with the PDS dealers. He ordered lifting of huge volume of rice. Ram Balak Rai (deceased) at the time of his death was possessed of 3680.49 quintals of rice. Mr. Navin Kumar Singh took no action as to what happened to the rice and how they disappeared. Nor did Mr. Navin Kumar Singh had any explanation why so much rice was delivered to the dealer without any scheme. That also at the fag end of SGRY. This entailed tones of rice worth Rs 50,42,271/- (Rupees fifty lakh forty two thousand two hundred seventy one) only. This calls for stringent scrutiny and action against Mr. Navin Kumar Singh. At that time Ram Balak Rai, was the Secretary of Primary Agriculture Cooperative Society (PACS)Rajapakar.

103- I have annexed the quantum of loss to the State in several districts. These show that the State Government lost Rs 239,00,79,977.80 (Rupees two hundred thirty nine crore seventy nine thousand nine hundred seventy seven and paise eighty) only as price of residual rice.

104- The State has suffered crores of rupees as indicated above. The loss could have been obviated or minimized if the High Court while restraining the Deptt. from taking coercive action had directed the dealers to deposit the price of residual rice as an interim measure @

Rs 622/- per quintal. The dealers were clamoring that the rice had rotten. That was a matter to be considered. The dealers were also agitating that in any case they should have been called upon to deposit not more than @ Rs 622/- per quintal which was the BPL rate. Till that stage since the dealers were being asked to file their representation before the B.D.O., D.D.C. or Certificate Officer, an interim order for deposit of price at that rate would probably have been more appropriate which they were willing to pay. The stay orders were issued since 2009 and remained pending in the High Court till 2015 because the State Government was not up and doing. Thus the dealers made illegitimate gain. Some orders were passed to deposit 10% or 20% of the demand. That was too low.

105- The Commission was constituted by Government Notification in pursuance of the order passed by Mr Justice M.K. Jha. The Commission commenced with three Members consisting the Chairman assisted by Mr Sanjay Kumar Singh, IAS (Retd) and Mr Arun Kumar Singh, IA&AS (Retd). The High Court had ordered a deep and permissive judicial inquiry into the working of the SGRY. It was however, aborted by the two other Members who relinquished office on 30th June, 2017. As stated earlier, the Chairman conveyed the piquent situation to the Hon'ble Chief Justice who ordered that the Commission will be a one man Commission presided by the Chairman (i.e. myself). Thereafter, the Commission functioned as a single member Commission.

106- The High Court had directed to examine all the dealers 5994 in number vide para-68 of the High Court order and to examine the role of officers in the implementation of SGRY scheme. This task of examining all the dealers in the State of Bihar and examining the conduct of officers was not a matter which could be completed within six months. Mr Sanjay Kumar Singh felt that the High Court was not right in calling upon the Commission to examine all the dealers. The deep and permissive inquiry did not appear to be appropriate. He was therefore of the view that the Commission must conclude its deliberations within six months. This was an impossible task. Anyway, The Commission started functioning by issuing notices and

examining all the dealers of Vaishali as a starter. Later, notices were issued to the dealers in Aurangabad, Rohtas, partly Purnea and partly Patna.

107- It must be stated here and now that the terms of reference mentioned in the Government Notification was "to determine the responsibility for the lapses for the loss food grain and for realization of equal amount of the same after closure of SGRY scheme and National Food for Work schemes. In terms of the notification the Commission was required to deliberate upon realization of amount equivalent to the loss of food grains as well as the responsibility for the lapses for the loss of food grains.

108- During discussion between the Members, Mr Sanjay Kumar Singh was of the view that SDOs, DDCs, Collectors and Commissioners had no role to play and therefore, there was nothing to examine their activity. This attitude of Mr Singh was directly opposed to the purpose of the judicial inquiry laid down by the High Court. The High Court has specifically stated that no useful purpose would be served by deciding the individual writ applications. According to the High Court, the malady in the implementation of the scheme was very deep and officers and dealers were all responsible. The guidelines had enjoined duties upon S.D.Os., D.D.Cs., Collectors and Commissioners in the implementation of the scheme. The State Government also issued directions in accordance with the guidelines. It would therefore, be not right to say that the Commission was not required to question the attitude of Collectors and Commissioners.

109- Since the objective of the order of the High Court and of the State Government was to determine the quantum of loss of food grains and for realization of equivalent amount, it was necessary to determine the rate at which realization of the residual rice was to be effective. I have earlier set out the rate at which realization had to be done and the reasons there for. Since the State Government was not clear in its mind at the initiation of the Commission in regard to the rate of realization, the Commission proceeded to hear the dealers of Vaishali on its own. Learned counsel for the State Mr K.K. Mishra took up

cudgels against the inquiry suggesting that the first duty of the Commission was to determine the rate of realization. This brought about difference between the Chairman and other two Members. Having fixed the rate the Chairman invited the two Members to come to his chamber and discuss the question of the rate. Mr Sanjay Kumar Singh was the D.D.C., Bhojpur, Ara and thus had conflict of interest in hearing of the cases specially the rate of realization. Mr Sanjay Kumar Singh refused to enter into any discussion. His view was that the rate should not be more than APL rate. The two members refused to consider the rate as fixed by the F.C.I. and circulated by the Mr. Santosh Mathew, the then Principal Secretary R.D.D. as also the statement before the full commission by the present Secretary of the R.D.D. Mr. A.K.Choudhary. All of them had insisted only one rate and that was Rs. 1370/- per quintal.

110- On being asked by the Chairman Mr. Sanjay Kumar Singh suppressed the fact that he was D.D.C. Bhojpur(Ara) between 16.12.2006 to 26.10.2007 which was a vital period for the enquiry. After it came to the knowledge of the Chairman some querries were made from Mr. Sanjay Kumar Singh via e-mail. He did not respond and ignored the e-mail. This was ostensibly the reason for Mr. Sanjay Kumar Singh to relinquish office.

111- The C.A.G. too computed rate of the residual rice with PDS dealers at different rates in different cases/ districts. In their report vide Memo No.IC-XX-CL dated 14/03/08 concerning Kaimur district, the price of rice has been noted @ Rs 1310/- per quintal. In the next para of this report, the same rice is shown priced @ Rs 690/- per quintal **(Annexure- 9A &B)**.

In another report vide Memo No.I.C.XXI-19 dated 31/07/08, the price of rice concerning Kaimur district appears to be computed @ Rs 565/- per quintal by the C.A.G.

This might have been the reasons for Mr Arun Kumar Singh (Member) who himself was A.G./ Principal A.G./Dy C.A.G. during the period of reference to relinquish his post and to follow suit of Mr Sanjay Kumar Singh (Member). Both the Members had serious

objection in fixation of the rate of residual rice at Rs 1370/- per quintal.

112- After that as per order of the Patna High Court, this Commission started functioning as a Single Man Commission.

113- While the Commission was functioning as three-Man Commission and hearing individual dealers of Vaishali, all the dealers were directed to deposit 50% of the demand.

114- On one issue there was serious difference between Chairman and the other two Members. The Members were of the view that the licensed PDS dealers had died, no realization should be made from his heirs. In some cases licenses had been granted on compassionate ground to the sons of the dealers. In that case also, the other two Members were of the view that no realization should be made from the successor.

115- In one case the sum of realization from the dealer was not high. In a weak moment the Chairman concurred with the views of the other two Members rather unwillingly. That case was followed by another dealer where the demand was seventeen lakh of rupees. In that case also, the two Members took up the stand that the dealer's heir should not be made to pay for the residual rice. At this stage, I put my foot down and refused to agree to allow the heir to escape without payment. The Chairman's view was that the heir while accepting the benefits of his forbear must also be held liable to meet the liabilities.

116- The other difference between the Members was in regard to the rate at which the price of residual rice was to be realised. On account of these differences the two Members relinquished office as stated earlier. These two Members refused to consider the rate as fixed by the FCI and circulated by Mr Santosh Mathew, the then Principal Secretary, Rural Development Deptt. as also the statement before the full Commission of Mr Arvind Kumar Chaudhary, the present Secretary, Rural Development Deptt. All of them had only one rate and that was Rs 1370/- per quintal of SGRY rice. On report by the Chairman, the High Court by order dated 02/08/2017 ordered that the Commission shall be a one Man Commission presided over by me. The single

Member Commission then took up the work. Since the writ application had to be considered and disposed of, all the petitioners were issued notice to appear before this Commission and file their submissions. Each dealer was informed that the writ application would be heard only if they had paid 50% of the demand. Thus all the petitioners deposited 50% of the demand. Those who did not deposit, their applications were rejected and the DDC and the Certificate Officer were directed to proceed with the certificate proceeding. All the writ petitioners were heard in person or through their counsel. There were 141 writ applications but the number of dealers was 214. This difference in number was because of the fact that in some writ applications there were several petitioners as stated earlier also.

117- All the writ applications were disposed of. The final orders have been placed . on the website of the Rural Development Deptt. (rdd.bih.nic.in). Hard copies of the final orders have been placed in **Volume-II** of this report.

HOW MUCH THE STATE LOOSE :

118- The first duty enjoined upon the Commission by Mr Justice M.K. Jha was to ascertain the quantum of actual loss sustained by the Government. As a colalary to that issue the Governor's Notification called upon the Commission :

> **"(a)** to determine responsibility for the lapses for the loss of food grains and for realization of equivalent amount after the closure of Sampoorna Gramin Rozgar Yojana and National Food for Work Scheme."

119- In short the duty was to find out how much rice was left with as residual which the State Government lost. The price of the residual rice would be the loss sustained by the State of Bihar.

120- It is therefore, necessary to ascertain as to what was the residual rice with the PDS dealers in the whole State of Bihar. This was no mean job. All the District Officers had been directed to get done the audit of the residual rice in all the districts. The District Officers measurably failed in this assessment of the residual rice. The result was that the Principal Additional Advocate General; on the instruction of departmental officers gave different figures of residual rice. The value thereof differed sometimes Rs 321 crores. At some other times at Rs 260 crores and at sometimes Rs 113 crores. That necessitated Mr Justice M.K. Jha to enjoin the Commission to ascertain the actual loss sustained by the Government.

121- In order to discharge the obligation cast upon the Commission in this behalf all District Officers were directed to send audited statement of residual rice. This meant that all the districts were to draw up a chart of the quantum of lifting and distribution which would bring out the balance of the residual rice. Some districts did send the report but several of them defaulted seriously. The district of Katihar sent a statement of dues in 2017. Audit had been effected in that district, as in all districts in 2011 itself but the officers for reasons best known to them failed to comply. In Dhoraiya block in the district of Banka the figure was received in April, 2018. The audit is still going on and final

audit report has not yet been received. The District Magistrate, Gaya was also one of the defaulting officers. He failed to take any action. He got a statement of dues sent only after he was threatened by the Commission that his name would be reported to the Chief Secretary for dereliction of duty if the report was not sent. It appears to me that the District Magistrate, Gaya considered below his dignity to appear before the Commission and explain the matter. His conduct is reprehensible. A duly constituted Judicial Commission is entitled to be treated by the District Officers with respect and expediency.

122- The work of collection of the residual rice from each district (barring Banka) was received in January, 2018. The report of Bank is now available except the audit report. The report on certain points from Bhagalpur is still pending for which the Secretary, Rural Development Deptt. has been reminded.

123- According to the statement sent by the Disrict Officers the residual rice was to the tune 17,44,583.55 quintals. The value thereof @ Rs 1370/- per quintal is Rs 239,00,79,997.80 80 (Rupees two hundred thirty nine crore seventy nine thousand nine hundred seventy seven and paise eight) only. Out of this Rs 22,03,13,835.15 (Rs. Twenty two crore three lakh thirteen thousand eight hundred thirty five and fifteen paise)has been realised leaving a balance of Rs 216,97,66,162.65 . Thus the loss to the State was to the tune of Rupees two hundred sixteen crores ninetyseven lakhs sixtysix thousand one hundred sixtytwo and paise sixtyfive.

124- After the Commission took charge the Commission directed the dealers to deposit 50% of the demand in the light of the order of Mr Justice M.K. Jha. In this process a good sum has been realised but the Commission is not in a position to state the quantum of realization for the reason the district authorities expressed their inability to state the deposits made by the dealers. At the initial state the rate has been calculated at the rate of Rs 1370/- per quintal which I have already decided. A copy of the chart of dues is annexed as **Annexure-10** to this report.

125- In stating the figures mentioned above, I have some difficulty in stating those figures as absolutely correct for the reason that the auditors' role in the audit was not very straight. In the district of Katihar especially the role of auditor Rama Kant Jha & Associates was somewhat suspicious. Mr Rama Kant Jha was called by the Commission to explain some discrepancies but he did not turn up. All the time he sent his clerks who had no compulsion in furnishing tarnished statements. I must state that the heaviest lifting was done in the district of Katihar. The volume of lifting of rice was 4,69,840.42 quintals. According to the official statement 3,09,397.90 was distributed to workers leaving a balance of 160442 quintals which would be equal to 16044 tones, the value thereof would be Rs 21,98,06,252.40. The official statement sent to this Commission during the hearing shows that nothing had been realised. The Collector had repeatedly called upon the dealers to get the balance rice audited. Till 2015 very few of the dealers got their accounts audited. Seven dealers were given ten reminders from 2011 till 2017. They acquiesced in the audit in 2017. The report was received from the auditor Rama Kant Jha while the hearing was going on and on everyday he was used to come with varying figures. I am unable to vouch for the complete correctness of the quantum of residual rice on account of the behavior of the auditor. The delay in audit in several districts enabled the dealers to fabricate delivery coupons and thus cover up their misdeed of selling the rice in the black market. The auditors appeared to be too willing to lend their helping hand to the dealers enabling them to conceal the rice diverted in the black market by showing good quantity of rice distributed to workers obviously on forged coupons. This was the case in Tardih Block of Darbhanga district were a dealer Bhavesh Kumar Bhaskar fuged the account. On the basis of the statement of residual rice sent by the district authorities the total loss to the State of Bihar was Rs 216,97,66,162.65 (Rupees two hundred sixteen crore ninty seven lakh sixty six thousand one hundred sixty two and paise sixty five) only. The State Government was faced with the tough problem. This was not a situation of PDS dealers versus BDOs or Panchayat Secretaries or District Engineers or DDCs but it was a situation of unscrupulous

~~61~~ (60)

officers and PDS dealers hand in gloves mulcting the State surreptitously.

126- (A) The realization in Aurangabad district was creditable. Except two or three dealers, all paid the entire demand calculated @ Rs. 1370/- per quintal.

(B) Despite reminder after reminders, audit report from Banka did not come. The DDC verbally told that no PDS dealer appeared for audit which further proves the fact that the residual rice was sold in black market.

(C) The picture in respect of Kahalgaon and Pirpainti blocks of Bhagalpur was equally dismal. Nothing was realised from the dealers. The DDC kept mum over the action taken on several writs filed in the High Court despite specific orders from the High Court.

(D) The then Programme Officer was responsible for issuing instructions to Chandrama Chaudhary, the PDS dealer of Gopalganj district (Block Hathuwa) vide his Memo No.33 dated 23/01/2010 to deposit the price of residual rice at BPL rate for which he was not authorized.

The above concludes the duties and responsibilities cast upon the Commission.

~~60~~ (61)

127- SUMMARY :

The summary report is as follows :-

When the scheme was closed the dealers were left with 1744583.894 quintals i.e. 174458.389 tones of rice. The value of this is calculated @ Rs 1370/- per quintal which works out at Rs 239,00,79,997.80 80 (Rupees two hundred thirty nine crore seventy nine thousand nine hundred ninty seven and paise eight) only. When the first notification was issued by the State Government, the responsibility cast upon the Commission was to "determine the responsibility for the lapses for the loss of food grains and for realization of equivalent amount of the same after closure of SGRY and National Food for Work Scheme". At that time the Commission was a 3-Man Commission. When the Commission proceeded in its deliberations, one of the Members was not in favour of determining the responsibility for lapses by the Commissioners, Collectors and Sub-Divisional Officers. To cut matter short, they relinquished the Commission as the inquiry could not be completed within six months of the notification although earlier they had eagerly waited for an extension. The calculation of the loss was essential for the reason that the rate of realization had to be found out in order to dispose of the writ applications. In all the writ applications, challenge was to the quantum of realization, value of realization and transportation and handling charges. Thus the duty remained upon one-Man Commission as well. I therefore, calculated the loss in terms of quintals of rice and in terms of crores of rupees.

(63) (62)

THE FINDINGS OF THE COMMISSION ARE AS FOLLOWS :-

128- The State Government lost Rs 239,00,79,997.80 (Rupees two hundred thirty nine crore seventy nine thousand nine hundred ninty seven and paise eight) only. Out of that the State Government realised Rs 22,03,13,835.15 (Rupees twenty two crore three lakh thirteen thousand eight hundred thirty five and paise fifteen) only. Thus the State has still to realize Rs 216,97,66,162.65 (Rupees two hundred sixteen crore ninety seven lakh sixty six thousand one hundred sixty two and paise sixty five) only.

1- The rate of realization has been calculated @ Rs 1370/- per quintal which was the **economic cost of the FCI**.

2- The definite conclusion of the Commission is that the rice had not rotten but had been diverted by the dealers in black market. It is difficult to separate the loss prior to the setting up of the Commission and post functioning of the Commission. This is so because the district authorities are not able to state to the Commission the amount realised when the Commission started functioning.

3- The High Court and the State Government notification had laid the responsibility on the Commission to determine the responsibility for the lapses for loss of food grains. I have already stated earlier that the Sub Divisional Officers,D.D.Cs., Collectors and the Commissioners were lax in their duties in monitoring the SGRY Scheme. I have stated the duties cast upon them in terms of the guidelines of the Central Government and the State Government circular. These have been mentioned in para-69 to 89.

4- The High Court had stated in its judgement that the loss had to be realised not only from the dealers but from the officers as well. Since the inquiry was botched by the relinquishment of the two Members of the Commission and due to subsequent orders of the High Court to convert it into a Single Man Commission, it could not get complete picture of the entire State.

~~65~~ 63

5- It will not be therefore fair for the Commission as to what part should be realised from the officers. In that situation, the entire realization must be effected from the dealers as they were mainly responsible for the embezzelement of rice except those officers who have been indicted by me in para-98, 101 and 102 of this report.

6- While hearing the writ applications, I had the opportunity of considering the cases from the districts of Vaishali, Patna, Munger, Aurangabad, Purnea and Katihar. There were a few cases in the district of Saharsa as well. The Commission has set out the amount which has to be realised from the dealers.

7- The manner of conducting the audit proceeding was also very defective. The auditors were remiss in their functioning in the audit. The heaviest loss was from the district of Katihar. In the district of Munger especially Dharahra block, huge quantity of rice as directed to be released without any scheme.

8- Since there are thousands of Certificate cases pending in different districts, it will be adviseable for the State Government to earmark separate Certificate Officers with empowerment to dispose of pending Certificate cases of SGRY expeditiously.

129- Before closing this report I am inclined to point out some anomalies in the working of the SGRY scheme. According to the guidelines, scheme of work for the full year had to be drawn up and on that basis, rice or cash component had to be released. The impression I got was that the actual working was otherwise. The various letters indicate that the allotment of rice to the dealers preceded the calculation of full scheme for the year. The result was plethora of rice with the dealers through SFC. In the absence of considered scheme of work, the rice with the dealers started disappearing. When there was no scheme or inadequate scheme, naturally would be sold by the dealer. In my view it would not be apt to assume that the rice had deteriorated. If the schemes were imperfect and the dealers were loaded with grains, the result naturally would be flow of rice in the black market. There is yet another aspect of the matter. The idea was to provide employment

with wages to workmen. There is yet another aspect of the matter. I would like to draw the attention of the Government. Every workman was supposed to be issued a Red Card and that person is to be described as BPL Card Holder. The scheme was that every card holder would be supplied 30 kg of rice per month at BPL rate as the case may be. A family with two adult sons would be entitled to separate BPL card and thereby getting separate receipt of rice. That would result in overloading of BPL card holders. So much of rice cannot be consumed by them. The result would be sale of rice by the card holder himself. Further if the BPL card holder was given so much of rice, would he take up the spade and go to work. Why would he work at that stage ? This situation would create of a group of persons who need not work at all. That is why there isthe shortage of labourers in the villages.

Conclusion :

After going through the whole gamut of inquiry, it transpired to me that people friendly and poverty alleviation schemes such as SGRY, NREGA, FFWP etc are started with a bang but due to tardy implementation and poor supervision, all these end up with a whimper resulting into serious complaints against officials as well as non-officials. This is also due to the fact that the BDOs/SDOs/DDCs/DMs/Divisional Commissioners are pestered with non-developmental activities throughout the year viz; Panchayat/Municipal/Assembly/Parliamentary elections and bye-elections besides law and order prolems which takes much of their time. The Government only rises to the occasion when hue and cry over misdeeds are raised after audit or through other agencies and then bigger scandals like the pilferage into black market of SGRY rice comes to the fore but then due to excessive delays little could be done. So, the only way to prevent such large scale loot of public fund is to nip it in the bud during early implementation of such big schemes through regular inspection/supervision by senior officers. The State Government's endeavour to book the culprits too gets thwarted by unscrupulous and corrupt elements both inside and outside the administration which happened in the case of residual rice left with the PDS dealers who got relief from Courts. The follow up action for realization of the price is limited to certificate cases only for which extra and exclusive certificate courts need to be empowered. There is another angle to the problem. The corrupt elements (PDS dealers in the instant case) move the High Court to get stay against the action of the State apparatus and the State Government does not follow up such stay orders to get vacated. This gives time to the wrong doers and their cohorts to usurp the booty of their loot without being punished. A regular review of such cases at all levels is a dire necessity. This Commission within its limited scope has recommended deterrant action in certain cases which may be taken by the State Government.

(66)

I am obliged to Shri Shashi Bhushan Verma, retired Joint Secretary and Secretary of this Commission and Md Shamim Anwar, Personal Assistant working with me. Without their unnstinted cooperation, I could not have been able to discharge my obligation.

I am also specially grateful to Mr Binodji Verma and Mr Arup Kumar Chongdar, Special Public Prosecutors for the Commission who gave full support to me. The office staff viz; Mr Umakant Das, Atkas Bara, Manoj Jayshankar (computer operator), Rajesh Pandit (Computer operator) as well as class IV employees of this Commission were also very helpful to me. I wish them all success.

Mr K.K. Mishra, Counsel of the Rural Development Deptt., Mr Sanjay Kumar Singh, Joint Secretary-cum-Nodal Officer, Rural Development Deptt. and Mr Arvind Kumar Chaudhary, IAS, Secretary, Rural Development Deptt. deserve thanks for their cooperation in the establishment and running of the Commission and subsequent completion of the inquiry by this Commission.

Justice Uday Sinha,
Chairman,
Justice Uday Sinha Judicial
Inquiry Commission.
Patna,

Dated the May, 2018.

~~66~~ 67

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना (वर्ष 2002-2006) में बरती गयी अनियमितता के फलस्वरूप सरकार को हुई वित्तीय क्षति के ऑकलन एवं जिम्मेवारी तय करने के लिए गठित न्यायमूर्ति उदय सिन्हा न्यायिक जॉच आयोग से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन

पर

कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR)

(68)

कृत कार्रवाई प्रतिवेदन

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत उठाव किये गये खाद्यान्न के अवशेष अंश की वसूली एवं उसकी क्षति के लिए दायित्व का निर्धारण हेतु गठित न्यायमूर्ति उदय सिन्हा न्यायिक जाँच आयोग की अनुशंसा पर कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन ।

क्र0सं0	मंतव्य/अनुशंसा	कृत कार्रवाई
1.	आयोग द्वारा प्रतिवेदित है कि चावल सड़ा नहीं बल्कि डीलर के द्वारा काला बाजार में बेच दिया गया। राज्य सरकार को 239.0079998/-(दो सौ उन्नचालिस करोड़ उन्नासी हजार नौ सौ अन्ठानवे रुपये) की क्षति हुई । जिसमें 22.0313835/-(बाईस करोड तीन लाख तेरह हजार आठ सौ पैंतीस रुपये) की वसूली हो चुकी है तथा 216.9766163/-(दो सौ सोलह करोड़ सन्तानवे लाख छियासठ हजार एक सौ तिरसठ रुपये) की वसूली की जानी है । आयोग के द्वारा कंडिका-128(5) में उल्लेख किया गया है कि क्षति की सम्पूर्ण राशि डीलर से वसूल किया जाना चाहिए क्योंकि गबन के लिए वे ही उत्तरदायी हैं। आयोग के द्वारा वसूली का दर 1370 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया । प्रतिवेदन की कंडिका-64 में 13 रुपये प्रति क्विंटल की दर से परिचालन एवं हथालन हेतु राशि भुगतान की अनुशंसा आयोग द्वारा की गई है।	सभी जिला पदाधिकारी को आयोग के निष्कर्ष से अवगत कराया गया और उन्हें निदेश दिया गया कि 1370/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से राशि की वसूली करें तथा वसूली गयी राशि में 13 रुपये प्रति क्विंटल परिचालन एवं हथालन हेतु राशि का समायोजन करें।
2.	तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला पदाधिकारी तथा आयुक्त स्तर पर अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता बरती	उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, समाहर्ता एवं आयुक्त के कर्तव्य के प्रति

(69)

	गई है। कंडिका-72 में स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा निर्गत पत्र पत्रांक- ग्रा0वि0-8/क-37/2001- 6981 दिनांक- 28.05.2002 के द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त / जिला पदाधिकारी / प्रमण्डलीय आयुक्त को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) के क्रियान्वयन /निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया था। परन्तु आयोग द्वारा पाया गया कि इसका अनुपालन तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला पदाधिकारी तथा आयुक्त के द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया।	चूक के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को संसूचित किया गया ।
3.	कंडिका-81 में अंकेक्षण प्रक्रिया को भी काफी दोषपूर्ण बतलाया है । अंकेक्षक रामाकान्त झा के विरूद्ध भी विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है ।	अंकेक्षक श्री रामाकान्त झा, (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) के विरूद्ध विभाग के स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।
4.	कंडिका-128(8) में आयोग का सुझाव है कि प्रत्येक जिला में निलाम पत्र वाद पदाधिकारियों को राशि की वसूली हेतु कर्णांकित किया जाय ।	सभी जिला पदाधिकारी को छः माह के अन्तर्गत निलाम पत्र वाद की प्रक्रिया को पूर्ण करा कर सरकार को हुई राशि की क्षति को शीघ्र वसूली करने का निदेश दिया गया। साथ ही निलाम पत्र वाद की प्रक्रिया में जिले के सभी आपूर्ति निरीक्षक एवं विपणन पदाधिकारी की सेवा लेने का भी निदेश उन्हें दिया गया।

(70)

5.	कंडिका-87 में यह उल्लेख है कि श्री उपेन्द्र कुमार, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, मुंगेर, द्वारा दिनांक 30.05.2005 से दिनांक 31.12.2006 के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारियों को चावल के उठाव का निदेश दिया गया है । उनके निदेश के आलोक में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारियों के द्वारा 97936211.65/- (नौ करोड उन्नासी लाख छतीस हजार दो सौ ग्यारह रूपया एवं पैंसठ पैसा) की राशि का विचलन किया गया । सरकार को हुई इस राशि की छति के लिए श्री उपेन्द्र कुमार, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, मुंगेर, को आयोग के द्वारा दोषी पाया गया ।	तत्कालीन उप विकास आयुक्त , मुंगेर श्री उपेन्द्र कुमार, के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को संसूचित किया गया ।
6.	कंडिका-86 में यह प्रतिवेदित किया गया है कि श्री एम0के0 अग्रवाल, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा, के द्वारा 231 क्विंटल चावल का उठाव कर उसे बाँटने का कूपन निर्गत नहीं किया गया । अतः कंडिका-94 में 231 क्विंटल चावल के समतुल्य राशि की क्षति के लिए श्री अग्रवाल को आयोग के द्वारा दोषी पाया गया एवं उनके विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई।	तत्कालीन श्री एम0के0 अग्रवाल, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धरहरा के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को संसूचित किया गया।
7.	कंडिका-102 में श्री नवीन कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजापाकड़, वैशाली को अत्यधिक मात्रा में चावल के उठाव का निदेश दिया गया। आयोग के द्वारा यह भी पाया गया की उठाये गये चावल की कुल किमत 5042272/-(पचास लाख बियालीस हजार दो सौ बहत्तर रूपये) था । उठाव के बाद चावल को बाटा नहीं गया जिसके लिए आयोग के द्वारा श्री सिंह को दोषी पाया गया तथा इनके	तत्कालीन श्री नवीन कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजापाकड़, वैशाली के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को संसूचित किया गया ।

(71)

	विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।	
8.	कंडिका-101 में तत्कालीन जिला अभियंता, वैशाली श्री शिशिर कुमार के द्वारा अत्यधिक मात्रा में चावल के उठाव का आदेश दिया गया । आयोग के द्वारा वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने के लिए उन्हें कई बार सम्मन भेजा गया किन्तु उनके द्वारा आयोग के समक्ष उपस्थित होकर वस्तुस्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया । अतः आयोग के द्वारा उनके कार्यकलाप की गहन जाँच कर उनके विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।	श्री शिशिर कुमार, तत्कालीन जिला अभियंता, वैशाली के विरूद्ध कार्रवाई हेतु पंचायती राज विभाग को संसूचित किया गया।

षोडश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-07 बुधवार, दिनांक- 20 फरवरी, 2019 ई० ।

मानानीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.04 बजे पूर्वाह्न तक ।

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से बार-बार अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने स्थान पर जाए एवं प्रश्नकाल को चलने दें । यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो सभा की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

किन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 04.45 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[1] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना (वर्ष 2002-2006) में बरती गयी अनियमित्ता के फलस्वरूप सरकार को हुई वित्तीय क्षति के आकलन एवं जिम्मेवारी तय करने के लिए गठित न्यायिक जाँच आयोग का जाँच प्रतिवेदन तथा जाँच प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) की एक-एक प्रति को सभा पटल पर रखा गया ।

[2] **याचिकाओं का उपस्थापन :-**

सभा सचिव द्वारा सदन के लिए स्वीकृत कुल 96 याचिकाओं का उपस्थापन सदन में किया गया ।

74 73

- 8 -

285

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 1587145 पटना, दिनांक 17/02/2020

पेषक

संजय कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

निदेशक,
बिहार विधान सभा (लोक-लेखा समिति) सचिवालय, पटना ।

विषय :- बिहार विधान सभा की लोक-लेखा समिति की उप समिति- (4) की बैठक के संबंध में ।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 62 दिनांक 27.01.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग में बिहार विधान सभा की लोक-लेखा समिति की उप समिति- (4) की दिनांक 20.02.2020 को 12:00 बजे मध्याह्न में आयोजित बैठक से संबंधित सी०ए०जी० की संसूचित लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन 10 (दस) प्रतियों में संलग्न है।

अनु० - यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

बिहार विधान सभा सचिवालय
प्राप्ति तिथि: 19.02.2020
केन्द्रीय डाक सं०: 1841

~~25~~ 74

457745/19.02.2020

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक- 20.02.2020 को बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति की उप समिति (4) की बैठक से संबंधित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन

क्र0 सं0	कंडिका / वर्ष / जिला	प्रश्न	उत्तर
1	2.1.5 (2008-09) (सिविल)	मामला संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत दो घटक यथा रोकड़ घटक एवं खाद्यान्न चावल घटक में SGRY फरवरी 2006 में बंद होने के पश्चात भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जून 2006 तक योजना में बचे खाद्यान्न मात्रा का उपयोग करने की अनुमति के बावजूद निर्देश का उल्लंघन कर अप्रैल 2008 तक भी खाद्यान्न का उपयोग न कर सकने एवं इसकी वसूली ए0पी0एल0 मूल्य पर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारो के पास अवशेष खाद्यान्न के वसूली न होने से संबंधित है ।	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के बंद होने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न की क्षति एवं उसके समतुल्य राशि की वसूली के दायित्व के निर्धारण के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या- 19529/2011 सदानन्द यादव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा अन्य बैच वादों में दिनांक 21/09/2015 को पारित आदेश में न्यायिक आयोग के गठन का निर्देश दिया गया है । उक्त आदेश के अनुपालन में अधिसूचना क्रमांक- 258459 दिनांक- 18/01/2016 के द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री उदय सिंन्हा (सेवा निवृत) के अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है । आयोग के द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन सरकार को समर्पित कर दिया गया है । प्रतिवेदन के आलोक में विभाग द्वारा सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को निम्नांकित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है :- 1. अपने जिले में एस0जी0आर0वाई0 योजना के गबन किये गये चावल की मात्रा के समतुल्य राशि की वसूली रू0 1370/- प्रति क्विन्टल की दर से डीलर से करना सुनिश्चित करेंगे । राशि की वसूली में रू0 13/- प्रति क्विन्टल की दर से परिचालन एवं हयातन हेतु राशि का समायोजन सुनिश्चित करेंगे । 2. आयोग के सुझाव के आलोक में जिला में नीलाम पत्र पदाधिकारियों को

~~36~~ 75

			कर्णांकित कर प्रतिमाह वसूली की प्रक्रिया एवं वसूली की समीक्षाकर तत्संबंधी प्रतिवेदन से विभाग को अगवत कराना सुनिश्चित करेंगे । चूकिं इस संबंध में विभाग द्वारा राशि वसूली एवं संबंधित दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जा रहीं है। अतअनुरोध है कि इ :स कंडिका को ग्रामीण विकास विभाग की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय ।
~~2~~	2.4.6.1 (3 बुलेट), 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.6.4, 2.4.7 (3 बुलेट), 2.4.8.1, 2.4.8.2, 2.4.9.1, 2.4.9.2, 2.4.9.3, 2.4.9.4, 2.4.9.5, 2.4.9.6, 2.4.9.7, 2.4.9.8 'क', 2.4.9.9, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.12 एवं 2.4.12.1 (2013-14)	बिहार राज्य में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान / निर्मल भारत अभियान से संबंधित ।	यह कंडिका लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा इस विभाग को हस्तांतरण से प्राप्त हुई है। इन कंडिकाओं के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ की यह कंडिका 2013-14 की है एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान एवं निर्मल भारत अभियान में हुई अनियमितता से संबंधित है । सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान एवं निर्मल भारत अभियान का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाता था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या- 741 दिनांक 01.06.2016 द्वारा बिहार के शौचालय विहिन परिवारों को लाभार्थी द्वारा घरेलु शौचालय का निर्माण एवं नियमित उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित योजना "स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)" एवं राज्य संपोषित योजना "लोहिया स्वच्छता अभियान" के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित किया गया है। चुंकि यह कंडिका वर्ष 2013-14 का है एवं सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान एवं निर्मल भारत अभियान से संबंधित है फलस्वरूप इन कंडिकाओं को विभागीय पत्रांक 439143 दिनांक 02.09.2019 द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को हस्तांतरित कर दिया गया है । **अनु0- (i)**

बिहार विधान-सभा सचिवालय

पत्र संख्या-2लो0ले0स0-30/20- /वि०स०।

प्रेषक,

भूदेव राय,
निदेशक,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- जून, 2020 ई० ।

विषय:- लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-704 में सन्निहित आँकड़ों के सम्परीक्षण के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष-2008-09 (सिविल) की कंडिका-2.1.5 पर लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-704 को समिति द्वारा दिनांक-04.06.2020 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है ।

अत: पारित प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि प्रारूप प्रतिवेदन में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण कर प्रतिवेदन प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर समिति द्वारा पारित प्रतिवेदन की मूल प्रति सभा सचिवालय को वापस करने की कृपा की जाय । पत्र प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर प्रारूप प्रतिवेदन वापस नहीं होने पर यह समझा जायेगा की इसमें निहित आँकड़े सही हैं ।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(भूदेव राय)
निदेशक,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

ज्ञापांक-2लो0ले0स0-30/20- 538 /वि०स०, पटना, दिनांक- 24 जून, 2020 ई० ।

प्रति:-प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/6/20
(भूदेव राय)
निदेशक,
बिहार विधान-सभा, पटना ।
23/6/20

(07)

संख्या/No. लो० ले० स०/प्रा० प्र०/20-21/478/20

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना–800 001
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit) Bihar
Birchand Patel Marg, Patna-800 001

दिनांक/Date : 06.07.2020

सेवा में,

निदेशक,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना–800 001

विषयः– बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन संख्या–704 में सन्निहित तथ्यों एवं आँकड़ो का सम्परीक्षण के संबंध में।

प्रसंगः– बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्र सं0–2लो0ले0स0–30 / 20–538 / वि0स0, दिनांक–23.06.2020.

महाशय,

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों मे सन्निहित कंडिकाओं पर आपके द्वारा प्रेषित लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या–704 को मूल रूप में वापस करते हुए सूचित करना है कि उक्त प्रारूप प्रतिवेदन में सन्निहित तथ्यों एवं आँकड़ो का सम्परीक्षण किया गया तथा उनमें सन्निहित तथ्यों एवं आँकड़ों में आवश्यक आंशिक संशोधन किया गया है एवं अन्य तथ्यों एवं आँकड़ों को सही पाया गया।

भवदीय,

अनुलग्नकः– यथोपरि।

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी,
लोक लेखा समिति।

दूरभाष/Phone - 2221226, 2506091, 2223194, 2221941, 2223725, 2506283 ई.पी.ए.बी.एक्स./EPABX-2223757
फैक्स/Fax : 0612-250 6223,2506174 ई.मेल/E-mail- agaubihar@cag.gov.in, पो० बॉक्स/P.B.No.- 47

बिहार विधान-सभा सचिवालय

पत्र संख्या-2लो0ले0स0-30/20- /वि०स०।

प्रेषक,

स्मार पत्र

अनुपमा प्रसाद,
अवर सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- अगस्त, 2020 ई० ।

विषय:- लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-704 में सन्निहित आँकड़ों के सम्परीक्षण के संबंध में ।

प्रसंग:- सभा सचिवालय के पत्रांक-538, दिनांक-24.06.2020 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में निदेशानुसार सूचित करना है कि लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-704 में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण करने हेतु सभा सचिवालय के पत्रांक-538 दिनांक-24.06.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विभाग को भेजा गया था जिसमें यह उल्लेखित था कि आँकड़ों का सम्परीक्षण कर इसकी मूल प्रति 15 दिनों के अंदर सभा सचिवालय को वापस की जाय परंतु एक माह का समय बीत चुका है और अबतक प्रारूप प्रतिवेदन में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण कर इसकी मूल प्रति सभा सचिवालय को वापस नहीं किया गया है।

अत: आपसे अनुरोध है कि प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-704 में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण कर इसकी मूल प्रति सभा सचिवालय को सात दिनों के अंदर वापस की जाय । यदि प्रारूप प्रतिवेदन का सम्परीक्षण कर इसकी मूल प्रति इस अवधि के अंदर वापस नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि इसमें सन्निहित आँकड़े सही हैं एवं इसके उपरांत सभा सचिवालय द्वारा प्रतिवेदन उपस्थापन संबंधी अग्रतर कार्रवाई कर ली जायेगी ।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(अनुपमा प्रसाद)
अवर सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

ज्ञापांक-2लो0ले0स0-30/20- 590 /वि०स०, पटना, दिनांक- 10 अगस्त, 2020 ई० ।

प्रति:-प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

10.8.20

(अनुपमा प्रसाद)
अवर सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

10/8/20

प्रकाशन संख्या –717

बिहार विधान सभा

की

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) संख्या –706

ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सं0–506, 529 एवं 533 में सन्निहित समिति के अनुशंसाओं पर कार्यान्वयन प्रतिवेदन ।

(दिनांक – **05 मार्च 2021** को सदन में उपस्थापित)।

विषय–सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	1 अप्रील 2020 से षोडश बिहार विधान सभा की शेष अवधि तक के लिए गठित लोक लेखा समिति ।	क
2.	लोक लेखा समिति (मुख्य) का गठन वर्ष 2018–20 ।	ख
3.	लोक लेखा समिति की कार्यान्वयन उप समिति का गठन वर्ष 2018–20 ।	ग
4.	सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण, वित्त विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारीगण।	घ
5.	प्राक्कथन	च
6.	प्रतिवेदन	1–13
7.	परिशिष्ट	14–56

क

बिहार विधान सभा सचिवालय

1 अप्रील, 2020 से षोडश बिहार विधान सभा की शेष अवधि तक के लिए गठित लोक लेखा समिति ।

सभापति

1. **श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी,** **स०वि०स०,**

सदस्यगण

1. श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०,
2. श्री विजय शंकर दूबे, स०वि०स०,
3. श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव, स०वि०स०,
4. श्री अवधेश कुमार सिंह, स०वि०स०,
5. श्रीमती प्रेमा चौधरी, स०वि०स०,
6. श्री रवीन्द्र सिंह, स०वि०स०,
7. श्री अजीत शर्मा, स०वि०स०,
8. श्री भोला यादव, स०वि०स०,
9. श्री मेवालाल चौधरी, स०वि०स०,
10. श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, स0वि0स0
11. श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0
12. श्री मनीष कुमार, स0वि0स0,

ख

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति गठन वर्ष 2018–20 (षोडश बिहार विधान सभा)

सभापति

1. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स०,

सदस्यगण

1.	श्री ललित कुमार यादव,	स०वि०स०,
2.	श्री विजय शंकर दूबे,	स०वि०स०,
3.	श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव,	स०वि०स०,
4.	श्री अवधेश कुमार सिंह,	स०वि०स०,
5.	श्रीमती प्रेमा चौधरी,	स०वि०स०,
6.	श्री रवीन्द्र सिंह,	स०वि०स०,
7.	श्री अजीत शर्मा,	स०वि०स०,
8.	श्री भोला यादव,	स०वि०स०,
9.	श्री मेवालाल चौधरी,	स०वि०स०,
10.	श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव,	स0वि0स0
11.	श्री विजय कुमार खेमका,	स0वि0स0
12.	श्री मनीष कुमार,	स0वि0स0
13.	श्री मनोज यादव,	स0वि0प0,
14.	डॉ0 रामवचन राय,	स0वि0प0,

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति की कार्यान्वयन उप समिति का गठन वर्ष 2018–20

सभापति

1. श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, स0वि0स0,

सदस्यगण

1. श्री ललित कुमार यादव, स0वि0स0,
2. श्री विजय शंकर दूबे स0वि0स0,
3. श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव स0वि0स0,
4. श्री विजय कुमार खेमका स0वि0स0,

घ

बिहार विधान सभा सचिवालय

1.	श्री बटेश्वर नाथ पाण्डेय	सचिव
2.	श्री भूदेव राय	निदेशक
3.	श्रीमती अनुपमा प्रसाद	अवर–सचिव
4.	श्री उमा शंकर यादव	प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्री राजीव रंजन–2	सहायक
6.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह	सहायक
7.	श्री अरबिन्द कुमार दास	सहायक
8.	सुश्री कंचन कुमारी	सहायक
9.	श्री अमित कुमार झा	सहायक
10.	श्री बिट्टू शर्मा	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर

वित्त विभाग

1.	श्री एस सिद्धार्थ	प्रधान सचिव
2.	श्री ओम प्रकाश झा	अपर सचिव

ग्रामीण कार्य विभाग

1.	श्री विनय कुमार	सचिव
2.	श्री प्रवीण कुमार ठाकुर	अभियंता प्रमुख
3.	श्री सुनील कुमार	अधीक्षण अभियंता
4.	श्री नलिन कुमार सिन्हा	नोडल पदाधिकारी

प्राक्कथन

मैं सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से प्रतिवेदन संख्या–506, 529 एवं 533 (ग्रामीण कार्य विभाग) में निहित समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) संख्या–**706** प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक–**12 जून, 2020** को लोक लेखा समिति (मुख्य) की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है ।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में वित्त विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने परिश्रम से समिति को जो सहयोग दिया है, वह सराहनीय है । इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

समिति के माननीय सदस्यगणों ने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग प्रदान किया है, मैं उनका आभारी हूँ, और इस कार्य हेतु मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ ।

अब्दुल बारी सिद्दिकी
सभापति,
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा ।

पटना ।

दिनांक–12 जून, 2020 (ई0)।

प्रतिवेदन

ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित सी०ए०जी० की आपत्तियों पर

समिति का प्रतिवेदन संख्या-506

(दिनांक-01 अगस्त, 2013 को सदन में उपस्थापित)

में दर्ज अनुशंसाओं का कार्यान्वयन ।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या-506 (ग्रामीण कार्य विभाग) में निहित अनुशंसाओं पर समिति का कार्यान्वयन प्रतिवेदन ।

1. वर्ष 1996-97 (सिविल) की कंडिका सं0-4.21 अनुशंसा पृ0स0-06

समिति की अनुशंसा

दिनांक-19 दिसंबर, 2012 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय जवाब के आलोक में विभागीय आश्वासन के बाद कि भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होगी इस कंडिका को निष्पादित किया गया ।

कार्यान्वयन की स्थिति

पत्रांक-138, दिनांक-02.01.2018 द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता को समिति के अनुशंसा के आलोक में निदेश दिया गया है कि भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो, इसका ध्यान रखा जाय ।

समिति का निर्णय

दिनांक-20.02.2020 की कार्यान्वयन उप समिति की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में उक्त अनुशंसा को कार्यान्वित माना गया ।

पटना ।

दिनांक-12 जून, 2020 (ई0)।

अब्दुल बारी सिद्दिकी
सभापति,
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा ।

2. वर्ष 1998-99 (सिविल) की कंडिका सं0-4.18 अनुशंसा पृ0स0-09

समिति की अनुशंसा

दिनांक-7 जुलाई, 2011 की बैठक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि बचे हुए सामग्री को विभाग स्टोर पंजी में इन्ट्री करें, जहाँ कहीं भी इस तरह का पुल बने, वहाँ इस मैटेरियल को लगाया जाय और इसमें जो तकनीकी चूक हुई है, भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं हो । इस कंडिका को निष्पादित किया गया ।

कार्यान्वयन की स्थिति

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल झंझारपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है इस प्रमंडल अन्तर्गत झंझारपुर से अंधराठारी पथ में अधूरे पड़े स्क्रु पाईल पुल की सामग्री जो स्थल पर लगा हुआ है, को सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य अवर प्रमंडल, अंधराठारी के स्टोर पंजी में दर्ज करा दी गयी है ।

विभागीय पत्रांक-2790 दिनांक-06.03.2017 (प्रति संलग्न) के द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है कि भविष्य में जहाँ भी इस प्रकार के पुल का निर्माण/मरम्मति का कार्य हो तो कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर से स्क्रु पाईल पुल से संबंधित आवश्यकतानुसार आवश्यक अवयव प्राप्त कर इसका उपयोग किया गया ।

समिति का निर्णय

दिनांक-20.02.2020 की कार्यान्वयन उप समिति की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में उक्त अनुशंसा को कार्यान्वित माना गया ।

पटना ।

दिनांक-12 जून, 2020 (ई0)।

अब्दुल बारी सिद्दिकी
सभापति,
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा ।

3. वर्ष 2005-06 (सिविल) की कंडिका सं0-4.2.4 अनुशंसा पृ0स0-12

समिति की अनुशंसा

(अ) दिनांक-7 जुलाई, 2011 की बैठक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि शेष बची हुई राशि की वसूली कर शीघ्र समिति को अवगत कराये, निष्पादित किया गया ।

(ब) दिनांक-7 जुलाई, 2011 की बैठक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि शेष बची हुई राशि की वसूली की दिशा में कार्रवाई कर विभाग समिति को सूचित करें, इस कंडिका को निष्पादित किया गया ।

कार्यान्वयन की स्थिति

(अ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल सुपौल ने अपने पत्रांक-854(अनु0) दिनांक-16.08.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मेसर्स कार्तिक कुमार, गंगा जल सहरसा, के विरूद्ध कुल 6834035/-रू0 वसूली हेतु सर्टिफिकेट केश जिला नीलाम पदाधिकारी, सुपौल के समक्ष दायर की गयी है। जिसका केश संख्या-27/2017-18 ।

(ब) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल सहरसा ने अपने पत्रांक-47 अनु0 दिनांक-12.01.2018 प्रतिवेदित किया है कि संवेदक शिवकृष्ण बिल्डर्स प्रा0लि0 बैजनाथपुर, सहरसा से कुल 5728843.00/-रू0 की वसूलनीय थी, जिसमें से विभाग पर पूर्व से संवेदक का 4811729.00/- रू0 जमा था । शेष राशि 917114/-रू0 का चेक के माध्यम से संवेदक द्वारा कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल सहरसा को समर्पित किया गया है ।

समिति का निर्णय

दिनांक-20.02.2020 की कार्यान्वयन उप समिति की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में उक्त अनुशंसा को कार्यान्वित माना गया ।

पटना ।

दिनांक-12 जून, 2020 (ई0)।

अब्दुल बारी सिद्दिकी
सभापति,
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा ।

4. वर्ष 2007-08 (सिविल) की कंडिका सं0-4.1.5 अनुशंसा पृ0स0-14

समिति की अनुशंसा

दिनांक-17 फरवरी, 2012 की बैठक में समिति द्वारा महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति से इस निदेश के साथ कि भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं हो, इस कंडिका को विलोपित किया गया ।

कार्यान्वयन की स्थिति

विभागीय पत्रांक-139 दिनांक-02.01.2018 द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता को समिति के अनुशंसा के आलोक में निदेश दिया गया है कि भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो इसका ध्यान रखा जाय ।

इस प्रकार विभाग द्वारा समिति के अनुशंसा के अनुपालन किया जा चुका है ।

समिति का निर्णय

दिनांक-20.02.2020 की कार्यान्वयन उप समिति की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में उक्त अनुशंसा को कार्यान्वित माना गया ।

पटना ।

दिनांक-12 जून, 2020 (ई0)।

अब्दुल बारी सिद्दिकी
सभापति,
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा ।

5. वर्ष 2008-09 (सिविल) की कंडिका सं0-2.1.6 अनुशंसा पृ0स0-18

समिति की अनुशंसा

दिनांक-17 फरवरी, 2012 की बैठक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति न हो, वित्त विभाग और प्रधान महालेखाकार की सहमति से इस कंडिका को निष्पादित किया गया ।

कार्यान्वयन की स्थिति

समिति के अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-137 दिनांक-02.01.2018 द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो, इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया। एतद् संबंधी कार्यान्वयन प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक-1095 अनु0 दिनांक-29.01.2018 द्वारा विधान सभा सचिवालय, महालेखाकार कार्यपालक, बिहार, पटना एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित किया गया । उक्त अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में महालेखाकार कार्यपालक, बिहार, पटना द्वारा अपने पत्रांक-लो0ले0स0/ ग्रा0का0वि0/ए0टी0एन0/18-19/88B/08 द्वारा उपलब्ध कराये गये सम्परीक्षण टिप्पणी अंकित किया गया है कि विभागीय निदेश निर्गत होने के कारण सम्परीक्षण टिप्पणी अपेक्षित नहीं है ।

विभागीय पत्रांक-985, दिनांक-13-02-2020 से संबंधित अनुलग्नक परिशिष्ट पृष्ठ सं०-14 से 31 पर द्रष्टव्य ।

समिति का निर्णय

दिनांक-20.02.2020 की कार्यान्वयन उप समिति की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में उक्त अनुशंसा को कार्यान्वित माना गया ।

पटना ।

दिनांक-12 जून, 2020 (ई0)।

अब्दुल बारी सिद्दिकी
सभापति,
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा ।

ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित सी०ए०जी०

की आपत्तियों पर

समिति का प्रतिवेदन संख्या-529

(दिनांक-19 फरवरी, 2014 को सदन में उपस्थापित)

में दर्ज अनुशंसाओं का कार्यान्वयन ।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या-529 (ग्रामीण कार्य विभाग) में निहित अनुशंसाओं पर समिति का कार्यान्वयन प्रतिवेदन ।

1. वर्ष 2011-12 (सिविल) की कंडिका सं0-5.1.1 अनुशंसा पृ0स0-04

समिति की अनुशंसा

समिति द्वारा दिनांक-9 अक्टूबर, 2013 की बैठक में महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति से इस कंडिका को इस निदेश के साथ निष्पादित किया गया कि भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति न हो ।

कार्यान्वयन की स्थिति

समिति के अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-169 दिनांक-03.01.2018 द्वारा सभी संबंधित को भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो, इसके संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है । उक्त के आलोक में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना के पत्रांक-लो0ले0स0/ग्रा0का0वि0/ए0टी0एन0/16-17/88B, दिनांक-05.02.2018 द्वारा सम्परीक्षण टिप्पणी दर्ज कर उपलब्ध कराया गया है। उक्त सम्परीक्षण टिप्पणी में उल्लेख किया गया है कि समिति के अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया गया है तथा समिति द्वारा कंडिका को निष्पादित किया जा चुका है ।

इस प्रकार विभाग समिति के द्वारा किये गये अनुशंसा का पूर्णरूप से अनुपालन कर लिया गया है ।

विभागीय पत्रांक-985, दिनांक-13-02-2020 से संबंधित अनुलग्नक परिशिष्ट पृष्ठ सं०-14 एवं 32 से 35 पर द्रष्टव्य ।

समिति का निर्णय

दिनांक-20.02.2020 की कार्यान्वयन उप समिति की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में उक्त अनुशंसा को कार्यान्वित माना गया ।

पटना ।

दिनांक-12 जून, 2020 (ई0)।

अब्दुल बारी सिद्दिकी
सभापति,
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा ।

2. वर्ष 2011-12 (सिविल) की कंडिका सं0-5.2.2 अनुशंसा पृ0स0-06

समिति की अनुशंसा

समिति द्वारा दिनांक-9 अक्टूबर, 2013 की बैठक में इस कंडिका को इस निदेश के साथ निष्पादित किया गया कि भविष्य में जब भी इस तरह के कंसलटेंट बहाल किये जाये तो विभाग द्वारा उसके कार्य का प्रोपर मोनिटरिंग हो एवं पुल का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाय ।

कार्यान्वयन की स्थिति

समिति के अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-6820 अनु0 दिनांक-20.06.2018 द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन बिहार विधान सभा सचिवालय, महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग, बिहार पटना को प्रेषित की गयी थी जिसके आलोक में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा अपने पत्रांक-लो0ले0स0/ग्रा0का0वि0/ए0टी0एन0/18-19/88B दिनांक-10.08.2018 द्वारा अंतिम रूप से सम्परीक्षण टिप्पणी उपलब्ध कराया गया है । उक्त सम्परीक्षण टिप्पणी में प्रतिवेदित है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य प्रमंडल औरंगाबाद के अन्तर्गत रफीगंज से बलिगांव पथ के बीच में नदी के चैनलों में दो पूलो का निर्माण नहीं किया गया । इसके कारण रफीगंज से बलिगाँव पथ पर अवस्थित सभी बसावटों को बारहमासी सम्पर्कता नहीं प्रदान किये जाने संबंधी आपत्ति की गयी थी । उक्त आपत्ति के आलोक में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये नजरी नक्शा के अनुसार नदी के दोनों चैनल पर पुल का निर्माण किया जा चुका है । पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत अन्य सड़कों के माध्यम से भी आपत्ति बसावटों की सड़क सम्पर्कता बहाल कर दी गयी है। उपरोक्त के आलोक में महालेखाकार कार्यालय द्वारा उक्त कंडिका को अंतिम रूप से निष्पादित करने हेतु समिति से अनुशंसा भी की गयी है ।

विभागीय पत्रांक-985, दिनांक-13-02-2020 से संबंधित अनुलग्नक परिशिष्ट पृष्ठ सं०-14 एवं 36 से 38 पर द्रष्टव्य ।

समिति का निर्णय

दिनांक-20.02.2020 की कार्यान्वयन उप समिति की बैठक में समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि पुल नहीं बनने के कारण इस प्रकार के बने पथ की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती है इसलिए ऐसी स्थिति दोबारा नहीं हो । इस निष्कर्ष के साथ समिति द्वारा इस अनुशंसा को कार्यान्वित माना गया ।

पटना ।

दिनांक-12 जून, 2020 (ई0)।

अब्दुल बारी सिद्दिकी
सभापति,
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा ।

ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित सी०ए०जी०

की आपत्तियों पर

समिति का प्रतिवेदन संख्या-533

(दिनांक-15 जुलाई, 2014 को सदन में उपस्थापित)

में दर्ज अनुशंसाओं का कार्यान्वयन ।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या-533 (ग्रामीण कार्य विभाग) में निहित अनुशंसाओं पर समिति का कार्यान्वयन प्रतिवेदन ।

1. वर्ष 2008-09 (सिविल) की कंडिका सं0-1.2.8.4 अनुशंसा पृ0स0-16

समिति की अनुशंसा

संवेदक से राशि की कटौती की गई, के साक्ष्य का एक प्रतिवेदन विभाग समिति को उपलब्ध करा दे, के निदेश के साथ इस आपत्ति को दिनांक-2 सितम्बर, 2013 की बैठक में निष्पादित किया गया ।

कार्यान्वयन की स्थिति

समिति के अनुशंसा के आलोक में कार्य प्रमंडल मधुबनी, बेनीपट्टी, ढ़ाका, समस्तीपुर, रोसड़ा, बिहारशरीफ एवं हिलसा से संबंधित प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक-2790 अनु0 दिनांक-09.03.2018 द्वारा सभा सचिवालय, महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग को प्रेषित किया गया था, जिसके आलोक में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा उक्त कार्य प्रमंडल से संबंधित कतिपय साक्ष्य की मांग की गयी है, जिसे विभागीय पत्रांक 11848 अनु0 दिनांक 28.11.2018 द्वारा महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को उपलब्ध कराया गया ।

उक्त आलोक में महालेखाकार कार्यालय द्वारा विस्तृत समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक-लो0ले0स0/ ग्रा0का0वि0/ए0टी0एन0-18/2019/88C/211, दिनांक-26.12.2018 द्वारा कार्य प्रमंडलवार पृच्छात्मक सूची निराकरण हेतु उपलब्ध कराया गया है जिसके निराकरण हेतु विभाग स्तर पर कार्रवाई की गयी है तथा एतद् संबंधी प्रतिवेदन भेजे जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

समिति का निर्णय

दिनांक-20.02.2020 की कार्यान्वयन उप समिति की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में उक्त अनुशंसा को कार्यान्वित माना गया ।

पटना ।

दिनांक-12 जून, 2020 (ई0)।

अब्दुल बारी सिद्दिकी
सभापति,
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा ।

2. वर्ष 2008-09 (सिविल) की कंडिका सं0-1.2.9.1(क,ख) अनुशंसा पृ0स0-17

समिति की अनुशंसा

दिनांक 2 सितम्बर, 2013 की बैठक में विभागीय उत्तर के आलोक में इस निदेश के साथ कि ''विभागीय सचिव पूरे राज्य में देख लें कि जहाँ भी इस तरह की गलती हो रही हो तो संवेदक और अभियंता पर कार्रवाई करें'' उक्त कंडिका को निष्पादित किया गया ।

कार्यान्वयन की स्थिति

समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-538 दिनांक-04.02.2015 द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को लोक लेखा समिति द्वारा उठाये गये आपत्तियों की पुनरावृति नहीं करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसी क्रम में पुन: विभागीय पत्रांक-1858, दिनांक-16.04.2015 द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को पुन: निदेशित किया गया है कि कालीकरण हेतु निर्धारित विशिष्ट के अनुसार किसी भी Item का प्रावधान डी0पी0आर0 में न छूटे, इसे सुनिश्चित किया जाए । Base कार्य पूर्ण करने के साथ ही बिना विलंब किये कालीकरण कार्य विशिष्ट के अनुरूप कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्रामीण जनता को आवागमन में कठिनाई न हो एवं ग्रेट-3 क्षतिग्रस्त न हो जाए । यदि इस कार्य को करने में संवेदक द्वारा विलम्ब किया जाता हो तो उनके विरूद्ध पी0डब्लू0डी0 कोड तथा एकरारनामा की शर्तो के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए ।

उपरोक्त से संबंधित प्रेषित विभागीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन के आलोक मे महालेखाकार कार्यालय द्वारा सम्परीक्षण टिप्पणी अंकित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा ही अनुशंसा की गयी है कि विभाग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है । इसलिए इस कंडिका को अंतिम रूप से निस्तारित किया जा सकता है ।

विभागीय पत्रांक-985, दिनांक-13-02-2020 से संबंधित अनुलग्नक परिशिष्ट पृष्ठ सं०-14 एवं 39 से 53 पर द्रष्टव्य ।

समिति का निर्णय

दिनांक-20.02.2020 की कार्यान्वयन उप समिति की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में उक्त अनुशंसा को कार्यान्वित माना गया ।

पटना ।

दिनांक-12 जून, 2020 (ई0)।

अब्दुल बारी सिद्दिकी
सभापति,
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा ।

प्रतिवेदन संख्या-506, 529 एवं 533 में दर्ज समिति की अनुशंसाओं पर कार्यान्वयन कि सिीति ।

प्रतिवेदन संख्या-506

कार्यान्वयन हेतु कुल अनुशंसाओं की संख्या-05

कार्यान्वित अनुशंसाओं की संख्या-05 (100%)

प्रतिवेदन संख्या-529

कार्यान्वयन हेतु कुल अनुशंसाओं की संख्या-02

कार्यान्वित अनुशंसाओं की संख्या-02 (100%)

प्रतिवेदन संख्या-533

कार्यान्वयन हेतु कुल अनुशंसाओं की संख्या-02

कार्यान्वित अनुशंसाओं की संख्या-02 (100%)

परिशिष्ट

-893- -14-

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– 10/अ0प्र0–1–5/2017 985 अ0 पटना, दिनांक–13.02.2020

प्रेषक,

प्रवीण कुमार ठाकुर
अभियंता प्रमुख,

सेवा में,

श्री भूदेव राय
निदेशक,
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना

विषयः– लोक लेखा समिति की कायान्वयन उप समिति की दिनांक 20.02.2020 को अपराह्न 3.00 बजे निर्धारित बैठक से संबंधित अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक– 2लो0ले0सं0–09/20–57 दिनांक 24.01.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि लोक लेखा समिति की कार्यान्वयन उप समिति की दिनांक 20.02.2020 को अपराह्न 03.00 बजे निर्धारित बैठक में विचार विमर्श हेतु इस विभाग से संबंधित प्रतिवेदन संख्या–473, 506, 529, 533, 549 (कंडिका संख्या–3.2.11 को छोड़कर), 550, 563, 587, 659, 661 एवं 662 का अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन 10 प्रतियों (Soft Copy सहित) में संलग्न करते हुए आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

प्रतिवेदन संख्या–549 की कंडिका 3.2.11 एवं 566 के संबंध में विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इससे संबंधित कार्यान्वयन प्रतिवेदन अलग से शीघ्र समर्पित की जायेगा।

कृपया इसे स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त

विश्वासभाजन
13/02/2020
अभियंता प्रमुख,

13.02.20

55
14.2.20

बिहार विधान सभा सचिवालय
प्राप्ति तिथिः 13.02.2020
केन्द्रीय डाक सं0 802

प्रतिवेदन संख्या–506

क्रमांक	वर्ष	कंडिका	समिति की अनुशंसा	प्रतिवेदन में अनुशंसा का पृष्ठ संख्या	विभागीय कार्यान्वयन की स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	1996–97	4.21	समिति द्वारा विभागीय जवाब के आलोक में विभागीय आश्वासन के बाद कि भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होगी, इस कंडिका को निष्पादित किया गया है।	पृष्ठ 6/प0	पत्रांक 138 दिनांक 02.01.2018 द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता को समिति के अनुशंसा के आलोक में निदेश दिया गया है कि भविष्य में इसकी पुनर्रावृति न हो, इसका ध्यान रखा जाय। अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि इस कंडिका को पूर्ण रूप से विलोपित करने की कृपा की जाय।	विभागीय पत्रांक 485 अनु0 दिनांक 09.01.2018 द्वारा विधान सभा सचिवालय, महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग, बिहार पटना को पूर्व में भी अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित।
2	1998–99	4.18	समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि बचे हुए सामग्री को विभाग स्टोर पंजी में इन्ट्री करें, जहाँ कही भी इस तरह का पुल बने, वहाँ इस मैटेरियल को लगाया जाय और इसमें जो तकनीकी चूक हुई है, भविष्य में इसकी पुनर्रावृति नहीं हो इस	पृष्ट 9/प0	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल झंझारपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस प्रमंडल अन्तर्गत झंझारपुर से अंधराठारी पथ में अधूरे पड़े स्क्रु पाईल पुल की सामग्री जो स्थल पर लगा हुआ है, को सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य अवर प्रमंडल, अंधराठारी के स्टोर पंजी में दर्ज करा दी गयी है। विभागीय पत्रांक 2790 दिनांक 06.03.	विभागीय पत्रांक 484 अनु0 दिनांक 09.01.2018 द्वारा विधान सभा सचिवालय, महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग, बिहार पटना पूर्व में भी अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित

			कंडिका को निष्पादित किया गया।		2017 (प्रति संलग्न) के द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया है कि भविष्य में जहाँ भी इस प्रकार के पुल का निर्माण/ मरम्मति का कार्य हो तो कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर से स्क्रु पाईल पुल से संबंधित आवश्यकतानुसार आवश्यक अवयव प्राप्त कर इसका उपयोग किया जाय। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाय।	
3	2005–06	4.2.4	(अ) दिनांक 7 जुलाई 2011 की बैठक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि शेष बची हुई राशि की वसूली कर शीघ्र समिति को शीघ्र अवगत कराये, निष्पादित किया गया।	12/प0	कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल सुपौल ने अपने पत्रांक 854 अनु0 दिनांक 16.08.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मेसर्स कार्तिक कुमार, गंगा जल सहरसा, के विरूद्ध कुल 6834035/–रू0 वसुली हेतु सर्टिफिकेट केश जिला नीलाम पदाधिकारी, सुपौल के समक्ष दायर की गयी है। जिसका केश संख्या–27/2017 –18	विभागीय पत्रांक 1452 अनु0 दिनांक 06.02.2018 द्वारा विधान सभा सचिवालय, महालेखकार कार्यालय एवं वित्त विभाग, बिहार पटना को पूर्व मे प्रेषित।
			(ब) दिनांक 7 जुलाई 2011 की बैठक में समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि शेष बची हुई राशि की वसूली की दिशा में कार्रवाई कर विभाग समिति को सूचित करे, इस कंडिका को निष्पादित किया गया ।		कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल सहरसा ने अपने पत्रांक 47 अनु0 दिनांक 12.01.2018 (छायाप्रति संलग्न) प्रतिवेदित किया है कि संवेदक शिवकृष्ण बिल्डर्स प्रा0लि0 बैजनाथपुर, सहरसा से कुल 5728843.00 /रू0 की वसूलनीय थी, जिसमें से विभाग पर पूर्व से संवेदक का 4811729.00/–रू0 जमा था। शेष राशि 917114/–रू0 का चेक के माध्यम से संवेदक द्वारा कार्यपालक	

					अभियंता, कार्य प्रमंडल सहरसा को समर्पित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न) अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को को अंतिम रूप से विलोपित करने की कृपा की जाय।	
4	2007–2008	4.1.5	समिति द्वारा महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति से इस निदेश के साथ कि भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं हो इस कंडिका को विलोपित किया गया।	पृ0–14/प0	विभागीय पत्रांक 139 दिनांक 02.01.2018 द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता को समिति के अनुशंसा के आलोक में निदेश दिया गया है कि भविष्य में इसकी पुनर्रावृति न हो इसका ध्यान रखा जाय। इस प्रकार विभाग द्वारा समिति के अनुशंसा का अनुपालन किया जा चुका है। अतः अनुरोध है कि उक्त कंडिका को अंतिम रूप से निष्पादित करने की कृपा की जाय।	विभागीय पत्रांक 1094 अनु0 दिनांक 29.01.18 द्वारा बिहार विधान सभा सचिवालय एवं महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग को पूर्व में भी कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रेषित।
5	2008–2009	2.1.6	समिति द्वारा इस निदेश के साथ कि भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति न हो वित्त विभाग और प्रधान महालेखाकार की सहमति से इस कंडिका को निष्पादित किया गया।	पृष्ठ 18/प0	समिति के अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 137 दिनांक 02.01.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को भविष्य में इसकी पुनर्रावृति न हो, इस संबंध में दिशा–निर्देश जारी किया गया। एतद् संबंधी कार्यान्वयन प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 1095 अनु0 दिनांक 29.01.2018 द्वारा विधान सभा सचिवालय महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना एवं वित्त विभाग, बिहार पटना को प्रेषित किया गया। उक्त अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा अपने पत्रांक लो0ले0स0/ग्रा0 का0वि0/ ए0टी0एन0/ 18–19/888 /08	

-18-
~~-25-~~

					(छायाप्रति सलग्न) द्वारा उपलब्ध कराये गये सम्परीक्षण टिप्पणी अंकित किया गया है कि विभागीय निदेश निर्गत होने के कारण सम्परीक्षण टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि उक्त कंडिका को अंतिम रूप से विलोपित करने की कृपा की जाय।	

-19-

-26-

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–10/अ0प्र0–1–13/16 /38 पटना, दिनांक 2-1-18

प्रेषक,

विद्याभूषण सिंह
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय– लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या–506 के कंडिका 4.21 में समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में लोक लेखा समिति की प्रतिवेदन संख्या–506 की कंडिका–4.21 द्वारा 1996–97 जो निम्न आपत्तियो से संबंधित है।

(क) वाहनों की उपलब्धता–
(i) मंत्रियों की अत्यधिक संख्या में वाहनों की व्यवस्था
(ii) निष्क्रिय वाहन
(iii) जीप की चोरी एवं वाहनों की बीमाकृत नहीं होने के कारण हानि
(ख) मुहैया की गयी निधि से अधिक व्यय
(ग) बिना स्वीकृति के व्यय
(घ) पेट्रौल/डीजल के खपत पर अधिक व्यय
(ङ) निजी वाहन के किराया शुल्क का अनाधिकृत भुगतान
(च) निधि का अनाधिकृत विचलन
(छ) वाहन के लॉग बुक का संधारण नहीं किया जाना।
(ज) वाहनों से संबंधित अभिलेखो का संधारण।

लोक लेखा समिति द्वारा उक्त कंडिका के विषयवस्तु के संबंध में यह निदेश दिया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती का पुनर्रावृति न हों।

अतः समिति के उक्त निदेश के आलोक में भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो इसका ध्यान रखा जाय।

विश्वासभाजन

28.12.17
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 10/अ0प्र0–1–13/16 /38 पटना, दिनांक– 2-1-18

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब संबंधित पदाधिकारी के ई–मेल के माध्यम से सूचना भेज दी जाय।

28/12/17
सरकार के अवर सचिव

-20-

-27-

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–10/अ0प्र0–1–10/2016 2770 पटना, दिनांक 6.3.17

प्रेषक,

शंकर प्रसाद सिंह,
अभियंता प्रमुख

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

विषय–लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या–506 में निहित कंडिका–4.1B/98–99 में स्क्रू पाईल पुल की सामग्री के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या–506 में निहित कंडिका–4.1B/98–99 के आलोक में कहना है कि जहाँ भी स्क्रु पाईल ब्रीज की मरम्मति/निर्माण का कार्य हो तो कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर से स्क्रु पाईल पुल से संबंधित आवश्यकतानुसार आवश्यक अव्यय प्राप्त कर इसका उपयोग किया जाय।

विश्वासभाजन
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक 10/अ0प्र0–1–10/16 2770 पटना, दिनांक– 6.3.17

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब सभी पदाधिकारियों के ई–मेल के माध्यम से सूचना भेज दी जाय।

अभियंता प्रमुख

-21-

~~27~~ - 28

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल,सुपौल

पत्रांक 854 सुपौ /

प्रेषक :– कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, सुपौल।

सेवा में ,

सरकार के उप सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

सुपौल, दिनांक 16.08.2017

विषय :– लोक लेखा समिति की प्रतिवेदन संख्या–506 के कंडिका संख्या–4:2:4 / 05–06 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–10 / अ0प्र0–1–8 / 2016–9397 पटना, दिनांक 08.08.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक के अनुपालन में जिलाधिकारी सुपौल, के न्यायालय में मेसर्स कार्तिक कुमार, गंगजला, सहरसा बनाम कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सुपौल के नाम से ₹68,34,035=00(रुपये अड़सठ लाख चौंतीस हजार पैंतीस) वसूलनीय हेतु सर्टिफिकेट केस दायर कर दिया गया है, जिसका केस सं0– 27 / 2017–18 है। साक्ष्य हेतु इस पत्र के साथ केस संख्या की छायाप्रति संलग्न की जाती है।

अनु0– यथावर्णित।

विश्वासभाजन

16/8/17

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, सुपौल।

—22—

District Certificate Section, Supaul

~~28~~ - 29

17/17-18

FORM NO. II

REQUISITION FOR A CERTIFICATE

To,

The Certificate Officer of the District of... Supaul...

Number of certificate debtor	Address of certificate-debtor.	Amount of public demand for which the requisition is made	Amount of public demand for which this requisition is made.	Nature of that demand for which this requisition is made
1	2	3	4	5
	M/S Kartik Kumar, Reg. No. 235/86 dt 13.8.86 Class-IA At-Gangjala Dist-Saharsa Address - Kartik Kumar S/O Late Chandra Bhushan Singh At- Gangjala (Behind Saharsa College Saharsa) P.O.-Saharsa. Dist-Saharsa.	Rs. 6834035.00	Rs. 6834035.00	Construction of Road under P.M.G.S.Y. Package No:- BR-35R-03 [(i) Bhoora to Bhairo Patti (ii) Cheni W.B. Road to Charney Road]

I request you to recover the above mention sum of Rs 6834035.00 which I am satisfied, after inquiry, is due from the said ....Amount... respect of Cost. of Road under P.M.G.S.Y. Package No:- BR-35R-03 [(i) Bhoora to Bhairopatti (ii) Cheni W.B. Road to Charney Road]

Verified by me on the ....day of 20

16/8/17

Executive Engineer
R.W.D. Work Division
SUPAUL
12.7.17

16/8/17

-23-

- [illegible] - 30

District Certificate Section, Supaul

FORM NO. 1

CERTIFICATE OF PUBLIC DEMANDS

See Section [illegible]

Filed in the Officer of the Certificate Officer

Name of this District- Supaul

Number of certificate	Name and address of certificate-holder	Name and address of certificate-debtor	Amount of public demand including interest, if any, and including the fee paid under section 5, sub section 2, if any for which the certificate is signed & Period for which such demand is due.	Further [illegible] public dem[illegible] for which [illegible]
1	2	3	4	
	M/S Kartik Kumar, Reg. No 235/86 dt 13.8.86 Class-IA At- Gangjala Dist-Saharsa. Address- Kartik Kumar, S/O Late Chandra Bhushan Singh At- Gangjala (Behind Saharsa College Saharsa) P.O.-Saharsa Dist-Saharsa	Executive Engineer R.W.D. [illegible] Divi- Supaul	Rs. 6834035=00 (23.02.10)	Construction of Road under P.M.G.S.Y Package No- BR-[illegible] [illegible] to [illegible] [illegible] Road to [illegible] Road]

I hereby certify that the above-mentioned sum of Rs 6834035.00 [illegible] above-named certificate is holder from the above named certificate de[illegible] signed on requisition sent under section 5 [illegible]

I further certify that the above mentioned sum of Rs 6834035.00 [illegible] recoverable and that its recovery by suit is not barred by law.

Dated the .... day of Year-20

[illegible]

Su[illegible]

24-

31

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा।

पत्रांक ....47/अ.का.

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सहरसा।

सेवा में,

श्री विद्याभूषण सिंह
सरकार के अवर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सहरसा दिनांक 12-01-18

विषय : C.A.G की लंबित कंडिका 04.2.4 CWJC No. 4570/07 की अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग : अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा का पत्रांक 1192 दिनांक 26.08.09 एवं पत्रांक 374 दिनांक 12.05.15 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 526 दिनांक 24.03.17 एवं पत्रांक 1731 दिनांक 11.11.17

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के अनुपालन में विषयगत मामले में शिवकृष्णा विल्डर्स प्रा.लि. बैजनाथपुर, सहरसा से कुल 5728843.00 रू. वसूल करने हेतु निदेशित किया गया था जिसमें 4811729.00 रू. इस कार्यालय के पत्रांक 526 दिनांक 24.03.17 एवं 917114.00 रू. इस कार्यालय के पत्रांक 1731 दिनांक 11.11.17 द्वारा वसूली संबंधी प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्र की छायाप्रति पुनः आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती हैं।

अनु. – यथोक्त।

विश्वासभाजन

12.1.2018

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
सहरसा।

5.0-10
15.1.18

327(U.S)
16/8/18

18-1-18

81(10-5)
18.1.18

- —25 -

-33-32

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा।

पत्रांक ....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सहरसा।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
पटना।

सहरसा दिनांक ....

विषय : सी.डब्ल्यू. जे.सी नं. – 4570/07 शिवकृष्णा बिल्डर्स बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के आलोक में पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में अवशेष राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करने के संबंध में।

प्रसंग : सरकार के उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग का पत्रांक 1954 अनु दिनांक 20.02.17

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि उक्त वाद से संबंधित अवशेष कार्य एवं पुर्ननिविदा हेतु नए दर के अंतर राशि 5728843.00 रू. वसूलनीय है जिसमें विभाग पर संवेदक का 4811729.00 रू. जमा है, जिसकी विवरणी नीचे दी गई है।। शेष राशि 917114.00 रू. का अधोहस्ताक्षरी के नाम बैंक ड्राफ्ट (भुगतेय पटना) के माध्यम से यथाशीघ्र जमा करने हेतु निदेशित किया गया है जिसे प्राप्त होते ही यथाशीघ्र अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाएगी। यह प्रासंगिक विषय विधान सभा के लोक लेखा समिति एवं महालेखाकार का CAG पारा से भी संबंधित है।

संवेदक के जमा राशि का विवरण :–

1- बकाया विपत्र से भुगतेय चेक की राशि	: 1556683.00
2- जमानत जमा के रूप में विपत्र से कटौती की राशि	: 324844.00
3. समय वृद्धि में कटौती की राशि	: 550801.00
4. अग्रधन के रूप में जमा NSC की राशि	: 1148100.00
5. NSC पर प्राप्त ब्याज की राशि	: 1231301.00
कुल योग :	4811729.00

विश्वासभाजन

S/-

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
सहरसा।

ज्ञापांक 526 दिनांक 24/3/17

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता –2 ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

24.3.17

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
सहरसा।

– 26 –

~~३~~ – 33

(66)

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा।

पत्रांक ....
प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सहरसा।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,
भारतीय स्टेट बैंक,
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।

सहरसा दिनांक ....

विषय : संवेदको के अग्रधन के रूप में जमा राशि को जब्त कर उसका चेक जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस प्रमंडल के शीर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य को संवेदकों लोहा कन्सट्रक्शन, शिवकृष्णा बिल्डर्स, एवं मेसर्स ओम साई इंजिकोन्स द्वारा पूर्ण नहीं करने के कारण एकरारनामा को विखंडित कर उनके अग्रधन एवं जमानत की राशि का चेक निम्न विवरणी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम फंड खाता 11111137916 में जमा करने की कृपा की जाय।

Sl.No	Cheque/ D.D No.	Date	Amount	Remarks
1	594069	14.07.17	88322.00	
2	594073	15.07.17	28496.00	
3	594134	26.07.17	35300.00	
4	594151	27.07.17	148230.00	
5 ✓	740635	09.10.17	917114.00 –	
6	004643	07.11.17	1058000.00	
		Total :	**2275462.00**	

विश्वासभाजन

ह०/-
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
सहरसा।

ज्ञापांक 1731, दिनांक 11-11-17

प्रतिलिपि : अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी – सह – सचिव ग्रामीण कार्य विभाग, सहकारी भूमि विकास बैंक, तृतीय तल, बुद्ध मार्ग पटना – 1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

11.11.17
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
सहरसा।

-27-

-33-34

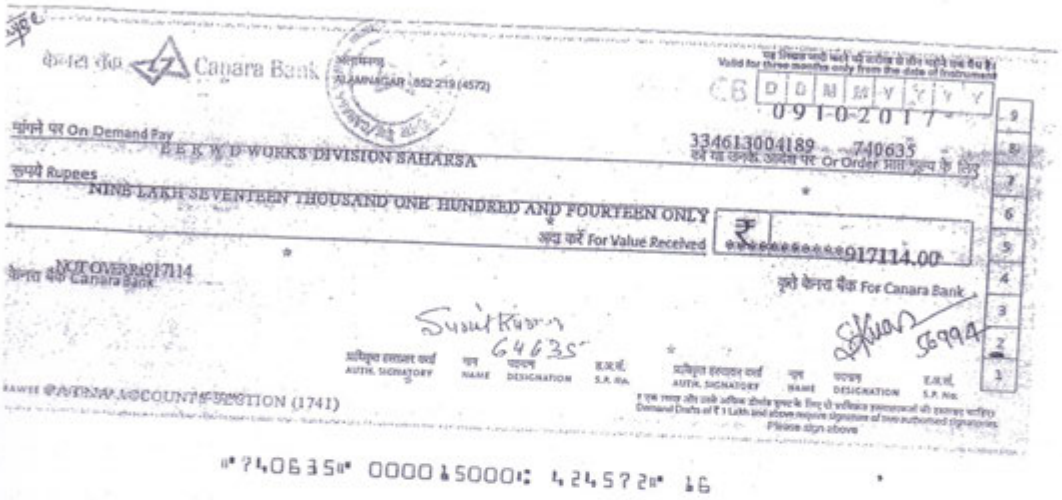

केनरा बैंक Canara Bank

ALAMNAGAR 852 219 (4572)

यह लिखत जारी करने की तारीख से तीन महीने तक वैध है। Valid for three months only from the date of instrument

CB D D M M Y Y Y Y

09 10 2017

मांगने पर On Demand Pay

E E K W D WORKS DIVISION SAHARSA

334613004189 740635

को या उनके आदेश पर Or Order मात्र/मूल्य के लिए

रुपये Rupees

NINE LAKH SEVENTEEN THOUSAND ONE HUNDRED AND FOURTEEN ONLY

अदा करें For Value Received

₹ ************917114.00

NOT OVER Rs917114

केनरा बैंक Canara Bank

कृते केनरा बैंक For Canara Bank

Sunil Kumar 64635

56994

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता AUTH. SIGNATORY	नाम NAME	पदनाम DESIGNATION	हस्ता.सं. S.P. No.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता AUTH. SIGNATORY	नाम NAME	पदनाम DESIGNATION	हस्ता.सं. S.P. No.

DRAWEE @ PATNA ACCOUNTS SECTION (1741)

Demand Drafts of ₹ 1 Lakh and above require signature of two authorised signatories. Please sign above

⑈740635⑈ 000015000⑆ 424572⑈ 16

-28-

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–10/अ0प्र0–1–07/16 139 पटना, दिनांक 2·1·18

प्रेषक,

विद्याभूषण सिंह
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय–लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या–506 के कंडिका 4.1.5 में समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में लोक लेखा समिति की प्रतिवेदन संख्या–506 की कंडिका–4.1.5 द्वारा 2007–08 जो ढुलाई पर कपटपूर्ण व्यय से संबंधित है। उक्त कंडिका आपत्ति में अन्य तथ्यों के साथ मुख्य रूप से यह आपत्ति था कि स्टोन मेटल चिप्स की खदान की वास्तविकता सुनिश्चित किए बगैर संवेदक को स्टोन मेटल चिप्स की ढुलाई पर रूपये का भुगतान कर प्रमंडल द्वारा संवेदक का पक्ष लिया गया।

लोक लेखा समिति द्वारा उक्त कंडिका के विषयवस्तु के संबंध में यह निदेश दिया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती का पुनर्रावृति न हों।

अतः समिति के उक्त निदेश के आलोक में भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो इसका ध्यान रखा जाय।

विश्वासभाजन

28.12.17
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 10/अ0प्र0–1–07/16 139 पटना, दिनांक–2·1·18

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब संबंधित पदाधिकारी के ई–मेल के माध्यम से सूचना भेज दी जाय।

28.12.17
सरकार के अवर सचिव

-29-

REGISTERED POST 35 - 36

संख्या No. लो.ले.स./प्रा.का.वि./रा.टी.स./18-19/885/08

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Accountant General (Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna-800 001

सत्यमेव जयते

दिनांक/Date : 26.04.2018

सेवा में,

सरकार के उप सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका ज्ञापांक– 10/अ0प्र0–1–11/16–1095, दिनांक– 29.01.2018.

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपके द्वारा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 506 में समिति के द्वारा वर्ष 2008–09 की कंडिका संख्या–2.1.6 पर की गई अनुशंसाओं के आलोक में प्रेषित कार्यान्वयन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई है एवं सम्परीक्षण टिप्पणी अंकित की गई है।

कार्यान्वयन प्रतिवेदन पर अंकित संपरीक्षण टिप्पणी संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

5010

अवर सचिव कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, पत्र प्राप्ति, 8 MAY 2018, 3192, संख्या, बिहार पटना

अनुलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
26.04.18
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
लोक लेखा समिति अनुभाग।

15.5.18

2831/84
15.5.18

फोन/Phone - 2221226, 2221941, 2223725, 2223194, 2506091, 2506283
फै./Fax : 0612-250 6223, 2506207 ई.मेल/E-mail-agaubihar@cag.gov.in
ई.पी.ए.बी.एक्स./EPABX-2223757, 2228320
पो॰ बॉक्स/P.B.No.-47

-30-

-36- 37

ANNEXURE

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या	विभाग का नाम	कंडिका संख्या	प्रतिवेदन वर्ष	सम्परीक्षण टिप्पणीयाँ
506	ग्रामीण कार्य विभाग	2.1.6 (सिविल)	2008–09	ज्ञापांक 1095 दिनांक 29.01.2018 समिति की अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को मस्टर रौल के संधारण के संदर्भ में पत्रांक 137 दिनांक 02.01.2018 द्वारा निदेश निर्गत किया जा चुका है। अतएव, सम्परीक्षण टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

[signature] 16.05.18

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
लोक लेखा समिति अनुभाग।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक—10/अ0प्र0—1—11/16 137 पटना, दिनांक 2·1·18

प्रेषक,

विद्याभूषण सिंह
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय—लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या—506 के कंडिका 2.1.6 में समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में लोक लेखा समिति की प्रतिवेदन संख्या—506 की कंडिका—2.1.6 द्वारा 2008—09 जो मास्टर रौल पर कपटपूर्ण भुगतान से संबंधित है। उक्त कंडिका आपत्ति में अन्य तथ्यों के साथ मुख्य रूप से यह आपत्ति था कि सतर्कता विभाग, बिहार सरकार के आदेशानुसार भुगतान की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु मास्टर रॉल पर श्रमिकों की विवरण यथा नाम, पिता/पति का नाम, गाँव एवं पूरा पता दर्ज किया जाना था। इसके अलावे बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के नियम के 227 के अनुसार मास्टर रॉल प्रपत्र—21 में तैयार किया जाना था।

उक्त के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा पर्यवेक्षण नहीं किए जाने तथा सतर्कता विभाग के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण 2.68 लाख रूपये का कपटपूर्ण भुगतान सी0ए0जी0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया।

लोक लेखा समिति द्वारा उक्त कंडिका के विषयवस्तु के संबंध में यह निदेश दिया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती का पुनर्वृत्ति न हो।

अतः समिति के उक्त निदेश के आलोक में भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो इसका ध्यान रखा जाय।

विश्वासभाजन

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक 10/अ0प्र0—1—11/16 137 पटना, दिनांक— 02·01·18

प्रतिलिपि— आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब संबंधित पदाधिकारी के ई—मेल के माध्यम से सूचना भेज दी जाय।

सरकार के अवर सचिव

प्रतिवेदन संख्या–529

क्रमांक	वर्ष	कंडिका	समिति की अनुशंसा	प्रतिवेदन में अनुशंसा का पृष्ठ संख्या	विभागीय कार्यान्वयन की स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	2011–12	कंडिका संख्या–5.1.1	समिति द्वारा महालेखाकार वित्त विभाग की सहमति से इस कंडिका को इस निदेश के साथ निष्पादित किया गया कि भविष्य में इस तरह की गलती की पुनर्रावृति न हों।	पृष्ठ– 4	समिति के अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 169 दिनांक 03.01.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सभी संबंधित को भविष्य में इसकी पुनर्रावृति न हो, इसके संबंध में दिशा–निदेश जारी किया गया है। उक्त के आलोक में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना के पत्रांक लो0ले0स0/ग्रा0का0वि/ए0टी0एन0 /16–17/888 दिनांक 05.02.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सम्परीक्षण टिप्पणी दर्ज कर उपलब्ध कराया गया है। उक्त सम्परीक्षण टिप्पणी में उल्लेख किया गया है कि समिति के अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा दिशा–निर्देश भी जारी कर दिया गया है तथा समिति द्वारा कंडिका को निष्पादित किया जा चुका है। इस प्रकार विभाग समिति के द्वारा किये गये अनुशंसा का पूर्णरूप से अनुपालन कर लिया गया है। अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि इस कंडिका को पूर्ण रूप से विलोपित करने की कृपा कीं जाय।	

क्रम – 40 | 17

संख्या/No. ओ॰ले॰प॰/ग्रा॰का॰वि॰/स्टी॰प॰/ 16-17/886

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Accountant General (Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna-800 001

दिनांक/Date : 05.02.2018

सेवा में,

सरकार के उप सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक– 10/अ0प्र0–1–13/16–789, दिनांक– 17.01.2018.

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपके द्वारा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 529 में समिति के द्वारा वर्ष 2011–12 की कंडिका संख्या– 5.1.1 पर की गई अनुशंसाओं के आलोक में प्रेषित कार्यान्वयन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई है एवं सम्परीक्षण टिप्पणी अंकित की गई है।

कार्यान्वयन प्रतिवेदन पर अंकित संपरीक्षण टिप्पणी संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

अनुलग्नक :– यथोपरि।

विश्वासभाजन

05.02.18

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
लोक लेखा समिति अनुभाग।

S.O.10
895/24
3/2/18

9/2/18

दूरभाष/Phone - 2221226, 2221941, 2223725, 2223194, 2506091, 2506283   ई.पी.ए.बी.एक्स./EPABX-2223757, 2228320
फैक्स/Fax : 0612-250 6223, 2506207   ई.मेल/E-mail-agaubihar@cag.gov.in   पो॰ बॉक्स/P.B.No.-47

-34-

-40-41

ANNEXURE

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या	विभाग का नाम	कंडिका संख्या	प्रतिवेदन वर्ष	सम्परीक्षण टिप्पणीयाँ
529	ग्रामीण कार्य विभाग	5.1.1	2011-12 (सिविल)	लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 529 के द्वारा कंडिका को निष्पादित किया जा चुका है तथा समिति की अनुशंसा के आलोक में विभाग द्वारा दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया गया है।

05.02.18

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
लोक लेखा समिति अनुभाग।

-35-

-42-

175

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–10/अ0प्र0–1–13/2016 169 /पटना, दिनांक– 3.1.18

प्रेषक,

विद्याभूषण सिंह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–14)
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय– लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन सं0–529 से संबंधित कंडिका 5.1.1 में समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोक लेखा समिति की अंकेक्षण प्रतिवेदन 2011–12 की कंडिका 5.1.1 में समिति के अनुशंसा के आलोक में सुनिश्चित किया जाये कि निबंधन हेतु बैंक ड्राफ्ट नियमानुसार एवं ससमय संधारित कर सरकारी खाते में जमा किये जाये। इस निदेश का पूर्णतः पालन करते हुए ध्यान रखा जाये कि भविष्य में पूर्व की गलती की पुनरावृति नहीं हो, अन्यथा दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,
03.01.18
सरकार के अवर सचिव।

मुनेश्वर–03.01.18

प्रतिवेदन संख्या–529

क्रमांक	वर्ष	कंडिका	समिति की अनुशंसा	प्रतिवेदन में अनुशंसा का पृष्ठ संख्या	विभागीय कार्यान्वयन की स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
2	2011–12	5.2.2	इस कंडिका को इस निदेश के साथ निष्पादित किया गया कि भविष्य में जब भी इस तरह के कंसलटेंट बहाल किये जाये तो विभाग द्वारा उसका कार्य का प्रोपर मोनिटरिंग हो एवं पुल का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाय।	6/प0	समिति के अनुशसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 6820 अनु0 दिनांक 26.06.2018 द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन बिहार विधान सभा सचिवालय, महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग, बिहार पटना को प्रेषित की गयी थी जिसके आलोक में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा अपने पत्रांक लो0ले0स0/ग्रा0का0वि0/ए0टी0एन0/18–19/888 दिनांक 10.08.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अंतिम रूप से सम्परीक्षण टिप्पणी उपलब्ध कराया गया है। उक्त सम्परीक्षण टिप्पणी में प्रतिवेदित है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य प्रमंडल औरंगाबाद के अन्तर्गत रफीगंज से बलिगांव पथ के बीच में नदी के चैनलों में दो पुलों का निर्माण नहीं किया गया। इसके कारण रफीगंज से बलिगाँव पथ पर अवस्थित सभी बसावटों को बारहमासी सम्पर्कता नहीं प्रदान किये जाने संबंधी आपत्ति की गयी थी। उक्त आपत्ति के आलोक में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये नजरी नक्शा के अनुसार नदी के दोनो चैनल पर पुल का निर्माण किया जा चुका है। पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत अन्य सड़कों के माध्यम से भी आपत्ति बसावटों की सड़क सम्पर्कता बहाल कर दी गयी है। उपरोक्त के आलोक में महालेखाकार कार्यालय द्वारा उक्त कंडिका को अंतिम रूप से निष्पादित करने हेतु समिति से अनुशंसा भी की गयी है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि इस कंडिका को अंतिम रूप से निष्पादित करने की कृपा की जाय।	

-37-

-44-

संख्या/No. लो.ले.स./ग्रा.का.वि./का.प्र./13-19/117

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna-800 001

दिनांक/Date : 10.08.2018

सेवा में,

सरकार के अवर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः- कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंगः- आपका पत्रांक-10/अ0प्र0-1-12/16-8370, दिनांक-27.07.2018.

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपके द्वारा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 529 में समिति के द्वारा दर्ज 2011-12 की कंडिका संख्या- 5.2.2 पर की गई अनुशंसाओं के आलोक में प्रेषित कार्यान्वयन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई है एवं सम्परीक्षण टिप्पणी अंकित की गई है।

कार्यान्वयन प्रतिवेदन पर अंकित सम्परीक्षण टिप्पणी संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

20 AUG 2018
5958

भवदीय,

10.08.18
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
लोक लेखा समिति अनुभाग।

9.8.18

29.8.18

फोन/Phone - 2221226, 2506091, 2223194, 2221941, 2223725, 2506283 ई.पी.ए.बी.एक्स./EPABX-2223757
फैक्स/Fax : 0612-250 6223,2506174 ई.मेल/E-mail- agaubihar@cag.gov.in, पो. बॉक्स/P.B.

-38-

~~44~~ -45

(64

ANNEXURE

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या	विभाग का नाम	कंडिका संख्या	प्रतिवेदन वर्ष	सम्परीक्षण टिप्पणी
529	ग्रामीण कार्य विभाग	5.2.2	2011-12 (सिविल)	**पत्रांक 8370 दिनांक 27.07.2018** कंडिका के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, औरंगाबाद के अंतर्गत रफीगंज से बलिगाँव पथ के बीच में नदी के चैनलों में दो पुलों का निर्माण नहीं किया गया था। इसके कारण रफीगंज से बलिगाँव पथ पर अवस्थित सभी बसावटों को बारहमासी सम्पर्कता नहीं प्रदान किए जाने संबंधी आपत्ति की गई थी। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए नजरी-नक्शा के अनुसार नदी के दोनों चैनलों पर पुल का निर्माण किया जा चुका है तथा पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत अन्य सड़कों के माध्यम से भी आपत्तित बसावटों की सड़क सम्पर्कता बहाल कर दी गई है। [redacted]

10.08.18

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
लोक लेखा समिति अनुभाग।

प्रतिवेदन संख्या–533

क्रमांक	वर्ष	कंडिका	समिति की अनुशंसा	प्रतिवेदन में अनुशंसा का पृष्ठ संख्या	विभागीय कार्यान्वयन की स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
2	2008–09	1.2.8.4	संवेदक से राशि की कटौती की गई, के साक्ष्य का एक प्रतिवेदन विभाग समिति को उपलब्ध करा दे, के निदेश के साथ इस आपत्ति को दिनांक 02 सितम्बर 2013 की बैठक में निष्पादित किया गया	पृ0–16	समिति के अनुशंसा के आलोक में कार्य प्रमंडल मधुबनी, बेनीपट्टी, ढ़ाका, समस्तीपुर, रोसड़ा, बिहारशरीफ एवं हिलसा से संबंधित प्रतिवेदन विभागीय पत्रांक 2790 अनु0 दिनांक 09.03.2018 द्वारा सभा सचिवालय, महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग को प्रेषित किया गया था, जिसके आलोक में महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना द्वारा उक्त कार्य प्रमंडल से संबंधित कतिपय साक्ष्य की मांग की गयी है, जिसे विभागीय पत्रांक 11848 अनु0 दिनांक 28.11.2018 द्वारा महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को उपलब्ध कराया गया। उक्त के आलोक में महालेखाकार कार्यालय द्वारा विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना ने अपने पत्रांक	

					लो0ले0सं0/ग्रा0का0वि0/ए0टी0एन0–18/2019/88C/211 दिनांक 26.12.2018 द्वारा कार्य प्रमंडलवार पृच्छात्मक सूची निराकरण हेतु उपलब्ध कराया गया है जिसके निराकरण हेतु विभाग स्तर पर कार्रवाई की गयी है तथा एतद् संबंधी प्रतिवेदन भेजे जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।	
3	2008–09	1.2.9.1 (क, ख)	दिनांक 2 सितम्बर 2013 की बैठक में विभागीय उत्तर के आलोक में इस निदेश के साथ कि " विभागीय सचिव पूरे राज्य में देख लें कि जहाँ भी इस तरह की गलती हो रही हो तो संवेदक और अभियंता पर कार्रवाई करे" उक्त कंडिका को निष्पादित किया गया।	पृ0–17	समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 538 दिनांक 04.02.2015 द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को लोक लेखा समिति द्वारा उठाये गये आपत्तियों की पुनरावृति नहीं करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसी क्रम में पुनः विभागीय पत्रांक 1858 दिनांक 16.04.2015 द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को पुनः निदेशित किया गया है कि कि कालीकरण हेतु निर्धारित विशिष्टि के अनुसार किसी भी Item का प्रावधान डी0पी0आर0 में न छूटे, इसे सुनिश्चित किया जाए। Base कार्य पूर्ण करने के साथ ही बिना विलंब किये कालीकरण कार्य विशिष्टि के अनुरूप कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्रामीण जनता को आवागमन में कठिनाई न हो एंवं ग्रेड–3 क्षतिग्रस्त न हो जाए। यदि इस कार्य को करने में संवेदक द्वारा विलम्ब किया जाता हो तो उनके विरूद्ध पी0डब्लू0डी0 कोड तथा एकरारनामा की शर्तो के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त से संबंधित प्रेषित विभागीय कार्यान्वयन	

					प्रतिवेदन के आलोक में महालेखाकार कार्यालय द्वारा सम्परीक्षण टिप्पणी अंकित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा ही अनुशंसा की गयी है कि विभाग द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर दिया गया है। इसलिए इस कंडिका को अंतिम रूप से निस्तारित किया जा सकता है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि इस कंडिका को अंतिम रूप से निष्पादित करने की कृपा की जाय।	

—42—

SPEED POST- 49

संख्या लो.ले.स./प्रा.का.वि./प्र.टी.-न/18-19/3840 ।।
No.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna-800 001

दिनांक/Date : 26.12.2018

विशेष सचिव

सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।
-800015

विषयः– कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक– 10/अ0प्र0–1–14/16/11848, दिनांक– 28.11.2018

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपके द्वारा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 533 में समिति के द्वारा वर्ष 2008–09 (सिविल) की कंडिका संख्या–1.2.8.4 पर की गई अनुशंसा के आलोक में प्रेषित कार्यान्वयन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई है एवं सम्परीक्षण टिप्पणी अंकित की गई है।

कार्यान्वयन प्रतिवेदन पर अंकित संपरीक्षण टिप्पणी संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

अनुलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,
26.12.18
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
लोक लेखा समिति।

दूरभाष/Phone - 2221226, 2506091, 2223194, 2221941, 2223725, 2506283 ई.पी.ए.बी.एक्स./EPABX-2223757
फैक्स/Fax : 0612-250 6223,2506174 ई.मेल/E-mail- agaubihar@cag.gov.in, पो० बॉक्स/P.B.No.- 47

-43-

-50-

ANNEXURE

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या	विभाग का नाम	कंडिका संख्या	प्रतिवेदन वर्ष	सम्परीक्षण टिप्पणीयाँ
533	ग्रामीण कार्य विभाग	1.2.8.4	2008–09 (सिविल)	ज्ञापांक 11848 दिनांक 28.11.2018 सभी 37 मामलों को संवीक्षीत कर लेखापरीक्षा अभियुक्ति संलग्न परिशिष्ट में अंकित किया गया है। संवीक्षा के अनुसार चार मामलों (12, 16, 04 एवं 82 F2, RWD, Madhubani) का अनुपालन प्रतिवेदन अबतक नहीं भेजा गया है। एक मामले (82F2, RWD, Biharsarif) में साक्ष्य संलग्न है तथा संतोषजनक है। बाकी 32 मामलों में संवेदकों को time extension देने की चर्चा की गई है तथा उससे संबंधित पत्र भी उपलब्ध कराया गया है। परंतु, संवेदकों द्वारा time extension के लिए सौंपे गए आवेदन तथा अंतिम मापी पुस्तिका की प्रति उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जिससे यह ज्ञात हो सके कि संवेदकों ने time extension हेतु F2 agreement के Clause (5) के अनुसार ससमय अनुरोध किया था अथवा नहीं तथा क्या time extension दिए जाने के बाद उनके द्वारा उसी अवधि के अंदर कार्य पूर्ण करा लिया गया था। उक्त दस्तावेजों को उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही कंडिका के अंतिम रूप से निष्पादन हेतु यथोचित मंतव्य दिया जा सकता है।

28.12.18

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
लोक लेखा समिति अनुभाग।

Annexure-A

लोक लेखा समिति की प्रतिवेदन संख्या–533 की कंडिका–1.2.8.4/2008–09 (सिविल) पर प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदन पर सम्परीक्षण टिप्पणी

प्रमंडल का नाम	एकरारनामा सं० (F_2)/वर्ष	एकरारित राशि (₹ लाख में)	क्षतिपूर्ति के रूप में, कटौती की जाने वाली राशि (₹ लाख में)	आपत्तित कंडिका एवं विभागीय अनुपालन के आलोक में अद्यतन कटौती की गई क्षतिपूर्ति की राशि (₹ लाख में)	विभागीय अनुपालन (ज्ञापांक–11848 दिनांक–28.11.2018) की समीक्षा के उपरांत वांछित अभिलेख/अभ्युक्ति
ग्रामीण कार्य प्रमंडल, मधुबनी	83/2006–07	248.93	24.89	10.04	दिनांक–22.07.2009 तक समय वृद्धि की स्वीकृति का साक्ष्य संलग्न। (i) संवेदक द्वारा समयवृद्धि की मांग के संबंध में दिए गए आवेदन की छायाप्रति वांछित। (ii) कार्य के समापन की अंतिम मापी लिए जाने की तिथि के साक्ष्य हेतु संबंधित मापी पुस्त की छायाप्रति वांछित।
	10/2007–08	82.69	8.27	1.73	दिनांक–28.07.2008 तक समय वृद्धि की स्वीकृति का साक्ष्य संलग्न। (i) संवेदक द्वारा समयवृद्धि की मांग के संबंध में दिए गए आवेदन की छायाप्रति वांछित। (ii) कार्य के समापन की अंतिम मापी लिए जाने की तिथि के साक्ष्य हेतु संबंधित मापी पुस्त की छायाप्रति वांछित।
	15/2007–08	168.11	16.81	2.85	दिनांक–05.08.2011 तक समय वृद्धि की स्वीकृति का साक्ष्य संलग्न। (i) संवेदक द्वारा समयवृद्धि की मांग के संबंध में दिए गए आवेदन की छायाप्रति वांछित। (ii) कार्य के समापन की अंतिम मापी लिए जाने की तिथि के साक्ष्य हेतु संबंधित मापी पुस्त की छायाप्रति वांछित।
	12/2007–08	87.89	8.79	4.70	लोक लेखा समिति की अनुशंसा (दिनांक–02.09.2013) के पाँच वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी अद्यतन अनुपालन अबतक अप्राप्त।
	16/2007–08	84.26	8.43	1.99	
	04/2007–08	146.79	14.68	1.00	
	82/2006–07	182.14	18.21	6.09	

ग्रामीण कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी	66/2006–07	198.35	19.84	10.32	विभागीय अनुपालन के आलोक में (i) संवेदक द्वारा समयवृद्धि की मांग के संबंध में दिए गए आवेदन की छायाप्रति (ii) समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान किए जाने वाले पत्र की छायाप्रति एवं (iii) कार्य के समापन की अंतिम मापी लिए जाने की तिथि के साक्ष्य हेतु संबंधित मापी पुस्त की छायाप्रति वांछित।
	67/2006–07	103.61	10.36	5.85	
	01/2007–08	149.11	14.91	6.21	
ग्रामीण कार्य प्रमंडल, ढ़ाका	61/2006–07	142.99	14.30	4.69	एकरारनामा वार अनुपालन नहीं दिया गया है। एकरारनामा वार क्षतिपूर्ति राशि की अद्यतन कटौती किये जाने एवं उसका साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।
	62/2006–07	66.51	6.65	3.62	
	65/2006–07	131.34	13.13	2.82	
	84/2006–07	118.47	11.85	7.84	
	85/2006–07	227.99	22.80	13.31	
ग्रामीण कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर	53/2006–07	79.70	7.97	3.77	कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर के संबंध में उपलब्ध कराये गये तीन कार्यों में समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान किए जाने वाले पत्रों की छायाप्रति (मुख्य अभियंता–3, पटना का ज्ञापांक–2961 दिनांक–11.06.2012, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, दरभंगा का पत्रांक–100 दिनांक–19.01.2011 एवं पत्रांक–99 दिनांक–18.01.2011) उपलब्ध करायी गयी है, परंतु उक्त तीनों कार्य किस एकरारनामा संख्या/वर्ष से संबंधित है, उल्लेखित नहीं है। इस संबंध में आपत्ति कंडिका में शामिल पाँचों एकरारनामों से कटौती की गई समयवृद्धि की राशि (साक्ष्य सहित) अथवा उक्त कार्यों में समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान किए जाने का साक्ष्य, उनके समापन की अंतिम मापी लिए जाने की तिथि सहित साक्ष्य के रूप में संबंधित मापी पुस्त की छायाप्रति उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।
	45/2006–07	53.20	5.32	2.69	
	47/2006–07	81.20	8.12	3.22	
	46/2006–07	85.60	8.56	3.66	
	01/2007–08	141.60	14.16	7.76	
ग्रामीण कार्य प्रमंडल, रोसड़ा	73/2006–07	39.28	3.93	1.95	कंडिका में उल्लेखित क्षतिपूर्ति की कटौती की जाने वाली कुल राशि ₹ 62.08 लाख के विरूद्ध कुल ₹ 28.46 लाख की क्षतिपूर्ति राशि की कटौती किए जाने का साक्ष्य के रूप में चालू विपत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है। शेष बची राशि ₹ 33.62 (₹ 62.08–28.46) की वसूली हेतु की जा रही कार्रवाई से साक्ष्य सहित अवगत कराया जाय।
	74/2006–07	67.18	6.72	4.13	
	01/2007–08	190.57	19.06	7.37	
	10/2007–08	323.66	32.37	15.01	

ग्रामीण कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ	65/2006-07	118.00	11.80	5.25	उक्त दोनों एकरारनामों में समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान किए जाने संबंधी पत्र की छायाप्रति संलग्न नहीं पायी गयी। पत्रों की छायाप्रति तथा उक्त दोनों एकरारनामों में कार्य की समापन की अंतिम मापी लिए जाने की तिथि का साक्ष्य के रूप में संबंधित मापीपुस्त की छायाप्रति उपलब्ध कराया जाय। साथ ही, संवेदक द्वारा समयवृद्धि की मांग के संबंध में दिए गए आवेदन की छायाप्रति वांछित है।
	08/2007-08	146.59	14.66	8.42	
	82/2006-07	45.90	4.59	—	एकरारनामा सं0-82एफ2/ 2006-07 के संदर्भ में कार्य की समाप्ति (दिनांक 15.09.2007 को) समय पर किए जाने का साक्ष्य के रूप में मापीपुस्त की छायाप्रति संलग्न की गई है एवं संतोषजनक है।
	01/2007-08	105.11	10.51	5.72	उक्त चारों एकरारनामों के कार्यों में समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान किए जाने का साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। इस संबंध में उक्त एकरारनामों के कार्यों के समापन की अंतिम मापी लिए जाने की तिथि का साक्ष्य के रूप में संबंधित मापीपुस्त की छायाप्रति उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही, संवेदक द्वारा समयवृद्धि की मांग के संबंध में दिए गए आवेदन की छायाप्रति वांछित है।
	03/2007-08	160.21	16.02	10.96	
	05/2007-08	98.85	9.89	6.57	
	09/2007-08	145.89	14.59	10.60	
ग्रामीण कार्य प्रमंडल, हिलसा	49/2006-07	37.62	3.76	0.54	उक्त चारों एकरारनामों के कार्यों में समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान किए जाने का साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। इस संबंध में उक्त एकरारनामों के कार्यों के समापन की अंतिम मापी लिए जाने की तिथि का साक्ष्य के रूप में संबंधित मापीपुस्त की छायाप्रति उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही, संवेदक द्वारा समयवृद्धि की मांग के संबंध में दिए गए आवेदन की छायाप्रति वांछित है।
	53/2006-07	64.15	6.42	2.87	
	60/2006-07	157.94	15.79	7.16	
	63/2006-07	96.45	9.65	6.45	
	51/2006-07	58.31	5.83	0.98	शेष बची राशि ₹ 4.85 लाख की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाय।
	07/2007-08	30.04	3.00	1.35	शेष बची राशि ₹ 1.65 लाख की वसूली की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाय।

-47-

-54-

A-13

ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण

पत्रांक– 10/अ0प्र0–1–14/16 11848 /पटना, दिनांक–28.11.18

प्रेषक,

विनय कुमार, भा० प्र० से०,
सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी,
लोक लेखा समिति अनुभाग,
महालेखाकार कार्यालय,
बिहार, पटना।

विषयः– लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या–533 की कंडिका संख्या–1.2.8.4/2008–09 (सिविल) में की गयी अनुशंसा के कार्यान्वियन प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका का पत्रांक लो0ले0स0/ग्रा0का0वि0/ए0टी0ए0/2018–19 /88A/10 दिनांक 26.04.2018 एवं पत्रांक लो0ले0स0/ग्रा0का0वि0/ए0टी0ए0/2018–19/88C/135 दिनांक 28.09.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में प्रतिवेदन संख्या–533 के कंडिका संख्या–1.2.8.4/2008–09 (सिविल) के संबंध में टिप्पणी किया गया है कि कार्य प्रमण्डल बेनीपट्टी, रोसड़ा एवं हिलसा के द्वारा वसूली का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही मधुबनी, ढ़ाका, समस्तीपुर एवं बिहारशरीफ कार्य प्रमण्डलों का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। उसके बाद ही इस कंडिका के निरस्तीकरण के संबंध में कोई टिप्पणी किया जा पाना संभव होगा।

उक्त सम्परीक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्य प्रमण्डल, मधुबनी, रोसड़ा, समस्तीपुर, बेनीपट्टी, बिहारशरीफ, हिलसा एवं ढ़ाका से प्राप्त प्रतिवेदन साक्ष्य सहित संकलित कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जा रही है।

अनुरोध है कि प्रतिवेदन संख्या–533 के कंडिका संख्या– 1.2.8.4/2008–09 (सिविल) को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

28/11/18

(विनय कुमार)

-48-
R.P -55-

संख्या No. लो.ले.स./ग्रा.का.वि./ए.टी.आर./18-19/869/10

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Accountant General (Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna-800 001

दिनांक/Date : 26.04.2018

सेवा में,

सरकार के उप सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः- कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंगः- आपका ज्ञापांक- 10/अ0प्र0-1-14/16-2790, दिनांक- 09.03.2018.

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि आपके द्वारा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 533 में समिति के द्वारा वर्ष 2008-09 की कंडिका संख्या-1.2.8.4 एवं 1.2.9.1 पर की गई अनुशंसाओं के आलोक में प्रेषित कार्यान्वयन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई है एवं सम्परीक्षण टिप्पणी अंकित की गई है।

कार्यान्वयन प्रतिवेदन पर अंकित संपरीक्षण टिप्पणी संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

26.04.18

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
लोक लेखा समिति अनुभाग।

अवर सचिव ग्रामीण कार्य विभाग पत्र प्राप्ति 8 MAY 2018 2049 बिहार पटना

15.5.18

286/504
16.5.18

-49-

ANNEXURE

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या	विभाग का नाम	कंडिका संख्या	प्रतिवेदन वर्ष	सम्परीक्षण टिप्पणीयाँ
533	ग्रामीण कार्य विभाग	1.2.8.4	2008-09 (सिविल)	ज्ञापांक 2790 दिनांक 09.03.2018 बेगीपट्टी, रोसड़ा एवं हिलसा प्रमंडलों के संबंध में वसूली का साक्ष्य उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही, मधुबनी, ढ़ाका, समस्तीपुर एवं बिहार शरीफ प्रमंडलों का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। उसके बाद ही इस कंडिका के निरस्तीकरण के संबंध में कोई टिप्पणी किया जा पाना संभव होगा।
533	ग्रामीण कार्य विभाग	1.2.9.1	2008-09 (सिविल)	ज्ञापांक 2790 दिनांक 09.03.2018 (क) लोक लेखा समिति में दिए गए निर्देश के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जा चुका है। अतः कंडिका अंतिम रूप से निरस्त की जा सकती है। ज्ञापांक 2790 दिनांक 09.03.2018 (ख) लोक लेखा समिति में दिए गए निर्देश के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किया जा चुका है। अतः कंडिका अंतिम रूप से निरस्त की जा सकती है।

26.04.18

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
लोक लेखा समिति अनुभाग।

-50-

-51-

ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण

पत्रांकः– मु०अ०–04 (मु०) विविध–09–20/09

पटना, दिनांकः–

प्रेषक,

विनय कुमार, भा.प्र.से.
सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल।

उप सचिव-2

17 APR 2015
3082

विषयः–लोक लेखा समिति द्वारा उठाई गई आपत्तियों की पुनरावृत्ति नहीं करने के संबंध में।

प्रसंगः–लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या– 533वाँ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि लोक लेखा समिति के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल/राजस्व) वर्ष 2008–09 की आपत्ति 1.2 (1.2.1 से 1.2.12 तक) में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित सभी आपत्तियों का निष्पादन कर दिया गया है।

अंकेक्षण के क्रम में जो आपत्ति उठायी गयी थी, उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभागीय पत्रांक–538 दिनांक–04.02.2015 के द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया था।

कृपया निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका–1.2.9.1 के आलोक में पुनः निदेशित किया जाता है कि कालीकरण हेतु Prime Coat, Tack Coat, Premix & Seal Coat में से किसी भी Item का प्रावधान डी0पी0आर0 में न छूटे, इसे सुनिश्चित किया जाए। Base कार्य पूर्ण करने के साथ ही बिना विलंब किये कालीकरण कार्य विशिष्टि के अनुरूप कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्रामीण जनता को आवागमन में कठिनाई न हो एवं ग्रेड–3 क्षतिग्रस्त न हो जाए। यदि इस कार्य को करने में संवेदक द्वारा विलम्ब किया जाता हो तो उनके विरूद्ध पी0 डब्लू डी0 कोड तथा एकरारनामा की शर्तो के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–
(विनय कुमार)

SO-10

531/D.2
01.4.15

380/30
21.4.15

-31-
-58-

ज्ञापांकः– मु०अ०–04 (मु०) विविध–09–20/09-1858 पटना, दिनांकः– 16·4·15

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार)

-52-

-59-

(86)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः– मु0अ0–04 (मु0) विविध–09–20/09 - 538 पटना/दिनांकः– 4.2.15

प्रेषक,

चंचल कुमार, भा0प्र0से0
सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल।

विषयः लोक लेखा समिति द्वारा उठाए गए आपत्तियों की पुनरावृत्ति नहीं करने के संबंध में।

प्रसंग : लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या– 533वाँ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सि0) वर्ष 2008–09 की आपत्ति 1.2 (1.2.1 से 1.2.12 तक) पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित सभी आपत्तियों का निष्पादन लोक लेखा समिति द्वारा किया जा चुका है। अंकेक्षण के क्रम में जो आपत्ति उठायी गई थी उसका पुनरावृत्ति न हो इसके लिए निम्न निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए:–

1. बीड़ क्षमता (Bid Capacity) का सही–सही आकलन कर संवेदक को कार्य आवंटित की जाए।
2. एकरारनामा के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने वाले संवेदकों के चालू विपत्र से दंड स्वरूप नियमानुसार राशि की कटौती की जाए।
3. एकरारनामा के अनुसार कार्यावधि समाप्त होने के पश्चात भी यदि कार्य लंबित रहता हो, तो वैसे संवेदकों को विभाग की Debar सूची में शामिल करने, अगले निविदा में भाग लेने से वंचित करने की कार्रवाई की जाए।
4. Bitumen प्राप्त करने हेतु DO Letter, IOC अथवा HPCL को निश्चित रूप से दी जाए जिसमें संवेदक के नाम, पथ का नाम एवं निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य के लिए Bitumen की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख हो। प्राप्त Bitumen का Detail मापीपुस्त मे भी दर्ज की जाए।
5. पथ का कालीकरण (Premixing) किए जाने के समय यातायात को रोक दी जाए।

-53-

~~60~~

6. सड़क निर्माण से संबंधित सामग्री के लिए प्रपत्र M एवं N प्राप्त कर ही संवेदको के विपत्र भुगतान की कार्रवाई की जाए।
7. विपत्र से आवश्यक कटौती करते हुए राशि चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित विभाग में जमा कर दी जाए।

विश्वासभाजन

(चंचल कुमार) 4/2/15

ज्ञापांक :– मु0अ0–04 (मु0) विविध–09–20/09-538 पटना/दिनांक :– 4.2.15

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

(चंचल कुमार) 4/2/15

ज्ञापांक :– मु0अ0–04 (मु0) विविध–09–20/09-538 पटना/दिनांक :– 4.2.15

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(चंचल कुमार) 4/2/15

बिहार विधान-सभा सचिवालय

पत्र संख्या-2लो0ले0स0-33/20- /वि०स०।

प्रेषक,

भूदेव राय,
निदेशक,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- अगस्त, 2020 ई० ।

विषय:- लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) संख्या-706 में सन्निहित आँकड़ों के सम्परीक्षण के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या-506, 529 एवं 533 में सन्निहित अनुशंसाओं (ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित) के कार्यान्वयन पर समिति का प्रारूप प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) संख्या-706 को समिति द्वारा दिनांक-12.06.2020 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है ।

अत: समिति द्वारा पारित प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसमें सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण कर पत्र प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर पारित प्रतिवेदन के वापस नहीं होने पर यह समझा जायेगा कि इसमें निहित आँकड़ें सही हैं एवं प्रतिवेदन का सदन में उपस्थापन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई कर ली जायेगी ।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(भूदेव राय)
निदेशक,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

ज्ञापांक-2लो0ले0स0-33/20-585 /वि०स०, पटना, दिनांक- 07 अगस्त, 2020 ई० ।

प्रति:-प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6/8/20
(भूदेव राय)
निदेशक,
बिहार विधान-सभा, पटना ।
6.8.20

बिहार विधान-सभा सचिवालय

स्मार पत्र पत्र संख्या-2लो0ले0स0-33/20- /वि०स०।

प्रेषक,

अनुपमा प्रसाद,
अवर सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- सितम्बर, 2020 ई० ।

विषय:- लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-706 में सन्निहित आँकड़ों के सम्परीक्षण के संबंध में ।

प्रसंग:- सभा सचिवालय के पत्रांक-585, दिनांक-07.08.2020 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध करना है कि लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-706 में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण कर इसकी मूल प्रति 7 दिनों के अंदर सभा सचिवालय को वापस करने की कृपा की जाय । ताकि प्रतिवेदन उपस्थापन करने संबंधी अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(अनुपमा प्रसाद)
अवर सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

ज्ञापांक-2लो0ले0स0-33/20- 654 /वि०स०, पटना, दिनांक-22 सितम्बर, 2020 ई० ।

प्रति:-प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुपमा 21.9.20

(अनुपमा प्रसाद)
अवर सचिव,
बिहार विधान-सभा, पटना ।
21/9/20

-7-

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– 10/अ0प्र0–1–5/17 4932 भू0 19/10/2020 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

प्रवीण कुमार ठाकुर,
अभियंता प्रमुख

सेवा में,

श्री भूदेव राय,
निदेशक,
बिहार विधान सभा,
बिहार, पटना।

विषयः– लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन(कार्यान्वयन) संख्या–706 में सन्निहित ऑकड़ों के सम्परीक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 585 दिनांक 07.08.2020 के द्वारा प्रारूप प्रतिवेदन संख्या–706 में सन्निहित ऑकड़ों का सम्परीक्षण हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया था। उक्त प्रारूप प्रतिवेदन में सन्निहित ऑकड़ों का सम्परीक्षण कर लिया गया है तथा इसे अग्रेतर कार्रवाई हेतु मूल रूप में वापस की जा रही है।

कृपया इसे स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
19/X/2020
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–10/अ0प्र0–1–5/17 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–श्री ओम प्रकाश झा, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना को उनके पत्रांक 4420 दिनांक 31.08.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/X/2020
अभियंता प्रमुख

बिहार विधान सभा सचिवालय
प्राप्ति तिथि: 20.10.2020
केन्द्रीय डाक सं०: 5718